जनवरी–मार्च–2023 (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 43–45

उत्तर प्रदेश संदेश

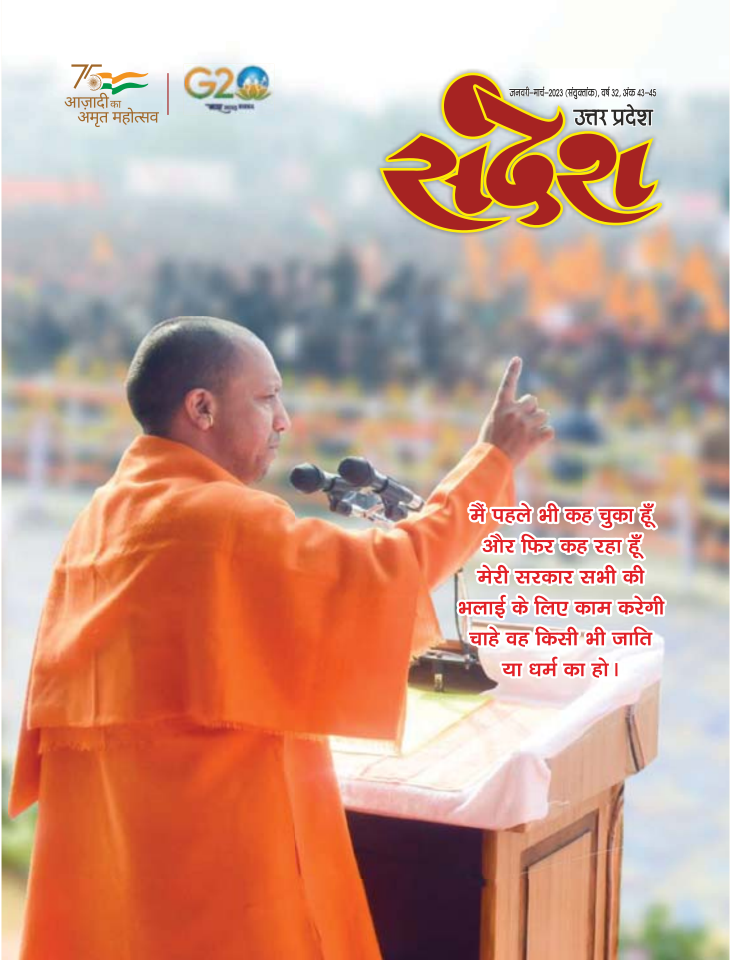

मैं पहले भी कह चुका हूँ
और फिर कह रहा हूँ
मेरी सरकार सभी की
भलाई के लिए काम करेगी
चाहे वह किसी भी जाति
या धर्म का हो।

पढ़ेंगी बेटियां-बढ़ेंगी बेटियां
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
14.86 लाख
बालिकाएं लाभान्वित
सुशासन विकास रोज़गार
डबल इंजन की सरकार
6 साल
यूपी खुशहाल

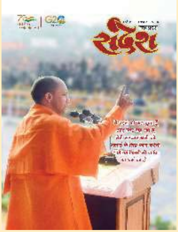

जनवरी-मार्च-2023 तक (संयुक्तांक), वर्ष 32, अंक 43-45

उत्तर प्रदेश
संदेश

संरक्षक एवं मार्गदर्शक :
संजय प्रसाद
प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी :
शिशिर
सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श :
अंशुमान राम त्रिपाठी
अपर निदेशक, सूचना

सम्पादक :
कुमकुम शर्मा
उपनिदेशक, सूचना

सम्पादकीय सहयोग :
दिनेश कुमार गुप्ता
उपसम्पादक
महेन्द्र कुमार
अपर जिला सूचना अधिकारी

सम्पादकीय संपर्क : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर, पार्क रोड, लखनऊ
ईमेल : upsandesh20@gmail.com
दूरभाष कार्यालय : ई.पी.ए.बी.एक्स 0522–2239132–33, 2236198, 2239011

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित
भारत सरकार के रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स की रजिस्ट्री संख्या : 55884 / 91

प्रकाशित सामग्री में विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोण एवं विचार से सूचना विभाग की सहमति अनिवार्य नहीं हैं। लेखों में प्रयुक्त आंकड़े अनन्तिम हो सकते हैं।

इस अंक में

योगी सरकार के 6 साल अहर्निश विकास यात्रा	-प्रद्युम्न तिवारी	3
यू.पी. बना निवेश गंतव्य	-वीरेन्द्र सिंह	8
वैश्विक निवेशक सम्मेलन	-प्रदीप उपाध्याय	12
वैश्विक सम्मेलन ने दी यूपी के विकास-विस्तार...	-सियाराम पांडेय 'शांत'	16
जी-20 की मेज़बानी ने बढ़ाया भारत का मान	-वीरेन्द्र सिंह	20
जी-20 मेज़बानी से मज़बूत होता उत्तर प्रदेश	-अखंड प्रताप शाही	23
यूपी बनेगा ग्लोबल टेक्सटाइल हब	-पी. कश्यप	26
उत्तर प्रदेश का बजट सबके विकास को समर्पित	-योगीन्द्र द्विवेदी	29
बजट में दिखी आत्मनिर्भर बनने की इच्छाशक्ति	-राघवेन्द्र प्रताप सिंह	32
भारत के प्रगति रथ का सबसे मज़बूत पहिया...	-सरिता त्रिपाठी	37
मेट्रो बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर	-सुरेन्द्र अग्निहोत्री	44
बढ़ती नगरीय सुविधाएं, सँवरते शहर	-आशीष कुमार मौर्य	48
योगी सरकार के लिए किसान आम नहीं खास	-विमल किशोर पाठक	51
यूपी में कृषि उत्पादों का होगा भरपूर उपयोग	-राजीव गोयल	53
युवाओं और रोज़गार पर पूरा फोकस	-जितेन्द्र शुक्ला	56
उ.प्र. का सलखन फॉसिस जीवाश्म पार्क भू-वैज्ञानिकों...	-केवल राम	60
बेसिक शिक्षा में नवाचारों को प्रोत्साहन	-अंजु अग्निहोत्री	62
खेलेगा यूपी, तेजी से आगे बढ़ेगा यूपी	-राजीव ओझा	66
उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति का विकास	-रजनीश वैश्य	74
अब खेल और खिलाड़ियों के लिए पहचाना...	-सरिता त्रिपाठी	78
सशक्त होती नारी समृद्ध होता समाज	-मुकुल मिश्र	81
महिलाओं के सतत् विकास के लिए प्रयत्नशील सरकार	-द्वारिका नाथ पाण्डेय	85
पूरी दुनिया को सेहत का तोहफा देगा भारत	-डॉ. शिव राम पाण्डेय	88
पर्यटन से लगेंगे यूपी के विकास को पंख	-अमित नारायण भार्गव	93
बेहतर स्वास्थ्य का सपना साकार	-सुयश मिश्रा	96
आस्था के सम्मान की परम्परा	-ए.एम. सिंह	99
वैश्विक सांस्कृतिक विरासत में अतुलनीय है	-प्रेमशंकर अवस्थी	102
सब जग होरी, ब्रज में होरा	-डॉ. अतुल कुमार सिंह	110

सम्पादकीय

सुशासन, सुरक्षा से समन्वित विकास और समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मान देने का जो सिलसिला 19 मार्च, 2017 को शुरू हुआ वह फिर आज तक कम नहीं हुआ बल्कि दोगुनी रफ्तार से बढ़ता ही रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस सकारात्मक रुख़ को अपनाते हुये काम करना आरम्भ किया उसकी बानगी हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रत्येक निर्णय में देखने को मिलती है फिर चाहे वह कानून व्यवस्था की स्थिति हो या महिलाओं, किसानों और हर तबके की खुशहाली अथवा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निवेश आमन्त्रित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने का कार्य हो, हर दिशा में योगी सरकार का विगत एक वर्ष का कार्यकाल साफ नीयत, दृढ़ संकल्प और सुशासन की कहानी कहता नज़र आ रहा है। सख़्त कानून व्यवस्था के चलते जो शान्तिपूर्ण वातावरण प्रदेश में सृजित हुआ है, यह एक दिन का काम नहीं है, बल्कि पांच वर्षों से अपराधियों, समाज विरोधी तत्वों और माफियाओं के विरुद्ध चलाई गई सतत कार्यवाही का प्रतिफल है। योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं का दमन करने के साथ ही नशीले मादक द्रव्यों का व्यापार करने वाले समाज विरोधी तत्वों पर भी निरन्तर सख़्त कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के चलते एक नई कार्यशैली सभी विभागों में दिखाई दे रही है जिसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही है।

सामाजिक सुरक्षा के बाद आम जनता को बेहतर सड़क, 24 घण्टे बिजली, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल की आवश्यकता होती है। वर्तमान सरकार में आम जन की स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्येक आवश्यकता को देखते हुए हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। इन मेडिकल कॉलेज में आमजन के सहयोग के लिए पर्याप्त स्टॉफ की भी व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सत्ता सम्भालते ही विद्युत वितरण में पक्षपात पूर्ण रवैये को खत्म करके एक समान विद्युत वितरण सुनिश्चित कराकर प्रदेश के हर तबके, हर मजरे, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। लोगों को फ्री कनेक्शन दिये गये ताकि गांव के बच्चे भी लालटेन में नहीं बिजली की रोशनी में पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने सबसे पहले प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के चरणबद्ध तरीके से प्रयास प्रारम्भ किये जिनके सुखद परिणाम हमें अब देखने हो मिल रहे हैं। आज महिलाएं मात्र शिक्षित ही नहीं सशक्त भी हो रही हैं। समाज में सकारात्मक वातावरण के चलते स्त्रियां अपने को और अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं।

पिछले दिनों आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन का असर स्पष्ट दिखाई दिया। दुनिया के तमाम उद्योगपति पूंजी निवेश के लिए यू.पी. की तरफ आकर्षित हुये हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करते हुये कहा, कि 'देश का हर नागरिक विकास के पथ पर चलना चाहता है, और एक विकसित भारत' देखना चाहता है। इस अंक में हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रद्युम्न तिवारी, वीरेन्द्र सिंह, रजनीश, वैश्य, प्रदीप उपाध्याय, रजनीकान्त वशिष्ठ, प्रेमशंकर अवस्थी आदि के लेखों को सम्मिलित किया है। हमारे अंक आपको कैसे लग रहे हैं। प्रतिक्रियाओं से अवश्य अवगत कराते रहिये।

सम्पादक

योगी सरकार के 6 साल

अहर्निश विकास यात्रा

–प्रद्युम्न तिवारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 25 मार्च को छह वर्ष पूरे हो गये। इस दौरान योगी जी ने कीर्तिमानों का गुलदस्ता भी सजाया है। योगी 2.0 का पहला वर्ष पूरा होते ही योगी के नाम 6 साल 6 दिन के मुख्यमंत्री होने का एक रिकार्ड कायम होगा, तो दूसरा कीर्तिमान अहर्निश विकास यात्रा का होगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन छह सालों में भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तर प्रदेश आज विकास के चहुँमुखी आयाम को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफार्म, परफार्म, ट्रांसफार्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश छह वर्षों में हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यूपी यदि भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि, दृढ़–संकल्प और अथक परिश्रम ही है। योगी सरकार के 2017 से शुरू हुए कार्यकाल में जिस नेक–नीयत से जन–आंकाक्षाओं की पूर्ति की गयी, उसी का परिणाम रहा कि वर्ष 2022 में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे यह भी प्रमाणित हो गया कि सरकार 'सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास–सबका प्रयास के लक्ष्य को अपनाकर सभी वर्गों की उन्नति कल्याण एवं सर्वांगीण विकास की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते पांच वर्षों में सुशासन, सुरक्षा, अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के साथ राज्य को अराजकता से उबारकर शांति और सद्भाव का जो वातावरण सुनिश्चित किया, वह अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूर्ण होने पर और पुख़्ता हुआ है। यह इसी से समझा जा सकता है कि जिस उत्तर प्रदेश में आने से उद्यमी डरते थे और जो यूपी से पलायन कर रहे थे, वे आज यहां अपने को सुरक्षित मानकर भरपूर निवेश कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही देश को पांच ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने का आधार भी बनेगा।

प्रदेश सरकार का फोकस शुरू से ही कानून–व्यवस्था, खेती–किसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, युवा रोजगार, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ औद्योगिक नेटवर्क खड़ा करने पर है। योगी सरकार–02 के पहले वर्ष में ही इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियां बनायी गयीं। साथ ही अनेक नीतियों में संशोधन कर उन्हें उदार बनाया गया। इसका परिणाम यह रहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। इस निवेश महाकुम्भ में लगभग 35 लाख करोड़ रु. के 19000 से अधिक एम.ओ.यू.

साइन हुए। राज्य के चौतरफा विकास की योगी सरकार की अवधारणा को इसी से समझा जा सकता है कि वर्ष 2023–24 के लिए 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रु. का बजट पास कराया गया है। विगत 06 वर्षों में प्रदेश के बजट का आकार दोगुना से अधिक बढ़ा है। अमृतकाल का प्रथम और अब तक का सबसे बड़ा यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं जी.डी.पी. में दोगुनी प्रगति और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को बखूबी दर्शाता है।

राज्य सरकार गरीब कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास पर फोकस कर रही है। उसने लोक कल्याण संकल्प पत्र–2022 के कुल 130 संकल्पों में से 2022–23 के बजट में 97 संकल्पों का समावेश किया था। वर्ष 2023–24 के बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के 13 अतिरिक्त संकल्प समाहित किये गये हैं। इस तरह कुल 110 संकल्प–पत्र की घोषणाओं के लिए 64687 की धनराशि का प्रावधान किया गया। इनके जरिये लोक कल्याण संकल्प पत्र के 110 वादों को धरातल पर उतारा जायेगा।

कोविड महामारी के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा। इसके बाद रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध का भी प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इस मंदी के दौर में भी देश का आर्थिक संतुलन बना रहा। प्रदेश की अनुशासित जनता और सरकार के अथक प्रयास से न केवल कोविड–19 जैसी विभीषिका को हराया जा सका, बल्कि प्रदेश की आर्थिक विकास की दर को मंदी के बावजूद अतिशीघ्र वापस पटरी पर लाने में सफलता भी मिली। हर्ष है कि वर्ष 2021–22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो देश की विकास दर से अधिक रही। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 17.07 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो पूर्णता की ओर है। अब वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जी.एस.डी.पी. में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 03 प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सरकार का कुशल वित्तीय प्रबन्धन को इसी से समझा जा सकता है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट में राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा 4 फीसदी की तुलना में 3.96 प्रतिशत रखने में सफलता मिली।

जनसमान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून–व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं

त्वरित सर्वसमावेशी विकास

राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक बजट में एक थीम को लेकर योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किया। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017-18 में अपना पहला बजट किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास तथ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के लिए था। वर्ष 2019-20 का बजट महिला सशक्तीकरण के लिए समर्पित था। वर्ष 2020-21 का बजट युवाओं तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समर्पित था। वर्ष 2021-22 के बजट का केन्द्र बिन्दु राज्य के विभिन्न वर्गों का 'स्वावलम्बन से सशक्तीकरण' का था। वर्ष 2022-23 का बजट 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' एवं 'अंत्योदय' की संकल्पना की सिद्धि' को समर्पित था। वर्ष 2023-24 के बजट का केन्द्र बिन्दु 'त्वरित समावेशी विकास' है। राज्य सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अब उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

सुदृढ़ करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा। सरकार ने पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153728 अभ्यार्थियों की नियुक्ति करके पुलिस बल को मजबूती दी। इसी से महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियन्त्रित करने में सफलता भी मिली है। कारगर पुलिस व्यवस्था एवं निरन्तर पर्यवेक्षण के कारण प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने अपराधियों, नशे के सौदागरों और भू-माफियाओं को भू-लुंठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर 04 स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश में अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत 70 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 847 अतिक्रमणकर्ताओं के भू-माफिया के रूप में चिह्नित किया गया है तथा वर्तमान में 196 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं। साथ ही 90 अरब 22 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां ज़ब्त की गयीं।

प्रदेश में सुरक्षा और शान्ति का माहौल कायम करने के साथ ही योगी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर फोकस किया। सरकार के आर्थिक विकास के एजेण्डे में प्रदेश में अवस्थापना संरचनाओं के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में सरकार ने जिस तेजी से कदम बढ़ाये, उसका नतीजा यह रहा कि प्रदेश में 5 एक्सप्रेस-वे क्रियाशील हैं, जबकि 6 निर्माणाधीन हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सड़कों कि कनेक्टिविटी बेहतर होने से आवागमन सुगम होने के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों ने भी जोर पकड़ा।

प्रदेश सरकार ने युवाओं का भविष्य संवारने और प्रदेश से उनका पलायन रोकने के लिए रोजगार पर भी फोकस किया। इन छह सालों मे साढ़े पांच लाख सरकारी नौकरियां दी गयीं। इसके अलावा रोजगार के लाखों अवसर सृजित कर लोगों को आमदनी का जरिया उपलब्ध कराया गया। अब रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश में बनाये जा रहे एक्सप्रेसवेज के किनारे औद्योगिक गलियारे बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ-साथ औद्योगिक विकास का दायरा और बढ़ेगा। वित्तीय 2023-2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल दिशा-निर्देशन में लखनऊ में 10 से 12 फरवरी, 2023 तक यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन हुआ। निवेश प्रोत्साहन के लिए स्वयं मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने प्रभावशाली रोड शो किये।

नीदरलैण्ड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुये। दुनिया के अनेक देशों के साथ–साथ भारत के निवेशकों और उद्यमियों की सहभागिता ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को निवेश महाकुम्भ का स्वरूप प्रदान किया। इसमें लगभग 35 लाख करोड़ रु. के 19000 से अधिक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए। इनमें से अधिकतर एम.ओ.यू नवीकरणीय ऊर्जा (16 फीसद), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 फीसद), औद्योगिक पार्क (11 फीसद), शिक्षा (9 फीसद) तथा लॉजिस्टिक्स (9 फीसद) सेक्टर्स में किये गये। ऐसा इसलिए सम्भव हुआ, क्योंकि राज्य सरकार ने इन सेक्टर्स के लिए नयी नीतियां तो बनायीं ही, विद्यमान नीतियों में सुधार भी किये।

उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ कि निवेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। अकेले पूर्वांचल क्षेत्र में 09 लाख 54 हजार 492 करोड़ रु. तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 04 लाख 27 हजार 873 करोड़ रु. का निवेश होगा। इससे राज्य में 93 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा मिलेगी। सरकार की सकारात्मक नीतियों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश वैश्विक मंच पर भारत में सबसे आकर्षक निवेश गन्तव्य के रूप में उभरा है। आज उत्तर प्रदेश ईज आफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर स्टेट बन गया है। सरकार ने निवेशकों के रुझान के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेन्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स, डिफेन्स एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, टेक्सटाइल, एम.एस.एम.ई सहित विभिन्न सेक्टर्स को प्रोत्साहन देने के लिए 25 नीतियां लागू कीं। इनके माध्यम से प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है।

राज्य सरकार गरीब कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास पर फोकस कर रही है। उसने लोक कल्याण संकल्प पत्र–2022 के कुल 130 संकल्पों में से 2022–23 के बजट में 97 संकल्पों का समावेश किया था। वर्ष 2023–24 के बजट में लोक कल्याण संकल्प पत्र के 13 अतिरिक्त संकल्प समाहित किये गये हैं। इस तरह कुल 110 संकल्प पत्र की घोषणाओं के लिए 64687 की धनराशि का प्रावधान किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 के बीच विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 के अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए यह गर्व का विषय है कि यहां के 04 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा को भी जी–20 की 11 बैठकों के आयोजन का उत्तरदायित्व मिला है। इस कड़ी में आगरा और लखनऊ में ग्रुप की बैठकों का आयोजन सफलतापूर्वक कराया जा चुका है।

किसी भी राज्य के लिए अन्न उत्पादन ख़ास मायने रखता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी गांवों में ही निवास करती है। इनके जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत कृषि एवं कृषि आधारित व्यवसाय है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 26 प्रतिशत है। प्रदेश की खुशहाली एवं स्थायी विकास कृषि पर निर्भर करता है, इसीलिए योगी सरकार के हर बजट में खेती और किसानी को प्रमुखता दी गयी। किसानों की तकनीकी ज्ञान एवं रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए इस बार कृषि शिक्षा के बजट में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। जनपद कुशीनगर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु. 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसानों की आय दोगुनी करने के भी अनेक उपाय किये गये है। नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में प्रदेश के 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने मिलेट्स पुररुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बजट में 55 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी साथ ही दलहन/तिलहन के उत्पादन में वृद्धि एवं इससे होने वाली आय में वृद्धि के लिए 30 करोड़ रुपये के दो नये प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। इसमें किसानों को मिनीकिट के रूप में निःशुल्क बीज वितरित किये जायेंगे। खाद्यान्न/दलहन/तिलहन बीज की लागत एवं उसमें अन्य प्रासंगिक व्यय हेतु वर्ष 2022–23 में 310.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 15,000 कृषकों को लाभान्वित करने के लिए 15,000 सोलर पम्पों का आवंटन करते हुए दिसम्बर, 2022 तक 6140 कृषक प्रक्षेत्रों में सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2023–2024 में 30,000 सोलर पम्प की स्थापना की जायेगी। निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 420 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था करते हुए 1920 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2022–23 में नवम्बर माह तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपये का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया।

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति–2022 के लिए 2500 करोड़ रुपये तथा नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 61 करोड़ 21 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे नये दुग्ध समूह प्रोत्साहित होंगे और दुग्ध उत्पादन के साथ ही उचित विपणन भी होगा। प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ■

मो. : 6388632034

यूपी बना निवेश गंतव्य

33 लाख, 50 हजार करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव

19058 एमओयू साइन

93 लाख, 82 हजार, 607 रोजगार सृजन

—वीरेंद्र सिंह

उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन का असर दिखाई दिया। दुनिया के तमाम उद्योगपति यूपी में पूंजी निवेश के लिए आकर्षित हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सुशासन से प्रभावित उद्यमियों और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अपनी रुचि दिखाई। प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ता दिखाई दिया। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया। कहा कि देश का हर नागरिक विकास के पथ पर चलना चाहता है और एक 'विकसित भारत' देखना चाहता है।

आज, भारत मजबूरी से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से सुधार कर रहा है। एक चैंपियन जब एक नए मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने की बात आती है। डबल इंजन सरकार का संकल्प, और उत्तर प्रदेश की संभावनाएं, इससे बेहतर साझेदारी नहीं हो सकती है।

उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में उद्योग जगत के लीडर्स ने इस अवसर पर बात की। श्री कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि भारत उल्लेखनीय उद्यमशीलता की गतिशीलता और नवाचार दिखा रहा है और उन्होंने देश के आर्थिक परिदृश्य में नई ऊर्जा का संचार करने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया। श्री मुकेश अंबानी ने कहा कि इस वर्ष के बजट ने भारत के एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की नींव रखी है। उन्होंने

कहा कि कैपेक्स व्यय के लिए अधिक आवंटन से अधिक आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में काफी बदलाव आया है और प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और निष्पादन पर तेज फोकस के मार्गदर्शन में एक साहसिक नया भारत आकार ले रहा है। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा संस के चेयरमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने ऐसी स्थिति पैदा की है जहां भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ''यह केवल आर्थिक विकास नहीं है, प्रधान मंत्री ने जो सक्षम किया है वह 360–डिग्री विकास है।'' उन्होंने कहा कि बजट में आवंटन बुनियादी ढांचे और खपत के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करेगा और साथ ही हम ग्रामीण विकास देखेंगे। ज्यूरिख एयरपोर्ट एशिया के सीईओ डेनियल बिर्चर ने कहा कि जिस तरह भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, उसी तरह ज्यूरिख एयरपोर्ट भी अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने भारत के साथ लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का उल्लेख किया जहां ज्यूरिख हवाई अड्डे ने दो दशक पहले बेंगलुरु हवाई अड्डे के विकास का समर्थन किया था और वर्तमान में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय

> **आज, भारत मजबूरी से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से सुधार कर रहा है। एक चैंपियन जब एक नए मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने की बात आती है। डबल इंजन सरकार का संकल्प, और उत्तर प्रदेश की संभावनाएं, इससे बेहतर साझेदारी नहीं हो सकती है।**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, 'उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है। गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे स्थित राज्य को असीमित अवसरों का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी सरकार की निवेशक हितैषी नीतिगत दिशा और सुशासन पहल, राज्य की अंतर्निहित शक्तियों के पूरक हैं, निश्चित रूप से राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य में बदलने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

हवाई अड्डे का विकास कर रहा है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस–वे के साथ नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सीधी कनेक्टिविटी को रेखांकित किया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष श्री सुनील वचानी ने कहा कि भारत में बेचे जाने वाले लगभग 65% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में निर्मित होते हैं और इसे विनिर्माण केंद्र बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार की गतिशील नीतियों को श्रेय दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगभग 100 अरब डॉलर मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात करने पर विचार कर रही है। सभी उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में उभर रहे अवसरों के प्रति उम्मीद दिखाई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, 'उत्तर प्रदेश भारत का विकास इंजन है, और देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है। गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे स्थित राज्य को असीमित अवसरों का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरी सरकार की निवेशक हितैषी नीतिगत दिशा और सुशासन पहल, राज्य की अंतर्निहित शक्तियों के पूरक हैं, निश्चित रूप से राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य में बदलने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे।

'इस निवेशक शिखर सम्मेलन के माध्यम से, हम इस प्रयास में हमारे साथ सहयोग करने के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमाग और विशेषज्ञता के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। मैं सभी हितधारकों को उत्तर प्रदेश में निवेश की सुविधा और ज़मीनी स्तर पर पूर्ण समर्थन का आश्वासन देता हूं।'

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया।तीन दिन तक चले समिट में कुल 33 लाख, 50 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19058 एमओयू साइन हुए। इससे करीब 93 लाख, 82 हजार, 607 लोगों को रोजगार मिलेगा। तीन दिवसीय यूपी जीआईएस–2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।

राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये 'निवेश सारथी' नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी इस समिट में

शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एशोसिएशन ने बाराबंकी में 30 हजार की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिये प्रदेश सरकार के साथ एमओयू किया है।

यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्रों में 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग–अलग जिलों में अस्पताल खोलने का एलान किया है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिये 29,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिये दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिये इस मंच पर बुलाया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की भागीदारी देखी गई।

दिसंबर 2022 में यूपीजीआईएस 2023 के लिये राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किये थे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके।

इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्था 'साझेदार देश' रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इसमें 28 हजार करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर एमओयू साइन किये गए थे।

12 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (यूपी जीआईएस–2023) का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ। ■

मो. : 9410704385

वैश्विक निवेशक सम्मेलन

तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश

–प्रदीप उपाध्याय

तीन दिनों तक चला निवेशकों का महाकुंभ उत्तर प्रदेश के विकास की नयी कहानी लिखेगा गत 10, 11 और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 का लखनऊ के वृन्दावन योजना में आयोजन किया गया। इसमें युनाइटेड किंग्डम, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, मारीशस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और इटली सरीखे सहभागी देशों के चार सौ से अधिक प्रतिनिधियों और लगभग एक हजार डेलीगेट्स ने भाग लिया। इस तीन दिवसीय आयोजन का शुभारंभ जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन समारोह को संबोधित किया। देश के शीर्षस्थ उद्योगपतियों ने इस मौके पर राज्य में निवेश की घोषणा की। निवेशक सम्मेलन में रिकार्ड 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये। पिछले साल जनवरी माह में कर्नाटक ने बड़े स्तर पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन बेंगलूरू में किया था, जिसमें लगभग 25 हजार करोड़ के निवेश करार हुए थे। फरवरी माह में मध्य प्रदेश सरकार ने इन्दौर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 17.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आये। जबकि पिछले साल राजस्थान में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान ग्यारह लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अब आन्ध्र प्रदेश का निवेशक सम्मेलन विशाखापत्तनम और पंजाब का वैश्विक निवेशक सम्मेलन मोहाली में होने जा रहा है। बुनियादी ढांचागत विकास, आर्थिक और औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने के लिए देश में पहली बार गुजरात में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की नीव डाली गयी थी। अब यह एक चिर परिचित परिपाटी बन चुका है। अनेक राज्य अपने स्तर पर इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं।

तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यू.पी. को वेल्थ क्रिएटर बताते हुए निवेशकों से कहा कि एक ओर डबल इंजन सरकार का मजबूत इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर साझेदारी हो ही नहीं सकती। यह समय गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य कहलाता था लेकिन बीते 5–6 वर्षों में यू.पी. ने अपनी नयी पहचान स्थापित कर ली है। यू.पी. देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। यू.पी. की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। श्री मोदी ने कहा कि सोशल, डिजिटल

और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है।

समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते आज दुनिया के तमाम देशों के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यूपी भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने में सक्षम भी है और तैयार भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश अगर समृद्ध हुआ तो देश भी समृद्धि की ओर जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में ख्याति मिलेगी। गौरतलब है कि यूपी ने वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। इस दिशा में निवेशक सम्मेलन को लम्बी छलांग माना जा सकता है।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश निवेश का सुरक्षित गंतव्य होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में अब तक आ चुका और आने वाला निवेश प्रदेश के विकास में सहायक तो होगा ही, स्वयं निवेशकों के लिए भी फलदायी होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले निवेश का मतलब सिर्फ एनसीआर अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता था, मगर अब सभी 75 जिलों में निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 33.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव से राज्य में 93 लाख नौकरियों तथा रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कमजोर समझे जाने वाले पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में भी भारी निवेश आया है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पारदर्शी नीतियों और तकनीक को अपनाकर निवेश के चार स्तंभों पर

समारोह के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते आज दुनिया के तमाम देशों के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि यूपी भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने में सक्षम भी है और तैयार भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर प्रदेश अगर समृद्ध हुआ तो देश भी समृद्धि की ओर जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में ख्याति मिलेगी। गौरतलब है कि यूपी ने वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। इस दिशा में निवेशक सम्मेलन को लम्बी छलांग माना जा सकता है।

काम किया। एम ओ यू से लेकर निवेश को धरातल पर उतारने के लिए निवेश सारथी, निवेश, मित्र, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र और इंसेटिव मानीटरिंग जैसे सिंगल विंडो सिस्टम बनाये गये और इनका कुशलतापूर्वक संचालन किया गया।

कुल 35 लाख 50 हजार करोड़ के 19,058 निवेश प्रस्तावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 45 प्रतिशत का निवेश हुआ है। यहाँ 14 लाख 81 हजार 108 करोड़ के 8,839 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूर्वांचल के लिए 9 लाख 54 हजार 492 करोड़ के 5,406 निवेश प्रस्ताव मिले, जो कुल निवेश का 29 प्रतिशत था। मध्य उत्तर प्रदेश के लिए 4 लाख 27 हजार 876 करोड़ रुपये के 4,424 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह कुल निवेश का 13 फीसदी रहा। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 4 लाख 27 हजार 873 करोड़ के 424 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो कुल निवेश का 13 प्रतिशत रहा। लखनऊ, वाराणसी और एनसीआर क्षेत्र में तो निवेश हुआ ही है, प्रदेश के अनेक जिलों में निवेश की नयी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। अब एम.ओ. यू. की सूख्या 18, 643 से बढ़कर 19058 हो गयी हैं। इस प्रकार कुल निवेश प्रस्ताव के अमल में आने पर 23 लाख 82 हजार 607 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 144 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में 4 लाख 47 हजार 310 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं; जिनसे 1 लाख 11 हजार 374 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 151 प्रस्ताव आये हैं। इस क्षेत्र में 3 लाख 58 हजार 798 करोड़ का निवेश होगा जिससे 1 लाख 67 हजार 788 लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक पार्क के लिए 2020 प्रस्ताव मिले हैं। इस सेक्टर में 3 लाख 28 हजार 076 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 11 लाख 98 हजार 349 लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख 57 हजार 922 करोड़ के 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 7 लाख 82 हजार 528 लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 7,711 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में 1 लाख 97 हजार 955 करोड़ का निवेश होना है, जिससे 15 लाख 49 हजार 168 लोगों को नये सिरे से रोजगार मिलेगा। जबकि लाजिस्टिक वेयर हाउस के 249 प्रस्ताव मिले हैं। इस सेक्टर में 15 हजार 967 करोड़ का निवेश होगा और 1 लाख 95 हजार 294 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। रियलस्टेट के क्षेत्र में 492 प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र में 1 लाख 24 हजार 964 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 8 लाख 86 हजार 799 लोगों को नये सिरे से रोजगार मिल सकेगा।

आईटी सर्विस के क्षेत्र में 92 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस सेक्टर में 1 लाख 12 हजार 862 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे 1 लाख 98 हजार 526 लोगों को रोजगार मिल सकेगी। पर्यटन के क्षेत्र में 327 प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र में 98 हजार 193 करोड़ का निवेश होना है। इससे 2 लाख 60 हजार 40 लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में 1092 प्रस्ताव मिले। इस सेक्टर में 54 हजार 710 करोड़ का निवेश होगा। इससे 2 लाख 46 हजार 808 लोगों को रोजगार मिलेगा। पावर जेनरेशन के क्षेत्र में 6 प्रस्ताव मिले हैं। यहाँ 53 हजार 495 करोड़ का निवेश होगा और 12 हजार 850 लोगों को रोजगार मिलेगा।

हाउसिंग के क्षेत्र में 384 प्रस्ताव मिले। इस सेक्टर में 67 हजार 562 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 2 लाख 2 हजार 841 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में 72 प्रस्ताव मिले हैं। यहाँ 47 हजार 72 करोड़ का निवेश होगा जिससे 1 लाख 46 हजार 984 लोगों को रोजगार मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 970 प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र में 37 हजार 359 करोड़ का निवेश होगा और 2 लाख 9 हजार 851 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। डेयरी उद्योग के 1028 प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 30 हजार 593 करोड़ का निवेश होगा और 71 हजार 384 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

खाद्य एवं रसद के 73 प्रस्ताव मिले हैं। इस क्षेत्र में 29 हजार 852 करोड़ का निवेश होगा और 4,275 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए, इनमें 25 हजार 822 करोड़ का निवेश होगा तथा 6050 लोगों को रोजगार मिलेगा। होटल के क्षेत्र में 437 प्रस्ताव मिले हैं। इस सेक्टर में 20 हजार 722 करोड़ का निवेश होगा और 99 हजार 608 लोगों को रोजगार मिलेगा। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में 44 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस क्षेत्र में 20 हजार 452 करोड़ का निवेश होगा और 19 हजार 962 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जबकि बायोमास के क्षेत्र में 174 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस सेक्टर में 20 हजार 360 करोड़ का निवेश होगा और 1 लाख 33 हजार 770 लोगों को रोजगार मिलेगा।

गौरतलब है कि कैपिस समूह नोएडा में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगायेगा। इसमें तकरीबन एक लाख करोड़ का निवेश होगा और लगभग तीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। रिलायंस कम्पनी एमआरओ, टेलीकाम और इन्फ्रास्ट्रक्चर में पांच हजार करोड़ का निवेश करेगी। जबकि आदित्य बिड़ला समूह 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के विजन 'रिफार्म–परफार्म–ट्रांसफार्म' को आत्मसात किया गया है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून–व्यवस्था के साथ ही विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। अब उत्तर प्रदेश इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 के दौरान 34 सेक्टोरल सेशन हुए, जिनमें विभिन्न देशों के पच्चीस हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। ग्लोबल ट्रेड शो के दौरान 525 प्रदर्शनियां आयोजित की गयीं। इस दौरान पांच सौ से अधिक बी 2 जी तथा 1100 से अधिक बी–बी बैठकें हुईं। सोलह देशों के 21 शहरों में रोड शो आयोजित किए गए। देश के नौ राज्यों में रोड शो के आयोजन के साथ ही प्रदेश के 75 जिलों में विभागीय और सेक्टोरल रोड शो भी आयोजित हुए।

यूं तो निवेश प्रस्तावों के मामले में गौतम बुद्धनगर, लखनऊ और वाराणसी को प्राथमिकता दी गयी है लेकिन सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर और बलरामपुर सरीखे आकांक्षात्मक जिलों में 1.59 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है। सिद्धार्थनगर के लिए 650 करोड़ के 128 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 4,895 लोगों को रोजगार मिलेगा। बहराइच में 4,451 करोड़ रुपये के 160 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 82 हजार 912 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। सोनभद्र में 74 हजार 201 करोड़ के 67 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनमें 10.753 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रावस्ती में 1525 करोड़ रुपये के 90 निवेश प्रस्ताव मिले है जिनसे 7,773 लोगों को रोजगार मिलेगा। चित्रकूट में 63 हजार 59 करोड़ रुपये का 207 निवेश प्रस्ताव मिला है, जिससे 78 हजार 471 लोगों को रोजगार मिलेगा। चंदौली के लिए 11,891 करोड़ रुपये के 200 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 44 हजार 430 लोगों को रोजगार मिलेगा। फतेहपुर के लिए 2,391 करोड़ रुपये के 100 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनसे 3,904 लोगों को रोजगार मिलेगा। बलरामपुर के लिए 1,071 करोड़ रुपये के 142 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इससे 4.626 लोगों को रोजगार मिलेगा। ललितपुर के लिए अगर 32 हजार करोड़ का निवेश होने जा रहा है तो मऊ के लिए 119 उद्यमियों ने मूल्यवान निवेश किया है। देखा जाए तो राज्यय के सभी 75 जिलों में कहीं कम, कहीं ज्यादा निवेश के प्रस्ताव आये हैं। यह एक तरह से उद्योग और कारोबार के वे बीज हैं जिन्हें फलीभूत कराने के लिए सरकारी तंत्र के साथ–साथ प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को ज्यादा सतर्कता और मेहनत के साथ काम करना होगा। यदि ऐसा हुआ तो तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। ▪

मो. : 9695232888

वैश्विक सम्मेलन ने दी
यूपी के विकास-विस्तार को रफ्तार

–सियाराम पांडेय 'शांत'

तीन दिन में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के 34 सत्र हुए जिसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विकास और उसे देश का सर्वोत्तम देश बनाने पर मंथन ही था। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर में वशिष्ठ, भारद्वाज, व्यास, दधीचि, व्यास हाल का निर्माण और वहां का विचार कुंभ यह बताने के लिए काफी था कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के उन्नयन के साथ ही औद्योगिक विकास भी विस्तार चाहता है।

लक्ष्मी का निवास व्यापार में होता है। जो व्यक्ति, समाज, प्रदेश और देश इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता और तदनुरूप आचरण करता है, वह प्रगति के शीर्ष तक सहज ही पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष–2023 के पूर्वाद्ध में राज्य सरकार, निवेशकों और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी मंथन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तीन दिन में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के 34 सत्र हुए जिसमें एक सूत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के विकास और उसे देश का सर्वोत्तम देश बनाने पर मंथन ही था। लखनऊ के वृंदावन सेक्टर में वशिष्ठ, भारद्वाज, व्यास, दधीचि, व्यास हाल का निर्माण और वहां का विचार कुंभ यह बताने के लिए काफी था कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के उन्नयन के साथ ही औद्योगिक विकास–विस्तार भी चाहता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने इस साल एमएसएमई सेक्टर में उद्योगतियों के साथ 9 हजार एमओयू किए हैं और संभावना जताई है कि प्रदेश इससे प्रदेश में 18 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस साल हुए निवेशक सम्मेलन में 1.25 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1.37 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिसमें 10 करोड़ की सीमा वाले 6 हजार से अधिक निवेश प्रस्ताव शामिल हैं जबकि 50 करोड़ से कम निवेश वाले एमओयू की श्रेणी में कुल 1.05 लाख करोड़ के निवेश पर सहमति की मुहर लगी है।

उत्तर प्रदेश में लगभग 95 लाख लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं और बैठकों में प्रायः इस बात का उल्लेख करते रहे हैं। उनकी परिकल्पना एमएसएमई के

इस आधार को प्रदेश में और विस्तार देने की रही है और इसके लिए न केवल उन्होंने राज्य के ढांचागत विकास को मजबूत किया बल्कि यहां की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का हर संभव प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि देश–विदेश के तमाम प्रतिनिधि न केवल लखनऊ आए बल्कि उन्होंने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में भारी निवेश करने पर अपनी सहमति जताई। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद एमएसएमई का यह आधार अब और बड़ा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह इसलिए भी कि इस सेक्टर में बड़े पैमाने पर उद्यमियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। प्रदेश सरकार ने यूपीजीआईएस के जरिए जो 19 हजार से ज्यादा एमओयू किए हैं, उनमें 9 हजार से ज्यादा एमओयू सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में हुए हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में 18 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

योगी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए पहले एक लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी मंत्रिमंडल के साथियों ने न केवल भारत के बाहर के देशों में जनसंपर्क किया, बल्कि भारत के बड़े शहरों, खासकर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में भी रोड शो किया। स्थानीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला प्रशासन ने अलग–अलग जिलों में भी स्थानीय स्तर पर औद्योगिक निवेश की संभावनाएं तलाशीं और उसके नतीजे यह हैं कि पूरे प्रदेश में कल–कारखानों की स्थापना की संभावनाओं को पंख लग गये। विभिन्न देशों और प्रदेशों के साथ ही यूपी में मंडल व जिला स्तर पर हुए निवेशक सम्मेलनों के बाद यूपी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के मुख्य समारोह के समापन तक एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत कुल 1.37 लाख करोड़ रुपए के 8,829 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जाहिर है, इससे प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में एमएसएमई इकाइयां स्थापित होंगी, जिनका सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो रोजगार की तलाश में हैं। साथ ही, परोक्ष रूप से भी लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार एक ओर जहां यूपीजीआईएस के माध्यम से बड़े निवेशकों को तो प्रदेश में निवेश के लिए

आमंत्रित कर रही थी, वहीं, उसका इरादा छोटे निवेशकों और उद्यमों को भी बढ़ावा देने का था। कहना न होगा कि अपने इस ध्येय को पूरा करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता मिली है। हजारों छोटे निवेशकों ने भी लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों में निवेश के लिए एमओयू किया है। एमएसएमई के तहत सर्वाधिक 6212 एमओयू ऐसे रहे हैं जिनकी निवेश राशि 10 करोड़ रुपए से कम की है। इसके तहत 26,124 करोड़ रुपए का कुल निवेश प्रदेश में आ रहा है। वहीं, 10 से 20 करोड़ के बीच निवेश वाले 938 एमओयू हुए हैं, इसके अंतर्गत 15,341 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच के 451 एमओयू हुए और इसके तहत होने वाले निवेश की राशि भी 11,956 करोड़ है। 30 करोड़ से 40 करोड़ के बीच के 213 एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। इसमें 7,931 करोड़ रुपये का निवेश होगा। 40 से 50 करोड़ रुपये की लागत वाले निवेश की बात करें तो इस श्रेणी में 894 एमओयू हुए हैं और इसके तहत सबसे ज्यादा 43,890 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आना संभावित है। इस तरह अगर 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए कुल 8,708 एमओयू हुए हैं और इसके जरिये 105,242 करोड़ रुपए का निवेश होना प्रस्तावित है। 50 करोड़ से अधिक के निवेश के 121 एमओयू पर हस्ताक्षर भी अपने आप में बड़ी बात है। इसके तहत यूपी में 32,312 करोड़ रुपए के निवेश किया जाना है। 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच 65 एमओयू के माध्यम से प्रदेश में 5,341 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जबकि 100 से 200 करोड़ के बीच 33 एमओयू में 4,984 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर दस्तखत हुए हैं। 200 से 500 करोड़ के बीच 13 एमओयू हुए हैं जिनमें 3,391 रुपए का निवेश हो सकता है। वहीं 500 करोड़ से ऊपर के जो 10 एमओयू हुए हैं, उनके माध्यम से 18,596 करोड़ रुपए का निवेश होना तय माना जा रहा है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 10, दूसरे दिन 13 और आखिरी दिन 11 सत्र हुए। अधिकांश सत्रों में केंद्रीय मंत्रियों ने बदलते यूपी के विकास पर चर्चा की। यूपी डिजाइनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, टूरिज्म लीवरेजिंग कल्चरल हैरिटेज फॉर मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश, सस्टेनेबल डवलपमेंट : रिनीवल एनर्जी, एडवांटेज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, ओडीओपी

इम्पावरिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी फूड प्रोसेसिंग लिवरेजिंग फूड बॉस्केट ऑफ इंडिया, पर्यटन, इको सिस्टम के विकास, सड़क परिवहन के विकास, सहकारिता आधारित उद्योगों के विकास पर नीर–क्षीर विवेक के साथ मंथन हुआ। सिंगापुर पार्टनर कंट्री सेशन, डेनमार्क पार्टनर कंट्री सेशन, नीदरलैंड पार्टनर कंट्री सेशन, जापान पार्टनर कंट्री सेशन, यूएई पार्टनर कंट्री सेशन, पार्टनर कंट्री सेशन ऑस्ट्रेलिया आदि पर चिंतन मनन तो हुआ ही। योगी सरकार ने अतिथियों के सम्मान और मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा। उन्हें उत्तर प्रदेश की समर्थ साहित्य, संस्कृति की झलक तो दिखाई ही, उसे उत्तर प्रदेश का वैभव भी दिखाया। लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन निवेशकों के लिए बसाई गई औद्योगिक सिटी में तो हुआ ही, शहर के लगभग सभी प्रमुख कलाकारों द्वारा स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बधावा लोक नृत्य, राई लोकनृत्य, धोबिया लोकनृत्य, थारू लोक नृत्य, फरुवाही लोक नृत्य, ढेढ़िया लोक नृत्य और मयूर नृत्य को इसी कोट में रखा जा सकता है। बांसुरी, सितारा, तबला, सितार, वीणा, ढोलक वादन केजरिए जहां दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की गई, वहीं कई बड़े गायकों ने भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। सैकड़ों ड्रोन के जरिए शो का आयोजन कर योगी सरकार ने निवेशकों को यह बताने और जताने का भी प्रयास किया कि हम अंदर से मजबूत भी हैं और आपके सहयोग के आकांक्षी भी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को यह प्रतीति भी दिलाई कि उनका निवेश राज्य में पूरी तरह सुरक्षित है। कुल मिलाकर जिस तरह का यूपी वैश्विक निवेशक सम्मेलन इस बार हुआ, वह अपने आप में अद्भुत है। जिस तरह निवेशकों ने दिल खोलकर निवेशक प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह इस बात की बानगी है कि उत्तर प्रदेश के विकास की डगर को अवरुद्ध कर पाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है। ■

बधावा लोक नृत्य, राई लोकनृत्य, धोबिया लोकनृत्य, थारू लोक नृत्य, फरुवाही लोक नृत्य, ढेढ़िया लोक नृत्य और मयूर नृत्य को इसी कोट में रखा जा सकता है। बांसुरी, सितारा, तबला, सितार, वीणा, ढोलक वादन केजरिए जहां दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश की गई, वहीं कई बड़े गायकों ने भी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया।

मो. : 7459998968

जी–20 की मेज़बानी ने बढ़ाया भारत का मान

–वीरेन्द्र सिंह

लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय (13–15 फरवरी) जी–20 शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को शो केसिंग का मौका मिला। ग्रुप 20 के देशों ने यूपी के उत्पादों, दर्शनीय स्थलों को नज़दीक से देखा। मेहमानों की मेजबानी के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का दर्शन कराया गया। लखनवी खान–पान और तहज़ीब से उन्हें रूबरू कराया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से जी–20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सर्कुलर कार्बन इकोनॉमिक अप्रोच' पर जी–20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने स्वच्छ जलवायु के लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन से हमें अकेले नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ना चाहिए। भारत ने पर्यावरण के अनुरूप रहने की अपनी पारंपरिक नैतिकता के तहत कम कार्बन और जलवायु–अनुकूल विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे जैसे मेट्रो नेटवर्क, जल–मार्ग इत्यादि चीजें बना रहा है। ये अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे सुविधा और दक्षता के अलावा, एक स्वच्छ वातावरण में भी योगदान देंगे।

प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को आश्वस्त किया कि भारत 2022 के पहले ही 175 गीगा वाट अक्षय ऊर्जा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में किए गए प्रयासों के

जी–20 का गठन सितंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। साथ ही जी–20 ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले अहम् देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का काम भी करता है।

बारे में जानकारी देते हुए 'सिंगल यूज प्लास्टिक' को खत्म करने के अभियान को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने एलईडी लाइट्स को लोकप्रिय बनाकर बिजली को किफायती बनाया है। यह प्रतिवर्ष 3.8 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाता है।

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

जी–20 का गठन सितंबर 1999 में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। साथ ही जी–20 ब्रेटन वुड्स संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा के भीतर आने वाले अहम् देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देने का काम भी करता है।

उत्तर प्रदेश में 13 फरवरी से तीन दिवसीय जी–20 समिट बैठक की शुरुआत हुई है. जिसके तहत राजधानी लखनऊ में डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक में विभिन्न देशों के 143 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने जी–20 समिट डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी।

जी–20 समिट को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि–वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. यह वास्तव में भारत का वो प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है कि भारत के पास जो कुछ भी था उसे बिना राग द्वेष के या किसी भी अहंकार के कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा है तो इस पर मेरा ही एकाधिकार है।

सीएम योगी ने कहा कि– निश्चित ही डिजिटल इकॉनमी वसुधैव कुटुम्बकम के इस भाव के साथ पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही मानवता के जीवन में कल्याण का काम कर सकती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि– मुझे पूरा विश्वास है कि जी–20 समिट की यह बैठक कुछ नए मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ डिजिटल इकॉनमी पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके अलावा इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ।

143 देशों के प्रतिनिधि शामिल

जी20 समिट के दौरान डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक में इस दौरान विभिन्न देशों के 143 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके साथ ही जी20 समूह देशों के अलावा नौ अन्य देशों के प्रतिनिधि को भी समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

डीईडब्ल्यूजी की बैठक के दौरान साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा पर अलग–अलग समूह के साथ सत्र आयोजित होंगे। जिसमें, भारत के हुए कामों को जहां प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य की रणनीति को लेकर भी इस पर चर्चा की गई।

क्या है जी–20?

जी–20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ ट्वेंटी भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। जी–20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं।

इसलिए हुआ था गठन

शुरुआत में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। इसका पहला सम्मेलन दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार जी–20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी।

जी 20 में ये देश हैं शामिल

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

ज्ञातव्य है कि 18वां जी–20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 9–10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। यह शिखर सम्मेलन मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी जी–20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर जी–20 नेताओं की एक घोषणा को अपनाया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्रिस्तरीय और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमत प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को बताया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन से पूर्व देश के विभिन्न प्रदेशों में समिट का आयोजन किया गया, जिससे कि प्रतिनिधि सम्पूर्ण भारत को समझ सकें। ■

मो. : 9410704385

जी–20

मेज़बानी से मज़बूत होता उत्तर प्रदेश

–अखंड प्रताप शाही

दुनिया भर की 85 फीसदी जीडीपी का हिस्सा जिन 20 देशों के पास है उनके सबसे अहम संगठन जी–20 के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन बदहाली से बेहतरी की राह पर अग्रसर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य का उद्घोष जैसा है। वन अर्थ, वन फैमली, वन फ्यूचर की जिस थीम के साथ भारत को मेजबानी मिली, वह महाउपनिषद के विश्व बंधुत्व की भावना को चरितार्थ करती है। **अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।** समूचे संसार को एक कुटुम्ब के तौर पर देखने की भारतीय दृष्टि वैश्विक नेतृत्व की बागडोर संभालने का सामर्थ्य हासिल कर चुकी है। भारत के इस गौरवशाली उपलब्धि में उत्तर प्रदेश महत्वूर्ण सहयोगी भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए **उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023** का आयोजन फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया। लक्ष्य था 17 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना। लेकिन नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर रहे। GIS2023 में कुल 33.50 लाख करोड़ के एमओयू हुए, यह संख्या लक्ष्य से लगभग दोगुने की है। तीन दिनों (10 से 12 फरवरी) तक उत्तर प्रदेश के संसाधनों, सुविधाओं, संभावनाओं और सामर्थ्य को टटोलती देश दुनिया के बड़े उद्यमियों की निगाहें पिछले 6 सालों में बदले उत्तर प्रदेश की छवि से अभिभूत दिखीं।

सुदृढ़ कानून व्यवस्था, समृद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास को समर्पित आर्थिक नीति और निवेश–समर्पित सोच के साथ उत्तर प्रदेश निवेशकों का भरोसा जीतने में सफल रहा है। GIS-23 के फौरन बाद लखनऊ में 13 से 15 फरवरी के बीच जी–20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। जी–20 की प्रदेश में कुल 11 मीटिंग्स निर्धारित हैं। प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों का चयन किया गया है। इनमें राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेटर नोएडा

जिन रास्तों से प्रतिनिधिमंडल को गुजरना था उन्हें फूलों से सजाया गया था। उत्तर प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीकों की कलाकृतियों को दीवारों पर उकेरा गया था। मेहमानों को खास तौर ऐतिहासिक स्मारक इमामबाड़ा भी ले जाया गया। तो दूसरी तरफ वर्चुअल रिएलिटी एक्सपीरिएंस सेंटर की तरफ से होटल सेंट्रम में एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मेहमानों ने आर्टिफीशिएल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में समृद्ध होते भारत और उत्तर प्रदेश की बानगी भी देखी। मेहमानों की सुरक्षा के खास इंतजाम तो थे ही, संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक मेहमान का कोविड टेस्ट भी किया गया।

शामिल हैं। अलग–अलग समय पर प्रदेश के इन चार शहरों में आयोजित होने वाली बैठकों में मुद्दे भी अलग–अलग रहने वाले हैं। दरअसल भारत द्वारा जी–20 शिखर सम्मेलन के क्रम में 200 से अधिक बैठकें आयोजित होनी है। इन बैठकों में डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की बैठक एक अहम कड़ी रही, जिसमें जी–20 देशों के 143 प्रतिनिधियों सहित 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। राजधानी लखनऊ में आयोजित बैठकों में साइबर क्राइम और डिजिटल शिक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। डिजिटल लेनदेन के मामले में अकेले भारत में आज 45 फीसदी डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है। यानि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन आज भारत में होता है। जनधन योजना के तहत शुरू हुआ बैंकिंग सुविधाओं में बदलाव अब हिंदुस्तान को डिजिटली दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा कर रहा है।

पर्यटन के लिहाज से प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिली। जी–20 सम्मेलनों के मद्देनजर जन–भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। लोक कलाओं, नृत्यों और यादगार सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए समृद्ध लोक कलाओं को वैश्विक पहचान मिली। मोटे अनाज 'मिलेट्स' और स्थानीय जायके को विशेष पहचान मिली। वोकल फॉर लोकल की मुहिम के तहत ओडीओपी उत्पादों के गिफ्ट पैक से मेहमानों को सम्मानित किया गया।

खास मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी लखनऊ अपने पूरे वैभव के साथ तैयार थी। प्रमुख स्थानों और चौराहों पर जी–20 देशों के ध्वज और होर्डिंग्स को लगाया गया था।

जी–20 के सदस्य देशों में मेजबान भारत सहित अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सउदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। जबकि आमंत्रित देशों बांग्लादेश, मिश्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई के प्रतिनिधि भी राजधानी लखनऊ में मौजूद रहे। इन बैठकों में इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन, विश्व बैंक, यूनेस्को और यूएनडीपी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। दरअसल जी–20 आर्थिक लिहाज से दुनिया के सशक्त देशों का संगठन तो है ही, 75 फीसदी कारोबार और 85 फीसदी जीडीपी इन देशों से ही जुड़ी है। जबकि जनसंख्या के लिहाज से दुनिया की दो तिहाई आबादी इन्हीं देशों में निवास करती है। डिजिटल लेनदेन के मद्देनजर इन देशों ने पहली

बार 2017 में डिजिटल इकॉनमी टास्क फोर्स बनाया जो बाद में डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप के नाम से पहचाना जाने लगा।

राजधानी लखनऊ के अलावा वाराणसी में भी जी–20 देशों की बैठक आयोजित हुई। देश भर के विभिन्न शहरों में ये सिलसिला अगस्त तक चलेगा। लेकिन यूपी के नजरिए से ये बैठकें कई मायनों में अलग और दूरगामी प्रभाव वाली साबित हो रही हैं। मसलन, जी–20 सम्मेलन प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई आयोजक शहरों को बेहतर बदलाव का शानदार अवसर भी मिला। कभी बीमारू राज्य के तौर पर बदनाम रहे उत्तर प्रदेश को निर्बाध योजना और रसद आपूर्ति के मामले में एक सक्षम प्रदेश के तौर पर पहचान मिली है।

पर्यटन के लिहाज से प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिली। जी–20 सम्मेलनों के मद्देनजर जन–भागीदारी को प्राथमिकता दी गई। लोक कलाओं, नृत्यों और यादगार सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए समृद्ध लोक कलाओं को वैश्विक पहचान मिली। मोटे अनाज 'मिलेट्स' और स्थानीय जायके को विशेष पहचान मिली। वोकल फॉर लोकल की मुहिम के तहत ओडीओपी उत्पादों के गिफ्ट पैक से मेहमानों को सम्मानित किया गया। मेहमानों को मुहैया कराए गए अत्याधुनिक सुरक्षा कवच के जरिए प्रदेश के रक्षा सामर्थ्य को वैश्विक पहचान मिली। एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल, रोड और सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक मीडिया कवरेज से आयोजन के प्रत्येक पहलू को उजागर किए जाने के साथ ही ब्रांड यूपी को स्थापित किया गया। कार्यक्रम स्थलों को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही अत्याधुनिक संचार माध्यमों/उपकरणों से लैस किया गया जिसका लाभ भविष्य में भी प्रदेश को मिलता रहेगा। जी–20 के आयोजन के मद्देनजर ही ताज नगरी आगरा को मेट्रो संचालन का तोहफा भी मिला जो भविष्य में पर्यटन को आकर्षित करने के साथ ही स्थानीय यातायात का प्रभावी माध्यम बनेगा।

जी–20 डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ करते समय सीएम योगी ने मानवता के कल्याण के लिए जिस दिशा देने की जो उम्मीद जताई थी उत्तर प्रदेश के नजरिए से वो उम्मीद हकीकत में तब्दील होती दिख रही है। दुनिया के ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों की एक साथ, एक मंच पर मौजूदगी किसी भी आयोजक देश के मजबूत कद का एहसास कराती है।

जी–20 डिजिटल इकॉनमी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ करते समय सीएम योगी ने मानवता के कल्याण के लिए जिस दिशा देने की जो उम्मीद जताई थी उत्तर प्रदेश के नजरिए से वो उम्मीद हकीकत में तब्दील होती दिख रही है। दुनिया के ताकतवर देशों के प्रतिनिधियों की एक साथ, एक मंच पर मौजूदगी किसी भी आयोजक देश के मजबूत कद का एहसास कराती है। बतौर मेजबान उत्तर प्रदेश के चार शहर देश–दुनिया के सामने अपनी संपन्नता, समृद्धि और सामर्थ्य के साथ परस्पर सहयोगी भूमिका का सफल निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। ■

मो. : 8299742960

यूपी बनेगा ग्लोबल टेक्सटाइल हब

पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी नयी उड़ान

—पी. कश्यप

उत्तर प्रदेश यूं तो शुरू से ही वस्त्र उद्योग का गढ़ रहा है, लेकिन समय की मार और वर्ष 2017 के पहले की सरकारों की उदासीनता से इस उद्योग पर भी ग्रहण लगता गया। वह फिर चाहे छोटे वस्त्र उद्योग रहे हों अथवा बड़े, सभी हाशिये पर जाते रहे। पर, अपने पहले कार्यकाल से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा यूपी को वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाने की रही। इसके मद्देनजर सरकार ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाये। इसी का नतीजा है कि आज जहां बुनकर भी फलफूल रहे हैं, वहीं पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क जैसी बड़ी योजनाएं यूपी को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने में मददगार साबित हो रही हैं। प्रदेश सरकार की उदार नीतियों से निवेशकों ने भी इस सेक्टर की ओर रुख किया है। सरकार नयी टेक्सटाइल नीति भी ला चुकी है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क को सबसे बड़ा लाभ यूपी में सुदृढ़ हुई रोड, रेल, वायु और वाटर कनेक्टिविटी से मिलने वाला है। उत्तराखंड के सितारगंज और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के नजदीक स्थित मेगा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सीधे जुड़ा होगा। इसके अलावा लखनऊ– हरदोई फोर लेन स्टेट हाइवे 25 के करीब होने से भी इसे अतिरिक्त फायदा मिलेगा।

नयी पॉलिसी में बेहतरीन आधारभूत संरचना, बुनकरों के कौशल विकास और क्लस्टर अप्रोच के जरिये उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के क्रम में सरकार का ब्रांड यूपी के लिए तैयार माल की मार्केटिंग पर जोर है। इस क्रम में सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बड़ी कंपनियों मसलन फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ एमओयू करेगी। बुनकरों को अपने उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

हाल ही में पीएम मित्र योजना स्वीकृत की गयी है। इसके तहत लखनऊ–हरदोई के बीच अटारी गांव में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से 1162 एकड़ भूमि में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जायेगा। इस पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड होगा। पार्क की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा भी है कि मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में प्रदेश में स्थापित होने जा रहा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क राज्य के कपड़ा उद्योग को नयी पहचान देने के साथ करोड़ों रुपये की निवेश संभावनाओं और लाखों रोजगारों के सृजन का कारक बनेगा। यह टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री के टेक्सटाइल सेक्टर के '5–एफ' विजन (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फारेन) को साकार करते हुए उनके 'मेक इन इण्डिया' तथा 'मेक फार द वर्ल्ड' संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इससे लगभग 01 लाख प्रत्यक्ष एवं 02 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।

प्रदेश को मेगा टेक्सटाइल पार्क की सौगात मिलने के बाद अब यूपी को देश के वस्त्रोद्योग का सबसे बड़ा हब बनाने को लेकर योगी सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने मेगा टेक्सटाइल हब के लिए पहले ही कार्ययोजना बना ली थी। अब यूपी के पहले मेगा टेक्सटाइल पार्क को जल्द से जल्द तैयार कराने की कवायद तेज हो गयी है।

लखनऊ की मलिहाबाद तहसील के माल ब्लॉक के अटारी गांव में बनने वाले टेक्सटाइल पार्क का विशाल परिसर प्रदेश के 15 जिलों में चलने वाले वस्त्र उद्योग की सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा। यहां लखनऊ की चिकनकारी और जरी–जरदोजी, हरदोई और बाराबंकी का हैंडलूम, सीतापुर की दरी, उन्नाव की जरी जरदोजी, कानपुर की होजरी और टेक्सटाइल, फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग और जरी जरदोजी, शाहजहांपुर की जरी जरदोजी, अंबेडकरनगर, आजमगढ़ गोरखपुर और रामपुर का हैंडलूम उद्योग, मऊ और वाराणसी का सिल्क, हैंडलूम और टेक्सटाइल क्लस्टर और गौतमबुद्ध नगर का अपैरल क्लस्टर एक ही परिसर में समाहित होंगे। साथ ही इन जिलों से भी ये टेक्सटाइल पार्क सीधे–सीधे जुड़ा रहेगा।

मेगा टेक्सटाइल पार्क को सबसे बड़ा लाभ यूपी में सुदृढ़ हुई रोड, रेल, वायु और वाटर कनेक्टिविटी से मिलने वाला है। उत्तराखंड के सितारगंज और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के नजदीक स्थित मेगा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से सीधे जुड़ा होगा। इसके अलावा लखनऊ– हरदोई फोर लेन स्टेट हाइवे 25 के करीब होने से भी इसे अतिरिक्त फायदा मिलेगा। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी यहां से महज 45 किमी की दूरी पर होने से एयर कार्गो की तक पहुंच आसान होगी। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन 40 किमी और सीतापुर जंक्शन 70 किमी की दूरी पर स्थित है। साथ ही मलिहाबाद रेलवे स्टेशन 16 किमी की दूरी पर होने से माल ढुलाई को लेकर बेहतर रेल कनेक्टविटी मिलेगी। इनलैंड वाटर वे के जरिये प्रयागराज से कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हल्दिया बंदरगाह तक भी आसान पहुंच वस्त्र उद्योग के कारोबारियों के लाभ को बढ़ाने में सहायक होगी।

अटारी में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क में पानी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर योगी सरकार ने पहले ही आकलन करा लिया है। इसके अनुसार टेक्सटाइल पार्क के क्षेत्र में भूजल 40 फीट नीचे उपलब्ध है, जिससे पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अलावा गोमती नदी का एरियल डिस्टेंस भी 10 किमी दूर है। पार्क के बिल्कुल बगल से नहर भी गुजर रही है। म्यूनिसपल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किये गये आकलन के अनुसार 40 किलोमीटर दूरी पर मोहन रोड के समीप शिवरी गांव में वेस्ट टू इनर्जी प्लांट मौजूद है। विद्युत आपूर्ति के लिए इस क्षेत्र में 33 और 11 केवीए लाइन की मौजूदगी पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही झेठा में 400 केवीए का सबस्टेशन भी मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए काफी सहायक होगा। पार्क के 40 किलोमीटर के दायरे में पारिस्थितिकी रूप कोई भी संवेदनशील या संरक्षित क्षेत्र भी नहीं है।

पीएम मित्र योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से जो वैश्विक स्तर का टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, वह संबंधित उद्योग के लिहाज से सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा। पहले चरण के विकास में आने वाली लागत में प्रदेश एवं केंद्र की हिस्सेदारी का अनुपात क्रमशः 51:49 का होगा। पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किये जाने वाले इस पार्क के संचालन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) गठित होगी। उम्मीद है कि इस पार्क के जरिए करीब 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इसके विकसित होने पर एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं दो लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं।

गौर करने वाली बात यह है कि वस्त्र उद्योग से महज कपड़े ही नहीं मिलते हैं, बल्कि इससे हर वर्ग को लाभ मिलता है। इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट (जुलाई–2020) के मुताबिक इस सेक्टर में प्रति एक करोड़ के निवेश पर औसतन 70 लोगों को रोजगार मिलता है।

गौर करने वाली बात यह है कि वस्त्र उद्योग से महज कपड़े ही नहीं मिलते हैं, बल्कि इससे हर वर्ग को लाभ मिलता है। इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट (जुलाई–2020) के मुताबिक इस सेक्टर में प्रति एक करोड़ के निवेश पर औसतन 70 लोगों को रोजगार मिलता है। भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र–2022 में उत्तर प्रदेश को देश का 'टेक्सटाइल हब' बनाने की प्रतिबद्धता भी जतायी है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग ने 5 साल में 5 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 7500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य मुश्किल भी नहीं है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का टेक्सटाइल हब बनने की पूरी संभावना है। इसकी कई कारम हैं। उदाहरण के लिए देश की सबसे अधिक आबादी होने के नाते काम करने के भरपूर मानव संसाधन और तैयार माल के लिए बाजार यहां सहज उपलब्ध है। प्रदेश में वस्त्र उद्योग की बेहद संपन्न परंपरा के नाते यहां दक्ष श्रमिकों की भी कोई कमी नहीं है। जरूरत समय के अनुसार प्रशिक्षण देकर उनका हुनर निखारने की है। वाराणसी की रेशमी साड़ियां, भदोही की हाथ से बनी कालीन, लखनऊ की चिकनकारी, बरेली की जरी जरदोजी, नोएडा के रेडीमेड गारमेंट्स की देश–दुनिया में अपनी पहचान है। प्रदेश के 34 जिले हथकरघा बाहुल्य हैं। इसी तरह मऊ, अंबेडकर नगर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, झांसी, इटावा, संतकबीरनगर आदि जिले पॉवरलूम बहुल हैं।

उधर, देश–दुनिया में रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादन में पहचान बना चुके नोएडा में इसे संगठित रूप देने के लिए सरकार वहां अपैरल पार्क बनायेगी। इस पार्क में रेडीमेड गारमेंट्स की लगभग 115 निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। एक अनुमान के अनुसार इसमें तीन हजार करोड़ का निवेश आयेगा। जुलाई में शिलान्यास और सितंबर 2025 तक सभी इकाइयों में व्यावसायिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सरकार की योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर पांच टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क बनाने की भी है। इसके लिए अगले कुछ महीनों में जमीन चिन्हित कर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2026 तक इनमें उत्पादन शुरू कराने का लक्ष्य है। ■

मो. : 9935097419

उत्तर प्रदेश का बजट

सबके विकास को समर्पित

—योगीन्द्र द्विवेदी

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। इसे सबके विकास को समर्पित, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने तथा देश को पांच ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रदेश के एक ट्रिलियन का योगदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बिना कोई नया कर लगाए अब तक प्रदेश का सबसे बड़ा 6,90,242 करोड़ का बजट पेश किया है जो पिछले बजट की तुलना में 75,000 करोड़ रुपये अधिक है। हालांकि, प्रदेश भाजपा भी 'मिशन 2024' के अंतर्गत केन्द्र में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है और बजट में किसानों, नौजवानों व महिलाओं को कई 'उपहार' भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 'यह बजट प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत सबके हितों की पूर्ति करने वाला है।' वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि प्रदेश की राज्य सकल घरेलू विकास दर वर्तमान समय में 16.8 प्रतिशत है और इस बजट के माध्यम से उसे 19 प्रतिशत पर ले जाने का लक्ष्य है। प्रदेश की वर्तमान विकास दर राष्ट्रीय जीडीपी से लगभग दूनी है जिससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश तेजी से प्रगति करते हुए 'उत्तम प्रदेश' बनने के रास्ते पर चल रहा है। वर्तमान बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। बजट में केन्द्रीय बजट की तर्ज पर ढांचागत विकास के लिए सर्वाधिक आबंटन किया गया है और इसके बाद कृषि, स्वास्थ्य व शिक्षा को स्थान मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 20,000 करोड़ का आबंटन महत्वपूर्ण है। प्रदेश के 16 जिलों में सरकारी निजी सहयोग, यानी पीपीपी माडल पर नए मेडिकल कालेजों का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही नए डाक्टरों, नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण तेज किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास में लंबे समय से क्षेत्रीय असंतुलन व्याप्त रहा है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश तुलनात्मक रूप से राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने के कारण अधिक विकसित रहा है, वहीं बुंदेलखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीबी और पलायन के शिकार रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान

प्रदेश के वर्तमान बजट में बुंदेलखंड को सर्वाधिक धनराशि देकर इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 300 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जिनमें 'धार्मिक पर्यटन' का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार को उम्मीद है कि अगले पांच साल में पर्यर्टन क्षेत्र में दस लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी बढ़–चढ़ कर भागीदारी कर रहा है।

बजट में बुंदेलखंड को सर्वाधिक धनराशि देकर इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 300 करोड़ आबंटित किए गए हैं, जिनमें 'धार्मिक पर्यटन' का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार को उम्मीद है कि अगले पांच साल में पयर्टन क्षेत्र में दस लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिसमें निजी क्षेत्र भी बढ़–चढ़ कर भागीदारी कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को ग्रामीण विकास के केन्द्र में रखा है। सरकार का लक्ष्य देश के सभी बेघरों को जल्दी से जल्दी उनके सिर पर छत देना है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका इस योजना में संभवतः सर्वाधिक योगदान है। गांवों में 12,000 से अधिक पीएम आवास बनाने के लिए बजट में 9,000 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। कहा जाता है कि 2024 में आम चुनाव के समय तक उत्तर प्रदेश में कोई बेघर नहीं रह जाएगा। प्रदेश में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए 50–50 करोड़ रुपये की शुरुआती धनराशि रखी गई है और इनसे भी अधिकांश ग्रामीण जनता लाभान्वित होगी। प्रदेश में सड़कों, राजमार्गों व एक्सप्रेस–वे का जाल बिछाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक काम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इस दिशा में दो एक्सप्रेसवे के किनारे छः औद्योगिक काम्प्लेक्स बनाने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। प्रदेश में हाल ही में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन में सामने आए भारी निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है और बजट में इसके लिए समुचित प्राविधान किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरने से 95 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बुंदेलखंड के लिए बजट में दो नए एक्सप्रेस–वे के लिए 235 करोड़, औद्योगिक गलियारे के लिए 750 करोड़ तथा पुलों आदि के लिए 45304 करोड़ के प्रस्ताव किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश–विदेश में बेहतर कानून–व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रदेश सरकार पुलिस व्यवस्था को चाक–चौबंद बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के वर्तमान बजट में पुलिस विभाग को 2260 करोड़ रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश की लगातार बेहतर होती कानून व्यवस्था का विशेष उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि डकैती में लगभग 80 प्रतिशत, लूट में 60 प्रतिशत तथा हत्या में 83 प्रतिशत कमी आई है। प्रदेश पुलिस

को दिए जाने वाले बजट में पुलिस के लिए वाहन खरीदने के साथ ही पुलिस आवासों के लिए समुचित आबंटन किया गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले छः साल में अभियोजन प्रक्रिया को गति देने तथा उसे वैज्ञानिक बनाने के साथ न्यायालयों की ढांचागत संरचना बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। वर्तमान बजट में भी नए अदालत परिसरों के लिए 700 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बजट में खेलों को प्रोत्साहन देने के समुचित प्रयास किए गए हैं। वर्तमान बजट को खेलों के लिए सबसे बड़ा बजट बनाते हुए इसके लिए 957 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में प्रदेश में बेरोजगारी घटने को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार कहा है कि प्रदेश से युवाओं का पलायन जल्द ही समाप्त हो जाएगा तथा यहां से बाहर गए युवा प्रदेश में औद्योगिक विकास व स्टार्टअप बनाने में उल्लेखनीय भूमिका अदा करेंगे। युवाओं को टेबलेट व स्मार्टफोन बांटने के लिए 3,600 करोड़ का प्राविधान किया गया है। सात नए सर्वोदय विद्यालय खोलने तथा अटल आवासीय विद्यालयों को 113 करोड़ आबंटित करने की घोषणायें जमीन पर उतरने से ग्रामीणो व युवाओं को लाभ होगा।

किसानों को मुफ्त सिंचाई का उपहार देने के साथ ही प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी अद्यतन जानकारी देने के लिए 17,000 किसान पाठशालायें खोलने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के प्रयासों की तर्ज पर जैविक खेती व मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दे रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भारत सरकार व खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वर्ष 2023 को 'मिलेट इयर' घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोटे अनाजों को 'श्री अन्न' कहा है। श्री अन्न की खेती से जहां जल संरक्षण होगा, रासायनिक खादों व कीटनाशकों का उपयोग घटेगा, वहीं इनके प्रयोग से स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। भारत वर्तमान समय में श्री अन्नों का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। इनको बढ़ावा देने से किसान व खासकर छोटे किसान समृद्ध होंगे। किसानों को मुफ्त सिंचाई का लाभ पहुंचाने के लिए एक ओर तो निजी नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए 1950 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, वहीं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 'ड्रिप सिंचाई' को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से 'गौकशी' लगभग बंद हो गई है, लेकिन खेती में बैलों का प्रयोग बंद होने तथा अन्य कारणों से आवारा जानवरों की समस्या किसानों को लगातार परेशान कर रही है। प्रदेश सरकार के पिछले बजटों की तरह इस बजट में भी छुट्टा जानवरों को आश्रय स्थलों में रखने के लिए 750 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरी, मधुमक्खी पालन, भेड़पालन, बकरीपालन व मत्स्यपालन को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए बजट में प्राविधान किए गए हैं। इसके साथ ही वृक्षारोपण के लिए 935 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। सम्पूर्णता में देखें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश के विकास हेतु यथासंभव अधिकाधिक प्रयास कर रही है। सबसे जरूरी है कि बजट घोषणायें जमीन पर उतरें तथा किसानों समेत आम जनता को उसके लाभ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ें। योगी सरकार के लिए अब यह सबसे बड़ा लक्ष्य है और वह इस लक्ष्य को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। ▪

मो. : 9305894597

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश–विदेश में बेहतर कानून–व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रदेश सरकार पुलिस व्यवस्था को चाक–चौकंद बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश के वर्तमान बजट में पुलिस विभाग को 2260 करोड़ रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश की लगातार बेहतर होती कानून व्यवस्था का विशेष उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि डकैती में लगभग 80 प्रतिशत, लूट में 60 प्रतिशत तथा हत्या में 83 प्रतिशत कमी आई है।

बजट में दिखी आत्मनिर्भर बनने की इच्छाशक्ति

–राघवेन्द्र प्रताप सिंह

योगी सरकार ने पेश किया 6.9 लाख करोड़ रुपये का बजट–किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली –2025 में महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित–32.7 हजार करोड़ रुपये की 280 नई योजनाएं शामिल योगी सरकार ने इस बार विधानमंडल में 6.9 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से प्रस्तुत किए गए इस भारी भरकम बजट के जरिये सरकार ने केंद्र सरकार से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का इरादा जताया है। वहीं अगले साल होने वाले लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों को साधने के सारे जतन भी किए हैं। बजट में 32,721.96 करोड़ रुपये की 280 नई योजनाएं शामिल हैं। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। साथ ही निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये, वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से उत्साहित सरकार ने बजट में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए नई योजना शुरू करने का हौसला दिखाया है। पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने का इरादा भी जताया है। आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम कर सरकार ने अपने वादे को निभाया है। युवाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए कुशीनगर में कृषि

विश्वविद्यालय समेत राज्य में चार नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना की 1.74 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली, दीपावली पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर के रीफिल के लिए 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लिए दो लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार के लिए भी सरकार ने खजाना खोला है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार पैनी करने की कोशिश भी बजट में दिखी है। विकास को गति और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1,47,492.29 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय के रूप में नई परिसंपत्ति के सृजन पर खर्च किये जाएंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए भी मोटी रकम आवंटित की गई है।

ऐसे मिला बजट

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र–छात्राओं को स्मार्टफोन और टेबलेट के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान।

''मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को रुपये 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से उत्साहित सरकार ने बजट में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए नई योजना शुरू करने का हौसला दिखाया है। पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने का इरादा भी जताया है।

सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट–अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती तीन वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ रूपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है. असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वर्ष 2023 –2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 25,350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2023–2024 तक इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सत्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में पांच अन्तर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। प्रदेश में तीन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–

2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

दिल्ली–गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023– 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है. वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

बुन्देलखण्ड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के 04 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, अयोध्या, चाँदा तथा मेरठ में अवस्थापना कार्यों हेतु लगभग 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05–05 गो–आश्रय केन्द्र स्थापित/क्रियाशील है। छुट्टा गोवंश के रख–रखाव हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. पशु रोग नियंत्रण हेतु 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3 करोड़ 44 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नई योजनाओं के मद बजट में नई योजनाएं विभाग–

- धनराशि करोड़ में उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)–341.35
- उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)–185
- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)–1927.63
- खेल विभाग–193.21
- गृह विभाग पुलिस–487.79
- नियोजन विभाग–2221.77
- परिवहन विभाग–500
- पर्यटन विभाग–192
- महिला एवं बाल कल्याण विभाग–325.98
- राजस्व विभाग दैवीय विपत्तियों के संबंध में–348.89
- लोक निर्माण विभाग संचार साधन व सड़कें–3955
- लोक निर्माण विभाग संचार साधन एवं सेतु–1768.21
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग–397.76
- शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा– 642
- शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा–638
- शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा–559.01
- सिंचाई विभाग निर्माण कार्य–2578.15

योजना का नाम–धनराशि करोड़ में

- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे परियोजना–85
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना–150
- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय–465.93
- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–210
- पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाएं–400
- बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाएं–300
- सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड पोषित ओवरब्रिज, अंडरब्रिज का निर्माण–350
- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण–315.16
- रेलवे उपरिगामी व अधोगामी सेतुओं का निर्माण–354.55
- नाबार्ड पोषित सेतुओं का निर्माण–748.50
- चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण 250
- प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण–500
- राज्य राजमार्गों का सुधारीकरण–500

- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना–310
- शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाई ओवर का निर्माण–300
- आगरा में साइंस सिटी की स्थापना–15
- वाराणसी में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना–15
- ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना–300
- संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के असेवित जिलों में अनुसूचित जाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण– 50

सामाजिक सरोकारों का भी रखा ध्यान

- बजट में बुजुर्गों, दिव्यांगों व युवाओं पर किया फोकस
- समाज कल्याण विभाग को दिया 31,813.92 करोड़ रुपये का बजट

योगी सरकार 2.0 ने अपने दूसरे बजट में सामाजिक सरोकारों पर फोकस करते हुए बुजुर्गों, युवाओं व दिव्यांगों का भी ख्याल रखा है। सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए समाज कल्याण विभाग को 31,813.92 करोड़ रुपये बजट दिया है। पिछले वर्ष सरकार ने 29,236.57 करोड़ रुपये दिए थे। सरकार ने गरीब बुजुर्गों का जीवन आसान बनाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रुपये दिए हैं। पिछले वर्ष 7053.56 करोड़ रुपये मिले थे। सरकार बुजुर्गों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन देती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में 56 लाख से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन दे रही है। दिव्यांगजन पेंशन के लिए सरकार ने 1120 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे 11 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार ने बड़ा बजट दिया है। इस बार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार ने फिर 600 करोड़ रुपये दिए हैं। अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 962 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं की पूर्वदशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए भी सरकार ने 2107 करोड़ रुपये दिए हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 530 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 34.50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- पिछड़ा वर्ग के पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए–2107 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए– 962 करोड़ रुपये
- सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए–530 करोड़ रुपये
- जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए– 34.50 करोड़ रुपये
- वृद्धावस्था पेंशन योजना –7240 करोड़
- निराश्रित महिला पेंशन–4032 करोड़
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना– 600 करोड़
- दिव्यांगजन पेंशन योजना–1120 करोड़
- कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण योजना–42 करोड़

सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा

राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ (ऋणग्रस्तता) बढ़ा है। बजट के आंकड़े इसे बयां कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों में राज्य की ऋणग्रस्तता 6,66,153.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 32.5 प्रतिशत था। वहीं वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में पेश किये गए 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमानों में न सिर्फ राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा है बल्कि जीएसडीपी में उसकी हिस्सेदारी भी बढ़कर 34.2 प्रतिशत हो गई है। इसकी वजह यह है कि 2022–23 के बजट अनुमान में प्रदेश की ऋणग्रस्तता 6,66,153.39 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन पुनरीक्षित अनुमानों में यह बढ़कर 7,00,445.52 करोड़ रुपये हो गई है जबकि जीएसडीपी में बदलाव नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में राज्य की ऋणग्रस्तता 7,84,113 करोड़ रुपये और प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 24,391,71 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस आधार पर 2023–24 में कर्ज का बोझ भले ही बढ़ने का अनुमान है लेकिन जीएसडीपी में उसकी हिस्सेदारी घटकर 32.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन व ब्याज पर खर्च

राज्य सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा राज्य कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन और लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर खर्च होता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 55.4 प्रतिशत हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी पर खर्च होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर 1,66,161.2 करोड़ रुपये, पेंशन पर 82,422.38 करोड़ रुपये और ब्याज की अदायगी पर 50,255. 56 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस तरह वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी पर अगले वित्तीय वर्ष में कुल 2,98,839.14 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों के जरिए सरकार ने 5,70,865.66 करोड़ रुपये जुटाने की मंशा जताई है। इस हिसाब से कुल राजस्व प्राप्तियों में वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी की हिस्सेदारी 52.34 प्रतिशत है। वहीं कुल राजस्व व्यय के अनुपात में यह 59.48 प्रतिशत है। 2023–24 में सरकार का कुल राजस्व व्यय 5,02,354.01 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

इस साल अनुमान से 35,417 करोड़ कम मिलेगा कर राजस्व

- अगले वित्तीय वर्ष में कर राजस्व से 2,62,634 करोड़ कमाने की उम्मीद।
- बाजार से 75,150 करोड़ रुपये कर्ज लेगी सरकार।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए पेश किये गए 6,90,242.43 करोड़ रुपये के भारी–भरकम बजट को ईंधन देने के लिए राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से 2,62,634 करोड़ रुपये हासिल करने का मंसूबा पाला है। वर्ष 2022–23 में उसने स्वयं के कर राजस्व से 2,20,655 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद लगाई थी लेकिन अगले वर्ष के बजट के साथ पेश किये गए पुनरीक्षित अनुमानों में उसे चालू वित्तीय वर्ष में 1,85,237.98 करोड़ रुपये ही प्राप्त होने की संभावना है। इस तरह उसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वयं के कर राजस्व से अनुमान से 35,417 करोड़ रुपये कम राजस्व मिलने के आसार हैं। पुनरीक्षित अनुमान में कर राजस्व की सभी मदों में कमी आने की संभावना जतायी गई है।

इसके बावजूद राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में इस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 77,396 करोड़ रुपये यानी 41.78 प्रतिशत अधिक कर राजस्व प्राप्त करने का अनुमान लगाया है। इसमें राज्य वस्तु एवं सेवाकर से 1,08,212 करोड़ रुपये, राज्य उत्पाद शुल्क से 58000 करोड़ रुपये, वैट से 41788 करोड़ रुपये, स्टांप तथा पंजीकरण फीस से 34560 करोड़ रुपये, वाहन कर से 12672 करोड़ रुके और विद्युत कर तथा शुल्क से 6440 करोड़ रुपये प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यांश से 183237.59 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान जताया है। केंद्रीय सहायता के रूप में 84,199 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद जतायी है। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में अनुदान के तौर पर 15,487.61 करोड़ रुपये हासिल करने का अनुमान लगाया है। वहीं बाजार से 75,150 करोड़ रुपये कर्ज लेने का इरादा जताया है। ▪

मो. : 9415650340

भारत के प्रगति रथ का सबसे मजबूत पहिया उत्तर प्रदेश

—सरिता त्रिपाठी

किसी भी राज्य का लक्ष्य होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े जिससे उसके नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया जा सके जिससे बुनियादी और उन्नत अवसंरचनाओं का विकास हो सके। लेकिन ऐसा चाहने मात्र से नही हो जाता। इसके लिए एक बड़े विजन और पहल करने के प्रवृत्ति का होना भी जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के जरिए यह दिखा दिया है कि देश दुनिया के बड़े निवेशक कैसे योगी सरकार के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश को सुरक्षित निवेश का पहला गंतव्य मान रहे हैं। देश और दुनिया ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षमता का मुआयना इस समिट में कर ये जान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का इंजन बनने की क्षमता है। यह एक ऐसा प्रदेश है जो रोजगार सृजन और मानव पूंजी के सबसे मजबूत माडल के रूप में उभरते हुए पाया गया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 95 लाख एमएसएमई हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। ऐसे में यहां औद्योगिक विकास के असीम विकास की संभावना है। 6 वर्ष पूर्व तक जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य जाना जाता था उसने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ मिलकर सुशासन की नींव रखते हुए बीमारू राज्य के दंश को मिटाने का संकल्प लिया। 25 सेक्टर चिह्नित कर पारदर्शी नीतियां बनाई और आज उसका परिणाम है कि वैश्विक निवेशक समुदाय यहां निवेश करने को तत्पर है।

उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में अवश्यम्भावी सिद्धि बनने वाले ऐतिहासिक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 का समापन हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ है। तीन दिवसीय यूपी जीआईएस का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस समिट के जरिये उत्तर प्रदेश में समावेशी विकास के लिए करीब 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के करार हुए जिनसे लगभग 93 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

ऐसे में यहां औद्योगिक विकास के असीम विकास की संभावना है। 6 वर्ष पूर्व तक जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य जाना जाता था उसने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ मिलकर सुशासन की नींव रखते हुए बीमारू राज्य के दंश को मिटाने का संकल्प लिया। 25 सेक्टर चिह्नित कर पारदर्शी नीतियां बनाई और आज उसका परिणाम है कि वैश्विक निवेशक समुदाय यहां निवेश करने को तत्पर है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समावेशी विकास की सोच के साथ आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के सार्थक परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश को विश्वव्यापी ख्याति मिलेगी। दूरदर्शितापूर्ण नीतियों को लागू कर तथा उसके कार्यान्वयन से उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने के लिए सक्षम भी है और इसके लिए तैयार भी है। उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा तो भारत भी समृद्ध होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश को उत्तम निवेश प्रदेश बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी काम हुआ है। सड़क यातायात, हाइवे व एक्सप्रेस–वे में निवेश से आर्थिक विकास में काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता है कि देश मे 65 प्रतिशत मोबाइल उपकरण अकेले उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यही नहीं परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने वाली उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) भी काफी सफल है। परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक उन्नयन तो होता ही है, निवेशकों को भी काफी अवसर मिलता है।

उत्तर प्रदेश की धरती अन्नदाता की धरती है। खाद्यान्न, गन्ना, आलू आदि व दूध के उत्पादन में यह देश में अग्रणी है। इसी आधार पर भारत की राष्ट्रपति ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्यमिता विकास की अनेक संभावनाएं हैं। प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिलेट्स की डिमांड और सप्लाई चौन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है। यह डिफेंस कॉरिडोर देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को सफलता प्रदान करने के साथ ही उद्यम, रोजगार और विकास को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि यहां विकास के साथ पर्यावरण संतुलन के भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी विकसित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के यह प्रयास देश के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जब निवेश का माहौल बनता है तो स्वरोजगार को भी बल मिलता है। इस दिशा में स्टार्टअप को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी महत्वाकांक्षी प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के सबसे युवा राज्य उत्तर प्रदेश का स्वरोजगार में भी अग्रणी स्थान होगा।

निवेश का सुरक्षित गंतव्य होगा उत्तर प्रदेश :

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन दिन तक चले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि निवेश के इस वैश्विक महाकुंभ में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस निवेश से 93 लाख नौकरी व रोजगार का सृजन होगा। पहले निवेश का मतलब सिर्फ एनसीआर में

निवेश होता था। लेकिन अब उद्योगपति, पूंजीपति उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में निवेश के आकांक्षी है। मुकेश अंबानी ने तो 2018 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश पहले ही कर रखा है और इस बार के इन्वेस्टर समिट में उन्होंने उत्तर प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए के निवेश की बात की है। इस बार के समिट में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए निवेश मिले हैं। कमजोर समझे जाने वाले पूर्वांचल व बुंदेलखंड में भी भारी निवेश आया है। 9.54 लाख करोड़ तथा बुंदेलखंड में 4.28 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ऐसी ऊंचाई मजबूती मिली है कि आपराधिक तत्वों के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। बेहतर कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास में क्या संबंध है ये योगी सरकार ने साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन सभी बुनियादी और उन्नत अवसंरचनाओं का विकास किया, बेहतर सड़कें, राजमार्ग, एक्सप्रेस–वे, एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जो आर्थिक प्रगति के ईंधन का काम कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की संभावना को बड़े स्तर पर खोजना शुरू कर दिया है।

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफार्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर काम किया है। पारदर्शी नीतियों और तकनीकी को अपनाकर निवेश के चार स्तम्भो पर काम किया उत्तर प्रदेश ने काम किया है। एमओयू से लेकर निवेश को धरातल पर उतारने तक के चरणों में उद्यमियों की सहायता के लिए निवेश सारथी, निवेश मित्र, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र और इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे पारदर्शी सिंगल विंडो सिस्टम बनाए गए। इन सबके साथ हर निवेशक प्रदेश के कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर निवेश के लिए आकर्षित हुआ। आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देश के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य लेकर यूपी को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनाने के लिए काम किया जाना भी शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नीति आयोग से विकास के नए मानकों को गढ़ने का मंत्र भी हाल के वर्षों में सीखा है और इस बात का संकेत भी दे दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर नीति आयोग जैसी संस्था का गठन करने का विचार कर रहा है ताकि एक थिंक टैंक दिन रात उत्तर प्रदेश की आर्थिक संभावनाओं के दोहन के लिए काम करे, सिफारिशे दें।

आध्यात्मिक पर्यटन के जरिए जोरदार निवेश और राजस्व की बनी नीति :

उत्तर प्रदेश प्राचीनकाल से ही आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, काशी का बाबा विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या हो या कान्हा मथुरा वृंदावन यूपी में है। गंगा, जमुना और

उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य की नई पर्यटन नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। इस नीति के माध्यम से सरकार ने कम प्रसिद्ध स्थानों को विकसित करने पर भी जोर दिया है।

सरस्वती की त्रिवेणी, कुंभ की धरती प्रयागराज भी यही है। भगवान बुद्ध की साधना स्थली, बाल्यकाल का क्षेत्र, प्रथम उपदेश की प्रथम भूमि और महापरिनिर्वाण स्थली भी यूपी के सौभाग्य में शामिल है। यह विद्या की धरती है तो विशिष्ट पहचान रखने वाले परंपरागत उद्यम के आकर्षण की भी धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद, परंपरागत उद्यम को ओडीओपी से जोड़कर इन उद्यमों के उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई गई है।

उत्तर प्रदेश को देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य की नई पर्यटन नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। इस नीति के माध्यम से सरकार ने कम प्रसिद्ध स्थानों को विकसित करने पर भी जोर दिया है।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नई नीति को देखें तो अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और ऐसे अन्य ''महत्वपूर्ण स्थान'' रामायण सर्किट में शामिल किए जाएंगे। इसी तरह मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव कृष्ण सर्किट में शामिल होंगे और बौद्ध सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम और अन्य स्थान शामिल होंगे। जैन सर्किट को देवगढ़, हस्तिनापुर से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर तक भी बढ़ाया जाएगा।'' वन्यजीवों और ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में अभयारण्यों और वन भंडारों को विकसित किया जा रहा है। साथ ही, वन्य जीवन से संबंधित क्षेत्रों को विकसित करते हुए पर्यटकों के अनुकूल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश में महाभारत सर्किट की भी परिकल्पना की गई है और हस्तिनापुर, कांपिल्य, एकछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्षागृह जैसे स्थानों का चयन किया गया है। इसी तरह शक्तिपीठ सर्किट को भी विकसित किया जाएगा। इसका विस्तार विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से देवीपाटन, नैमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी सहारनपुर से शिवानी देवी, चित्रकूट और मऊ जिले के शीतला माता तक होगा। इन सभी उपायों से आर्थिक विकास और बेहतर आध्यात्मिक धार्मिक अनुभव दोनों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए योगी सरकार मुखर हुई है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को साकार करने में बैंकों की भूमिका पर बल देती योगी सरकार :

किसी भी देश या प्रदेश के विकास को नई बुलंदियां देने में बैंक और उद्योग की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। बिना बैंकों के सहयोग के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी बात को ध्यान में रखकर इस बार के उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बैंकों से प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले उद्योगपतियों को

कम कागजात और आसान शर्त पर लोन देने की अपील की। साथ ही कहा कि इस प्रक्रिया को अपनाने में ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग हो यह भी जरूरी है। केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार का फोकस एमएसएमई यूनिट पर है। बैंकों को भी इस ओर फोकस करना होगा तभी प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को हम बुलेट ट्रेन की रफ्तार दे सकेंगे। योगी सरकार ने प्रदेश में एमएसएमई यूनिट को बढ़ाने के लिए पॉलिसियों में कई तरह की रियायतें दी हैं। यही वजह है कि प्रदेश में देश ही नहीं विदेश के निवेशक भी यूपी में अपना उद्योग लगाने के लिए यूपीजीआईएस–23 के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए यहां आए। इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। यह योगी सरकार की नीतियों का ही असर है कि प्रदेश में एक्सपोर्ट बढ़ा है, जो वर्तमान में एक लाख 56 हजार करोड़ को पार करने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपेक्षा की है कि बैंकर्स एमएसएमई यूनिट को लोन देने में कोई कसर न छोड़ें क्योंकि यही यूनिट उनकी ग्रोथ का इंजन भी बनेंगी। पीएनबी के चेयरमैन ने का इस समिट में कहना था कि उनका सबसे ज्यादा फोकस किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पर है। इसके लिए बैंक की ओर से कई तरह की स्कीम जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4.6 प्रतिशत की दर से एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है इसे बढ़ाने के लिए हमारी बैंक फसल बीमा समेत कृषि से जुड़े तमाम इंफ्रा पर किसानों की मदद कर रही है। एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीन राघवेंद्र ने बताया कि उनकी बैंक ने डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में काम किया है और लगातार इसे बेहतर करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एसबीआई का करीब 97 प्रतिशत ट्रांसजेक्शन अलग–अलग पैनल पर होता है इसे एक करने के लिए बैंक ने यूनो एप लांच किया, जिसमें 5 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को बोर्ड किया गया है। वहीं एमएसएमई यूनिट के लिए एक एप डे वलप किया गया है, जिसके माध्यम से 20 लाख तक के लोन के लिए बिना किसी कागजात के लोन दिया जा रहा है।

मजबूत होता उत्तर प्रदेश का रेलवे मानचित्र :

रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा कि उत्तर प्रदेश (यूपी) की जीआईएस–23 की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ा रही है। भारत की ग्रोथ में यूपी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसी वजह से जी–20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं। हमें यूपी को दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जब रेल बजट आता था तो यूपी के हिस्से में 1000–1100 करोड़ रुपए आवंटित होते थे। इस बार के बजट में मोदी सरकार ने यूपी के हिस्से में 16 गुना बढ़ोतरी की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस–23) के तीसरे दिन यूपी में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क विकास को लेकर रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 17507 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान–प्रदान किया गया। इस दौरान रेल और सड़क के आधुनिकीकरण में उत्तर प्रदेश विषय पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के तहत उत्तर प्रदेश के 150 स्टेशन को विश्व स्तर का बनाया जा रहा है। आर्ट और क्राफ्ट में कार्य करने वाले लोगों के वन स्टेशन वन उत्पाद की योजना शुरू की गई है। इससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों की आमदनी बढ़ी है। साथ ही ये उत्पाद

लोकल से ग्लोबल बन गए हैं। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि रेलवे से जुड़कर बिना किसी संकोच के आप उत्तर प्रदेश में अपना प्रोजेक्ट लगाएं और अपने निवेश को फलदाई बनाएं। रेलवे इसमें आपका पूरा सहयोग करेगा। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि देश का औद्योगिक रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन क्रांति के लिए पूरी तैयार है। यूपी में चार लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व प्रदेश में एक्सप्रेस–वे और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। 560 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस–वे पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 59 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर काम पूरा हो चुका है। साथ टी 250 आरओबी को चिन्हित कर लिया गया है, जिन पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख टीयूवी का कार्य रेलवे के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इसका पूरा खर्च रेलवे वहन करेगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद निवेशकों से यूपी में निवेश की आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले समय में यूपी से सिर्फ भारत की राजनीति का ही नहीं बल्कि देश का औद्योगिक रास्ता भी उत्तर प्रदेश से जाएगा।

रेलवे बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर) के सदस्य रूप नारायण शंकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क के विकास किया जा रहा है। देश में 1275 रेलवे स्टेशनों को विश्वस्तर का बनाया जा रहा है, इनमें 150 यूपी में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 हजार किमी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। फरवरी के अंत तक उत्तर प्रदेश के पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो जाएगा।

फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने से भी उत्तर प्रदेश के रेल के नेटवर्क में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। रेलवे के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र जैन ने कहा कि देश में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बना रहे हैं। इसमें एक पश्चिम कॉरिडोर है तो दूसरा पूर्वी कॉरिडोर है। इन फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से माल गाड़ियों का आवागमन सुगम हो जाएगा और समय की बचत होगी। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हजार 58 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके पूरा होने से उत्तर प्रदेश के रेल के नेटवर्क में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। यहां निवेश करने वाले उद्यमियों को अपना माला लाने और ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी।

फिल्म उद्योग के विकास के व्यापक निवेश आकर्षण की राह पर उत्तर प्रदेश अग्रसर :

दुनिया भर के फिल्म मेकर्स अपने फिल्म के निर्माण के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारत आते हैं। कोई मुंबई आता है, कोई चेन्नई तो कोई हैदराबाद। यूपी में जिस फिल्म सिटी के निर्माण की बात हो चुकी है जब उसकी शुरुआत हो जाएगी तो उन्हें उत्तर प्रदेश आने से भी कोई नहीं रोक सकता। यूपी की फिल्म पॉलिसी दिखाती है कि यदि आप यहां फिल्म बनाएंगे तो आपको कई तरह की छूट प्राप्त होंगी। स्पोर्ट्स और सिनेमा को एक साथ बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश खुले मन से काम कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में फिल्म पॉलिसी को मजबूती से लागू किया है। फिल्मों के निर्माण पर 2 से ढाई लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। फिल्मों के साथ–साथ लैब के गठन, प्रॉसेस और प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान दिया जाएगा। यही नहीं, मुंबई में मिले सुझावों के आधार पर उत्तर प्रदेश वेब सिरीज, ओटीटी को भी अनुदान देने पर विचार कर रहा हैं। नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित है। एक या दो महीने में इसकी बिड का काम फाइनल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक फिल्म निर्माण का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है। 20 से ज्यादा फिल्मों को प्रदेश सरकार 44 करोड़ रुपए का अनुदान दे चुकी हैं। जैसे टूरिज्म में हम कहते हैं उसी तरह फिल्मों के लिए भी यह कहा जा सकता है कि यूपी में निवेश नहीं किया तो क्या किया। जेवर में एक और फिल्म सिटी के साथ ही रीजनल फिल्म सिटी की भी प्लानिंग की जा रही है। 500 करोड़ का निवेश बॉलीवुड की तरफ से करने की सतीश कौशिक की बात हो, उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक थिएटर बनाने की बात हो, इसके जरिए 10 हजार लोगों को रोजगार देने की बात हो, फिल्म निर्माता मंधुर भंडारकर का ये विश्वास हो कि योगी सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत कर दी है। फिल्मों के अलावा ओटीटी को अनुदान का फैसला भी फिल्म जगत के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के हौसले से सभी ताकत महसूस कर रहे हैं।

योगी सरकार सामाजिक न्याय में भी कर रही निवेश :

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास और योजनाओं को लागू करने में काफी तेजी आई है। जून 2015 में जब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की तब यहां की तत्कालीन सरकार से इस योजना को लागू करने में केंद्र सरकार को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, ये किसी से छिपा नहीं है। जून 2015 से 17 महीने तक इस देश के सबसे बड़े राज्य में मात्र 17 हजार प्रधानमंत्री आवास बन पाए। इसके बाद 2017 में उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद अगले 17 महीनों में 17 लाख आवास बने, ये आंकड़े उत्तरप्रदेश की सफलता की कहानी बताने के लिए काफी हैं। आज उत्तर प्रदेश केंद्र की योजनाओ को लागू करने में नम्बर एक पर है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के लिए हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं,एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उससे पहले 2040 तक ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की यह खासियत है कि यहां अयोध्या, काशी और मथुरा की इस भूमि ने हमेशा से भारत को नई राह दिखाई है। उत्तर प्रदेश भारत के विकास में हरदम प्राथमिकता रखता था और रखता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है। यूपी को निवेश के लिए सबसे अनुकूल स्थान मानने में किसी को कोई शक नही है। 6 साल में यूपी में जिस तरह से कार्य हुआ, वो सभी को चौंका रहा है। रोड कनेक्टिविटी की बात हो या सिविल एविएशन की, यूपी ने हर क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। जिस प्रदेश में कभी मात्र 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहां आज वह 9 हवाईअड्डे क्रियाशील हैं। 10 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, इसके अलावा 2 एयरपोर्ट के लिए जमीन देखने का काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जा रहा है। इस तरह उत्तर प्रदेश सिविल एविएशन के सेक्टर में निवेश के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के एयरलाइंस सेक्टर का जिस तरह प्रजातांत्रिकरण हुआ है, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन का क्षेत्र असीम संभावना वाला है। आने वाले समय में प्रदेश में 21 एयरपोर्ट होने वाले हैं, इनमें से 16 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। इससे करोड़ों लोगों का आकाश में उड़ने का सपना साकार होगा।

इस तरह उत्तर प्रदेश 6 वर्ष में गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा मिसाल बन चुका है। प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए यूपी आज इज ऑफ डूइंग के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भी अग्रसर है। आज यूपी भारत के ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। ■

मो. : 9415650332

मेट्रो बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर

–सुरेन्द्र अग्निहोत्री

डबल इंजन की सरकार के सहयोग से आधुनिक, गतिमान तथा विकसित होते उत्तर प्रदेश को एक आधुनिक, तीव्र गति, सुरक्षित और सस्ती यातायात व्यवस्था आम नागरिको, पर्यटकों की सुविधा में बिस्तार एवं ओद्योगिक विकास के सपने में पंख लगाने में मेट्रो रेल महत्वपूर्ण हो रही है। प्रदेश की तस्वीर बदलने योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2023–24 का बजट में प्रदेश में रेल और रोप वे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिया है। योगी सरकार के बजट 2023–24 में जहां यूपी के चार महानगरों में मेट्रो रेल सेवा को विकसित करने के लिए ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, वहीं वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत के पहले रोपवे प्रोजेक्ट को भी खास तरजीह दी गयी है। इसके अलावा महानगरों के विस्तार के लिए भी बजट में खास प्रावधान किये गये हैं। योगी सरकार के बजट 2023–24 में शहरी क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है। इसके तहत वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप–वे सेवा विकसित किये जाने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

लखनऊ, नोयडा तथा कानपुर वासियों को मेट्रो रेल का सफर उपलब्ध भले ही सुलभ हो लेकिन आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी के लिए सिर्फ कल्पना की दुनिया को साकार करने की दिशा में यूपी सरकार के कुछ कदम सड़को पर जाम आम होने से श्रम और कार्यक्षमता के लाखों

लखनऊ, नोयडा तथा कानपुर वासियों को मेट्रो रेल का सफर उपलब्ध भले ही सुलभ हो लेकिन आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी के लिए सिर्फ कल्पना की दुनिया को साकार करने की दिशा में यूपी सरकार के कुछ कदम सड़को पर जाम आम होने से श्रम और कार्यक्षमता के लाखों घंटे बेकार चले जाने को रोकने अग्रसर है। इन घंटों का उपयोग सृजन एवं निर्माण की दिशा में लगने से प्रदेश की तस्वीर का रुख अनुपम गतिमान बन जायेगा।

घंटे बेकार चले जाने को रोकने अग्रसर है। इन घंटों का उपयोग सृजन एवं निर्माण की दिशा में लगने से प्रदेश की तस्वीर का रुख अनुपम गतिमान बन जायेगा। प्रदेश के स्वप्नदर्शी कर्मशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में कानपुर के वासिंदों के यातायात में होने वाली परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिये मेट्रो प्रदान की थी उसे अपने दूसरे कार्यकाल मे परियोजना को गति देने आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में यातायात को दबाव को कम करने के लिए मेट्रो को दौड़ाने की कवायद फिर शुरू हो गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवा की कवायद तेजी से चल रही है। गोरखपुर महानगर में जल्द ही मेट्रो परियोजना के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस परियोजना के प्रगति की निगरानी कर रहे हैं। सीएम योगी ने एक माह पूर्व वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए भी इस दिशा में काम तेज करने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब बजट पास होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार के रूप में रैपिड, मेट्रो में केंद्र बजट में 3596 करोड़ मिले है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए आम बजट में इस बार दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रैपिड, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने अपने कोटे का हिसाब चुकता कर दिया है। करीब 30 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार को 50 प्रतिशत राशि देनी थी। 2023–24 के बजट में 3596 करोड़ की व्यवस्था की गई है। प्रोजेक्ट में अब तक केंद्र सरकार से 15 हजार 265 करोड़ की राशि का आवंटन हो चुका है।दिल्ली–मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर मेरठ समेत पश्चिम क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में केंद्रसरकार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सरकार का शेयर है। सबसे बड़ा हिस्सा 50 प्रतिशत केंद्र सरकार का है। रेपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने पिछले तीन साल में कुल 11 हजार 669 करोड़ रुपये बजट में जारी किए थे।वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में सबसे अधिक 4710 करोड़ का बजट जारी किया गया था। इससे पूर्व 2021–22 में 4472 करोड़ और 2020–21 में 2487 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इस तरह तीन साल में 11 हजार 669 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रैपिड रेल के लिए जारी किए तो अब प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3596 करोड़ की व्यवस्था बजट में की है। इस तरह अब यह प्रोजेक्ट अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। गोरखपुर में 15.14 किमी लाइट मेट्रो रेल चलाने के लिए केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट इंवेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी तरह

लखनऊ में फेस–एक बी में 11.165 किमी मेट्रो रेल चारबाग से बसंत कुंज योजना तक चलनी है। इसके निर्माण पर 4880 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। केंद्र सरकार के बजट के बाद लखनऊ में मेट्रो रेल विस्तार के लिए पैसे की मांग आवास विभाग केंद्र सरकार से करेगा। लखनऊ की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर दूसरा रूट चारबाग से पुराने शहर में गौतम बुद्ध मार्ग, अमीनाबाद, सिटी स्टेशन, चौक, बालागंज, मूसाबाग से बसंत कुंज तक है । मोदी सरकार के बजट ने यूपी के इन पांच शहरों में मेट्रो की राह आसान कर दी है। केंद्र सरकार ने शहरों में लोगों को बेहतर सिटी ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 21968 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया है। मेट्रो के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का रास्ता साफ होगा। बजटीय व्यवस्था होने के बाद यूपी के पांच शहरों में मेट्रो रेल चलाने और सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। इससे गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी और बरेली में इसे चलाने के लिए सर्वे की राह खुल गई है। प्रदेश वासियों को रोज–रोज होने वाले जाम से मुक्ति मिल सके और विकास के रास्ते जल्द से जल्द पूरे हो। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है उस गंभीरता को कायम रखने के लिऐ आशा ही नही विश्वास के बल पर जमीनी हकीकत में उतर रही है। तभी लोगों को मेट्रो का प्रतिफल मिलेगा,विकास की राह में सुलभ और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने बाली मेट्रो एक नई भूमिका मे नजर आऐगी। ▪

मो. : 9415508695

कराने की ओर अग्रसर है। लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद में मेट्रो रेल चल रही है। लखनऊ में पहला चरण पूरा हो चुका है और 8.57 किमी में मेट्रो चल रही है। दूसरा चरण पर विचार हो रहा है। गाजियाबाद में मेट्रो का दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक 9.41 किमी का विस्तार हो रहा है।केंद्र ने कानपुर, मेरठ व आगरा के प्रस्ताव को हरी झंडी देकर यूपी को देश के नक्शे में सबसे ऊपर पहले ही ला दिया है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके नौ शहरों में मेट्रो पर प्रोजेक्टों पर काम हो रहा हो। केंद्र से मंजूरी मिलने के साथ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग कोशिश में है कि आगरा,गोरखपुर,झांसी में गतिमान मेट्रो को गति मिल सके।

यह होगा गोरखपुर मेट्रो का रूट

पहला रूट : मेट्रो का पहला रूट श्यामनगर (बरगदवां के पास) से सूबाबाजार तक होगा। इसकी लंबाई करीब 16.95 किलोमीटर होगी।

पहले रूट पर पड़ने वाले स्टेशन

श्यामनगर, बरगदवा, शास्त्रीनगर, नथमलपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय, मोहद्दीपुर रामगढ़ताल, एम्स, मालवीयनगर, एमएमएमटीयू, दिव्यनगर (भविष्य का स्टेशन) सूबा बाजार।

दूसरा रूट : दूसरा रूट गुलरिहा से नौसढ़ चौराहा तक होगा। इसकी लंबाई 12.70 किलोमीटर होगी।

दूसरे रूट पर पड़ने वाले स्टेशन

गुलरिहा, बीआरडी मेडिकल कालेज, मुगलहा, खजांची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, विष्णु नगर (भविष्य का स्टेशन), असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर, कचहरी चौराहा, बेतियाहाता, ट्रांसपोर्टनगर, नौसढ़ चौराहा।

देश के नक्शे में उत्तर प्रदेश मेट्रो विस्तार में सबसे ऊपर

उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने को अग्रसर है जो अपने प्रदेश के नागरिको को नौ शहरों में मेट्रो रेल या उसके विकल्प को उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर है।

एनसीआर के लिए महत्वपूर्ण रैपिड रेल

मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट में चार राज्यों और केंद्र सरकार की सहभागिता से गति मिली है। केंद्र सरकार को कुल प्रोजेक्ट की लागत का 50 प्रतिशत वहन करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को 12.5 प्रतिशत के हिसाब से 50 प्रतिशत राशि देनी है। इसमें से 60 प्रतिशत राशि की व्यवस्था विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से होनी है। 40 प्रतिशत की व्यवस्था केंद्र और प्रदेश सरकार को करनी है। मेट्रो के लिए 19518 करोड़ केंद्र सरकार ने आम बजट में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए इस बार पिछले दो वर्षों की अपेक्षा अधिक बजट की व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में 19518 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके पहले दो सालों में वर्ष 2021–22 में 23262 करोड़ और वर्ष 2022–23 में 15629 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

बढ़ती नगरीय सुविधाएं, सँवरते शहर

–आशीष कुमार मौर्य

उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की व्यापक सम्भावनाएं विद्यमान हैं। शहरी नियोजन आज की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का प्रमुख योगदान है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का प्रदेश बनने की ओर से उत्तर प्रदेश अग्रसर है। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शहरी विकास और नियोजित शहरीकरण की दिशा में अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ हुए हैं। विगत छह वर्षों में प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण की गति को तेज किया है। नियोजित शहरीकरण की दिशा में विभिन्न कार्ययोजनाओं को सम्पादित किया जा रहा है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास किए जा रहे हैं।

यूपी के शहरों में जीवनयापन के आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं के आकलन के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स व म्यूनिसिपल परफार्मेंस इंडेक्स सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि जीवन जीने की सुगमता का सूचकांक तैयार किया जाएगा। एकीकृत डाटा के आधार पर सर्वांगीण विकास की योजना बनेगी।

विगत 5 वर्षों में प्रदेश में 100 से अधिक नए स्थानीय निकायों का गठन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं। राज्य सरकार अपने प्रयासों से कन्वर्जेन्स के माध्यम से शेष 7 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है। प्रदेश के 60 शहरों में अमृत योजना के तहत नगरीय आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। शेष अन्य शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से भी प्रयास कर रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। शहरीकरण मूलतः नियोजन पर निर्भर है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए प्रदेश में युद्धस्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। सभी शहरी निकायों द्वारा अपने कार्यों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

यूपी के शहरों में जीवनयापन के आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं के आकलन के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स व म्यून्सिपल परफार्मेंस इंडेक्स सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के आधार पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि जीवन जीने की सुगमता का सूचकांक तैयार किया जाएगा। एकीकृत डाटा के आधार पर सर्वांगीण विकास की योजना बनेगी। यह अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क अपने आप में किसी भी शहर का रिपोर्ट कार्ड होगा। इससे एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित होगा जो शहर के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और इस इकोसिस्टम के आधार पर किया जाने वाला विकास कार्य हर वर्ग के लोगों के लिए होगा। प्रदेश के सभी स्मार्ट सिटी में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जिसमे शहर वार आंकड़े जमा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अर्बन आउटकम फ्रेमवर्क के मूल्यांकन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया गया है। इस योजना के तहत राज्यवार शहरों को सम्बंधित आकड़े" जुटाने के लिए शहरी एवं राज्य स्तर पर समन्वयकों को नामित करते हुए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से वर्ष 2018 में 111 शहरों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रारम्भ करते हुये द्वितीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2021 में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2.0 तथा म्युनिसिपल परफार्मेंस इंडेक्स की शुरूआत की गयी। तीसरे चरण में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, म्युनिसिपल परफार्मेंस इंडेक्स आदि सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके अन्तर्गत सभी स्मार्ट सिटी में करोड़ों की जनसंख्या वाले भारत के समस्त राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों तथा नगर निगम/नगर महापालिका सीमान्तर्गत समस्त शहरों को सम्मिलित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, इसके तहत अर्बन प्लानिंग के अलावा ग्रीन बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, वायु की गुणवत्ता, पानी सप्लाई और कचरा निस्तारण समेत कई मुद्दों पर काम होगा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय होगा कि किस शहर में रहने लायक कितनी सुविधाएं हैं। इसी आधार पर स्मार्ट सिटी प्रॉजेक्ट के तहत कमियां दूर करने के लिए बजट का आवंटन भी किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम वाले शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करवाने के बाद मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ ने अब 220 नगरों को भी स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार इन छोटे नगरों को पांच वर्षों में चरणवार स्मार्ट बनाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर छोटे नगरों में भी विकास होंगे। दो वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नेशनल मास्टर प्लान बनेगा। जलभराव और गंदे नालों की बेतरतीब प्रणाली को सुधारने का काम होगा। पानी के बहाव अनुरूप निकासी का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल के अंतर्गत नगर विकास विभाग के चयनित तीन इंडीकेटर्स में एक–एक ड्रेनेज सिस्टम का डाटा सीएंडडीएस, जल निगम व निकायों से तैयार किया जायेगा।

शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बनेगा मास्टर प्लान

शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए नेशनल मास्टर प्लान बनेगा। जलभराव और गंदे नालों की बेतरतीब प्रणाली को सुधारने का काम होगा। पानी के बहाव अनुरूप निकासी का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल के अंतर्गत नगर विकास विभाग के चयनित तीन इंडीकेटर्स में एक–एक ड्रेनेज सिस्टम का डाटा सीएंडडीएस, जल निगम व निकायों से तैयार किया जायेगा। शहर में बरसात के समय अधिकांश गलियां तालाब बन जाती हैं। नाले उफनाने लगते हैं। अनियोजित कालोनियों की वजह से नाले नहीं बनाए जाते हैं जिससे पानी की निकासी तो हो जाती है मगर उसके बाद क्षेत्र में हालात खराब हो जाते हैं। इसकी वजह होती है कि बरसात अधिक मात्रा में होती है और ड्रेनेज सिस्टम का आकार वही है। आबादी के लिहाज से ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता कम पड़ रही है। इसीलिए इसमें सुधार के लिए पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत नेशनल मास्टर प्लान बनाया जायेगा। इसके जरिए जल निकासी के विकल्प खोजे जाएंगे। नालों को दुरुस्त किया जाएगा। ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि पानी का कहीं भी जमाव ना होने पाए। बता दें कि पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट को वर्ष 2024–25 तक पूरा किया जाना है, इसी साल देश में आम चुनाव भी होने हैं। गति शक्ति प्रोजेक्ट से भारत के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संपत्तियां खड़ी हो सकती हैं। 100 लाख करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें निजी सेक्टर की कितनी भागीदारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गति शक्ति योजना का उद्देश्य है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी पक्ष के बीच समन्वय के साथ काम हो। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय कम लगेगा और संसाधनों की बबार्दी कम करने में मदद मिलेगी। ■

मो. : 09451134320, 07905513265

योगी सरकार के लिए किसान आम नहीं खास

—विमल किशोर पाठक

उप्र की योगी सरकार के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं यह सरकार द्वारा उठाये जाने वाले हर कदम से साबित होता है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य के भुगतान का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह अपने आप में अनूठा है। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी जब योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 का बजट पेश किया तो बजट में प्रदेश की जनता की खुशहाली और उसकी तरक्की के साथ ही प्रदेश को आगामी वर्षों में वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लक्ष्य का पूरा रोडमैप नजर आया। युवा, महिला, गरीब, वृद्ध, दिव्यांग, किसान समेत मुख्यमंत्री योगी ने बजट में हर वर्ग और तबके का ध्यान रखा तो वहीं प्रदेश में जीआईएस–23 के तहत होने वाले भारी निवेश को दृष्टिगत रखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस रहा। यह योगी सरकार का लगातार छठवां, जबकि दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट भी था। वहीं, यह प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट भी रहा। इस बार प्रस्तुत बजट का आकार 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए है।

हमेशा की तरह इस बार भी किसानों को इस बजट में खास तवज्जो दी गई। उनके हितों के साथ–साथ उनकी एजुकेशन पर भी फोकस रहा। बजट घोषणा के अनुसार, द मिलियन फार्मर्स स्कूल हेतु किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 831 करोड 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया गया है। यही नहीं, नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स के लिए 753 करोड़ 70 लाख रुपए तो यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए भी 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही कुशीनगर में 50 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी।

किसानों के लिए तकनीकी ट्रेनिंग की सुविधा के तहत प्रदेश में 1,700 किसान पाठशालाएं खोली जाएंगी। एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए हैं। सरकार ने आने वाले समय में किसानों को बिजली पर सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 55 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस बार बजट में किसान पेंशन योजना के लिए 7248 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला सहकारी

बैंकों के वित्तीय सुदृढीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021–2022 में 7,556.91 करोड़ रूपये का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुये। वर्ष 2022–2023 में दिनांक 30–11–2022 तक 6936.76 करोड़ रूपये का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

चूंकि छुट्टा गोवंश को लेकर सरकार की आलोचना होती है, ऐसे में गोवंश के रख रखाव को मिले 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत बुन्देलखंड में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए बुंदेलखंड के हर जिले में 5–5 गो–आश्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह बड़े गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पशु रोग नियंत्रण के लिए 116 करोड़ 52 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जिलों में भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख रुपये दिये गये हैं। इसके साथ ही प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश के सभी जिलों में 187 गो–संरक्षण केन्द्र में से 171 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। मत्स्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत होल सेल फिश मार्केट के लिये 257 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई जबकि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इसी तरह निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वहीं डेयरी सेक्टर को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए योगी सरकार ने 233 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की धनरशि खर्च करने का निर्णय लिया है। दरअसल पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 16 प्रतिशत का योगदान देकर यूपी पहले स्थान पर है। इस क्षमता को और बढ़ाने और दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में डेयरी सेक्टर के लिए 233.16 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए बड़ा बजट जारी किया गया है, जिससे किसान दुग्ध संगठन को उनके दूध का सही मूल्य और बाहरी राज्यों से देसी नस्ल की गायों की खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के लिए 86 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था की है। वहीं नन्द बाबा दुग्ध मिशन के लिए 61 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपये की बजट की व्यवस्था की गई है। ■

मो. : 9984905555

यूपी में कृषि उत्पादों का होगा भरपूर उपयोग

—राजीव गोयल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभालते ही कृषि उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया, ताकि यूपी के खाद्य पदार्थों को विश्वस्तर पर नयी पहचान मिल सके। इसी के तहत यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 लागू की गयी है। इसे बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की ओर से कई रियायतें और अलग–अलग तरह से सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, खाद्य उद्योग लगाने पर स्टाम्प शुल्क में छूट सहित मंडी शुल्क, विकास शुल्क, फसल उत्पादन के नुकसान को कम करने और उत्पादन में स्टार्टअप का इस्तेमाल करने पर भी छूट दी जा रही है। नीति के तहत सर्किल रेट से लेकर परिवहन, संयंत्र, मशीनरी, सिविल कार्य पर सब्सिडी दी जायेगी।

यही नहीं सरकार जानती है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु होते हैं, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाक़ों में लगते हैं। ऐसे में यह स्वतंत्र विद्युत औद्योगिक फीडरों की लागत वहन नहीं कर पाते। इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने उन्हें 75 केवीए तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। योगी सरकार सौर ऊर्जा परियोजना की लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी। वहीं महिलाओं के स्वामित्व और संचालन वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में संयंत्रों पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी।

इस तरह देश की सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा के जरिये पूरा किया जायेगा।

इस दिशा में योगी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल से ही फोकस किया। इसके लिए कारगर रणनीति और बेहतर पालिसी बनायी गयी। छह सालों में सरकार ने दिखा दिया कि आने वाले दिनों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश सौर ऊर्जा से भी जगमगायेगा।

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड है, इसलिये प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योग को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यात पर परिवहन की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी दी जायेगी। परिवहन की यह लागत प्रदेश में विनिर्माण/ उत्पादन के स्थान से आयातक देश के बंदरगाह तक होगी। वहीं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ पर होगी। इतना ही नहीं, इकाइयों के विस्तार पर भी संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 35 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये होगी।

उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड है, इसलिये प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योग को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यात पर परिवहन की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत की परिवहन सब्सिडी दी जायेगी। परिवहन की यह लागत प्रदेश में विनिर्माण/ उत्पादन के स्थान से आयातक देश के बंदरगाह तक होगी। वहीं प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा पांच करोड़ पर होगी।

नयी यूपी खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग नीति–2023 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगाने वाले स्थान पर अगर चक रोड आती है तो अब सर्किल रेट पर 25 प्रतिशत की धनराशि नहीं देनी होगी। पहले इसके लिए निवेशक को चक रोड की भूमि के बराबर दूसरी जगह भूमि देने के साथ उस भूमि के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि देनी होती थी। कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमी से कृषि भूमि पर 20 प्रतिशत सर्किल रेट वसूल कर सीएलयू (कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज) दिया जाता था, लेकिन अब इस पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर प्राधिकरण द्वारा बाहरी विकास शुल्क वसूला जाता था, जो ज्यादातर मामलों में भूमि के रेट से ज्यादा हो जाता था। ऐसे में अब प्रदेश में

ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर बाहरी विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट देने की कार्य योजना तैयार की गयी है। वहीं उद्योग लगाने के लिए स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से बजट के माध्यम से इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके साथ ही प्रसंस्करण के लिए दूसरे राज्य से लाये गये कृषि उत्पादों पर अब मंडी शुल्क और सेस में छूट दी जायेगी, क्योंकि दूसरे राज्य से लाये गये कृषि उत्पाद से प्रदेश में प्रसंस्करण के बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और राजस्व कर भी ज्यादा आयेगा। कहा जा सकता है कि योगी सरकार की यह नीति जहां कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने में कारगर साबित होगी, वहीं इसके जरिये हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही नीति में किये गये आकर्षक प्रावधानों और सब्सिडी के चलते बड़े पैमाने पर लोग इस क्षेत्र में आगे आयेंगे। ▪

मो. : 9935595471

युवाओं और रोजगार पर पूरा फोकस

–जितेन्द्र शुक्ला

इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। साफ है कि तो यहां युवा भी अन्य राज्यों से अधिक होंगे। ऐसे में इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से भिज्ञ हैं कि यहां के युवाओं को पहले शिक्षा और फिर रोजगार की आवश्यकता है। उनका मानना है कि शिक्षित युवाओं को अपने ही सूबे में रोजगार के अवसर मिल जाये तो उसे पलायन नहीं करना पड़ेगा। वहीं यदि कोई युवा किन्हीं कारणोंवश अशिक्षित रह गया तो कम से कम उसके भीतर जो हुनर, योग्यता है उसे कौशल विकास योजना के माध्यम से धार दी जाये ताकि प्रदेश की युवा ऊर्जा का लाभ सूबे को ही मिले और प्रतिभा पलायन न हो। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 के आयोजन की योजना और फिर निवेश के प्रस्ताव आने तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना फोकस भटकने नहीं दिया। प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश आये ताकि प्रदेश और देश का भविष्य बेहतर बन सके। वहीं यह भी कोशिश की कि जो आज युवा हैं उन्हें अपने ही जिले नही तो कम से कम अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। मुख्यमंत्री योगी की इसी सोच और उनकी टीम के अथक प्रयासों से ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सूबे को 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 19058 एमओयू के जरिए रोजगार के 93,82,607 अवसर भी यूपी के युवाओं के लिए सृजित होंगे। इनमें से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें 2,57,922 करोड़ के निवेश होंगे, जिसके जरिए 7.82 लाख से अधिक युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होकर उत्तम प्रदेश के विकास में भागीदार होंगे।

जीआईएस में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2,57,922 करोड़ के प्रस्ताव यूपी सरकार को मिले हैं, जो कुल निवेश का 8.92 फीसदी है। इन्हें धरातल पर उतारने की कार्ययोजना प्रारंभ हो गई है। इसके जमीं पर उतरते ही जहां युवाओं को शिक्षा के नए केंद्र मिलेंगे, वहीं इनके लिए सात लाख 82 हजार 528 अवसर रोजगार के पैदा होंगे। यानी योगी सरकार शिक्षा के साथ रोजगार को भी जोड़ने के संकल्प को पूरा करने के प्रयास को अमलीजामा पहनाएगी। यह योगी सरकार की सोच का ही नतीजा है कि जिस यूपी की बेरोजगारी दर जून 2016 के आसपास लगभग 18 फीसदी थी, उसी यूपी में फरवरी 2022 तक यह दर घटकर लगभग दो प्रतिशत रह गई है। यूपी की विशाल युवा आबादी को योगी आदित्यनाथ अपनी पूंजी मानते हैं। इनके लिए रोजगार सृजित कर अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। बेरोजगारी दर को भी शून्य पर लाकर योगी सरकार हर युवाओं का काम और काम को पूरा दाम देना चाहती है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में युवा उड़ान भरें, इसके लिए पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड समेत हर क्षेत्र में समान रूप से कार्य को गति प्रदान की जा रही है। यूपी की समृद्धि में कई नामचीन संस्थाएं भी सारथी बनने को उत्सुक हैं। सबसे अधिक युवाओं वाले यूपी में कानून का राज स्थापित

होना ही यहां निवेश का सबसे बड़ा पैमाना है। युनाइटेड स्टेट्स की इंपीरिया इनोवेशन इनवेस्टमेंट (ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप) ही नोएडा और लखीमपुर खीरी में निवेश कर 1.10 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ना चाहती है। पं. वासुदेव तिवारी स्किल यूनिवर्सिटी भी झांसी में 40 हजार करोड़ का निवेश करने को उत्सुक है। कभी पिछड़ेपन की पहचान बने बुंदेलखंड के 5000 से अधिक युवा सिर्फ एक ही संस्था के जरिए रोजगार के नए अवसरों से जुड़ेंगे। वहीं आरपीएम ग्रुप भी आरपीएम विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। समूह के निदेशक अजय शाही ने बताया कि सबसे अधिक युवा यूपी में हैं। हमारा यूपी सबसे आगे रहे, मुख्यमंत्री की इस सोच को सार्थक करने के लिए हमें अनुकूल माहौल मिल रहा, लिहाजा हम भी 500 करोड़ का निवेश कर रोजगार के 1200 अवसर भी मुहैया कराने को प्रतिबद्ध हैं।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले चार साल में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का खाका भी तैयार कर रखा है। इसके लिए यूपी शिक्षा का नया केंद्र बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार 'मिशन रोजगार' अभियान चला रही है, जिसके तहत अगले तीन–चार साल में दो करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। बीते दिनों राजधानी लखनऊ में हुए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय 'लखनऊ कौशल महोत्सव' में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का कौशल विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। उनकी सरकार ने ''सीएम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग'' शुरू की है और इससे प्रदेश के साढ़े सात लाख युवाओं को लाभ होगा।'' यह भी कहा कि, ''विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले युवाओं को अप्रेंटिसशिप योजना के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान देंगे। उनको हम अनुभवजन्य कार्य और नये प्रशिक्षण के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे।'' सीएम योगी ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की घोषणा की थी तो लोगों को यह लगता था कि यह मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक नई उड़ान, पहचान और मंच दिया ह।'' उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले छह साल में 16 लाख युवाओं का पीएम कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और श्रम एवं सेवायोजन के माध्यम से कौशल विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ''अब हमारे युवा को पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसे उसके गांव और उसके जिले में रोजगार प्राप्त होगा। इससे प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।'' उन्होंने कहा, ''प्रदेश सरकार 'एक फैमली एक आई कार्ड' (एक परिवार–एक पहचान पत्र) शुरू करने जा रही है और इसके माध्यम से हम प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं। इससे हम एक क्लिक पर जान लेंगे कि शासन की कौन सी योजना और रोजगार किस परिवार को नहीं मिला है और उसे वह उपलब्ध कराएंगे।''

योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 'हर हाथ को रोजगार' इस मूल मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी का संकल्प है कि चाहे स्वरोजगार हो या नौकरी, कम से कम हर परिवार के पास आय के साधन होने चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि हर किसी को सरकारी या प्राइवेट नौकरी दे पाना संभव नहीं है इसलिए स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं में आकर्षण पैदा हो इसी सोच के साथ योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरूआत की है।

योगी सरकार युवाओं के उद्यमी बनने की राह को और आसान बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। अब प्रदेश के युवा उद्यमी बनकर दूसरे लोगों को रोजगार दे सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत को 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की तैयारी है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी ने अपने पहले कार्यकाल में साल 2018 में की थी। इससे युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। दरअसल, योगी सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में हर परिवार से एक व्यक्ति को

रोजगार देने का है। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में नंबर एक बने। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार करने के इच्छुक युवाओं की सहायता का दायरा बड़ा किया जा रहा है। परियोजना लागत को बढ़ाकर 25 लाख से एक करोड़ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इसे 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया है। परियोजना लागत बढ़ने से युवाओं को स्वरोजगार करने में आसानी होगी और पैसे की कमी नहीं होगी। साथ ही ज्यादा संख्या में रोजगार का सृजन होगा. इस योजना का लाभ पाने वाले युवा खुद तो उद्यमी बनेंगे ही, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे।

योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 'हर हाथ को रोजगार' इस मूल मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी का संकल्प है कि चाहे स्वरोजगार हो या नौकरी, कम से कम हर परिवार के पास आय के साधन होने चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि हर किसी को सरकारी या प्राइवेट नौकरी दे पाना संभव नहीं है इसलिए स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं में आकर्षण पैदा हो इसी सोच के साथ योगी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत गरीब तबके से जुड़े कुम्हार, नाई, मोची जैसे कामगार शामिल होंगे। सरकार इनके हुनर को नई प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर और मशीने देकर बैंक से लोन भी कराने में मदद करेगी। जिससे कि ये अपना और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकें। "उद्यम सारथी ऐप" भी एमएसएमई विभाग ने बनाया है जिसको फोन पर डाउनलोड करके सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। इसके तहत जो बच्चे प्रशिक्षण क्लास लेंगे उनको संस्था से प्रमाण पत्र के अलावा बैंक लिंकेज से लेकर उद्यम स्थापित करने तक अन्य सारी मदद भी हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ओडीओपी योजना के जरिए हमारा लक्ष्य है कि अगले पांच सालों में निर्यात और रोजगार के अवसरों को दोगुना करें, विभाग उसी दिशा में काम कर रहा है।

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के साथ बीते वित्तीय वर्ष में रोजगार के आंकड़ों का लेखा जोखा भी पेश किया। बताया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम

स्थान प्राप्त किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81.283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। एमएसएमई अधिनियम, 2020 के माध्यम से इकाईयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति, लाइसेन्स, अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन करने की व्यवस्था की गयी है जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022–2023 में 24 नवम्बर तक 03 लाख 95 हजार से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये जिसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक रोजगार का सृजन हुआ।

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के साथ बीते वित्तीय वर्ष में रोजगार के आंकड़ों का लेखा जोखा भी पेश किया। बताया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022 2023 में अब तक लगभग 01 लाख 07 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81. 283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड प्रदान करते हुये 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है।

वहीं एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 01 लाख 35 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से अधिक हस्तशिल्पियों–पारम्परिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण किया गया। यह भी साफ किया गया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 01 लाख 73 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17.147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 01 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उधर, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 06 वर्षों में 12 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुये युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 01 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88.808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति–2022 के अंतर्गत अगले 05 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया। ▪

मो. : 9415158902

उ.प्र. का सलखन फॉसिल जीवाश्म पार्क भू-वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल

—केवल राम

धरती पर जीवों की उत्पत्ति का रहस्य समेटे हुए दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क प्रदेश के जनपद सोनभद्र के सलखन ग्राम पंचायत में स्थित है। यह इस तरह का जीवाश्म धरती पर एक रहस्य है, जिसपर दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। यह सलखन जीवाश्म पार्क 150 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म की एक श्रृंखला है। यह पार्क दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है, जो 25 हे. में फैला हुआ है और अमेरिका के एलोस्टोन पार्क से भी बड़ा है।

यहां के फॉसिल्स का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह जीवन की शुरूआत की कहानी समेटे हुए है। सलखन जीवाश्म पार्क एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहां जाकर पृथ्वी के भूवैज्ञानिक एवं जैविक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जीवाश्म पार्क पृथ्वी पर जीवन के विकास के आरम्भिक अवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहां पाये जाने वाले जीवाश्म विश्व के प्राचीनतम जीवाश्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस जीवाश्म पार्क के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसे इको पर्यटन से जोड़कर देश–विदेश के सैलानियों को यहां आकर्षित करने की योजना तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर्यटन सेक्टर में राजस्व अर्जन एवं रोजगार की असीमित संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की नीति पर काम कर रहे हैं।

इसलिए सलखन जीवाश्म पार्क भारत के लिए नहीं अपितु दुनिया के लिए भी एक बहुमूल्य भूवैज्ञानिक धरोहर है। इसके साथ ही मानव समुदाय के लिए एक नायाब तोहफा है। सलखन जीवाश्म पार्क सोनभद्र जिले के कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर

स्थित है। यह सेंचुरी राबर्ट्सगंज से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनभद्र जनपद पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण जनपद है। यहां पुरातात्विक विकास की असीम सम्भावनाएं हैं।

इस पार्क को अनमोल भू–वैज्ञानिक धरोहर से प्रकृति ने समृद्ध बनाया है। 150 करोड़ वर्ष पूर्व यहां समुद्र की लहरें हिलोरें मारा करती थीं। इस तथ्य के प्रकाश में आने के बाद सोनभद्र की संस्कृति भी 1.5 अरब वर्ष प्राचीन हो गई है। सलखन में लाइम स्टोन स्तम्भ एवं दुर्लभ दृश्य हैं, जिसके ऊपरी सतह पर अंकित गोल छल्ले जैसी आकृतियां वाली लगभग एक मीटर ऊँची संरचनाएं हैं, जो 1.5 अरब वर्ष पुराने जीवन आदि के प्रमाण हैं।

स्थानीय लोगों में पत्थर के फूल या पेड़ कहे जाने वाली संरचनाएं पृथ्वी पर सिएनोबैक्टीरिया द्वारा बनायी गयी हैं। 07 दिसम्बर, 2002 को 50 देशों के भू–वैज्ञानिकों ने यहां भ्रमण किया था और इसे पूरे विश्व का सबसे पुराना बहुमूल्य जीवाश्म पार्क बताया था। 1933 में इसकी खोज जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया ने की थी। कनाडा के मशहूर भू–वैज्ञानिक एच.जे. हॉफमैन इसे देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था कि इससे स्पष्ट और खूबसूरत जीवाश्म दुनिया में कहीं नहीं है। अमेरिकी सरकार ने पर्यटन के जरिए से अपने एलोस्टोन पार्क को विकसित किया है। इस पार्क के माध्यम से राजस्व अर्जन हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोग जुड़े हुए हैं।

इस जीवाश्म पार्क के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार इसे इको पर्यटन से जोड़कर देश–विदेश के सैलानियों को यहां आकर्षित करने की योजना तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर्यटन सेक्टर में राजस्व अर्जन एवं रोजगार की असीमित संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की नीति पर काम कर रहे हैं। पर्यटन सेक्टर में निवेशकों की रूचि को देखते हुए भविष्य में यह सेक्टर सेवा क्षेत्र समेत होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी आदि के लिए फायदेमंद साबित होगा।

सलखन जीवाश्म पार्क के अलावा सोनभद्र के आसपास मिर्जापुर एवं नजदीक के अन्य जनपदों में प्राकृतिक सुरम्य पर्यटन स्थल हैं। इसको पर्यटन के रूप में विकसित कर जल प्रपातों के आसपास बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। ईको पर्यटन बोर्ड का गठन इसलिए किया गया है कि जिसके तहत प्राकृतिक धरोहरों को बिना क्षति पहुँचाए इको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण, प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। ▪

मो. : 9415080727

बेसिक शिक्षा में नवाचारों को प्रोत्साहन

–अंजु अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत कर युगानुकूल बनाने की पहल माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बेसिक शिक्षा में तीव्रगति से की है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अकल्पनीय, अद्वितीय, अनुपम और अनुकरणीय कायाकल्प से प्रतिमान बनने की राह खुली है, कल तक छात्रों का टोटा था आज सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जा रहे है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा और शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ वर्तमान सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की उपलब्धता सुनिश्चित की है। छात्र–छात्राओं को लैपटॉप–टैबलेट्स भी उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। बच्चों को टेक्नोलॉजी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। हमारे देश के कल का भविष्य आज के युग, टेक्नोलॉजी के युग में अपने व्यतित्व का विकास कर सके। विकास के नये प्रतिमान गढ़ उत्तर प्रदेश के घर–घर तक टेक्नॉलोजी पहुंच चुकी है छोटी उम्र में ही बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं इसलिए यह प्रयास है कि बच्चों को बेहतर ज्ञान प्रदान करते हुए टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास प्राथमिक शिक्षा अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन का वायस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को मोटीवेशन एवं डायरेक्शन की जरूरत पर सम्यक विचार कर सकें। बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है उसको पहले से ही उसी फील्ड के लिए तैयारी कराई जाए जिससे बच्चा अपने उस फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करें और अपना नाम रोशन कर सके। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रयास भी किए जा रहे हैं लेकिन इस दिशा में और अधिक प्रयास करने हेतु मनन चिन्तन के लिए राज्य स्तर पर इस पहली बृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया है। डायट के द्वारा शैक्षिक नवाचार महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम किया।

उ.प्र. के मा. मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देशन में बेसिक शिक्षा में निरन्तर सुधारात्मक कार्य किये जा रहे है। सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिये इस कार्यशाला के मंथन में प्राप्त अनुभूति–स्फुरण, कार्यतत्परता एवं अवसरानुकूलता से लक्ष्य को पूरा करने के लिये सकारात्मक दिशा प्राप्त हुई है। शिक्षक एवं शिक्षकाओं का बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सकारात्मक सोच रखते हुये बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

सबका यही प्रयास है कि निपुण उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य को समय से पूरा किया जाए। विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता सम्बर्धन हेतु शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों का नवाचार पर उन्मुखीकरण किया जा रहा है। नवाचार का सम्बन्ध नवीन तकनीकी एवं नवीन ज्ञान से होता है। बदलती परिस्थितियों के साथ शिक्षण प्रक्रिया तथा बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने एवं विद्यालय को आनन्दशाला में परिवर्तित करने के लिए शिक्षकों में नवाचार की समझ होना तथा सतत् रूप से परिवर्तन शील समय में नवाचार किया जाना आवश्यक है। नवाचारों के माध्यम से स्कूल के वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाया जा रहा है। शिक्षक को प्रेरित किया जा है कि सीमित संसाधनों तथा विपरीत परिस्थितियों में भी इस प्रकार के कार्य कर सकता है, जिससे बच्चों के सीखने–सिखाने की लगन उत्पन्न करें। विद्यालय स्तर पर बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने एवं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनायें।

उ.प्र. के मा. मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देशन में बेसिक शिक्षा में निरन्तर सुधारात्मक कार्य किये जा रहे है। सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिये इस कार्यशाला के मंथन में प्राप्त अनुभूति–स्फुरण, कार्यतत्परता एवं अवसरानुकूलता से लक्ष्य को पूरा करने के लिये सकारात्मक दिशा प्राप्त हुई है। शिक्षक एवं शिक्षकाओं का बच्चों के साथ बेहतर व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सकारात्मक सोच रखते हुये बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाये। शिक्षक बच्चों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में होता है। शिक्षक एवं शिक्षिकायें बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये जो भी नई–नई जानकारी

प्राप्त करें। एस.सी.ई.आर.टी. के नेतृत्व में कई डायटस बेहतर कार्य कर रहे है। 05 डायटस को सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स के रूप में विकसित किये जा रहे है। कक्षा 6, 7, 8 की गणित विषय की शिक्षक संदर्शिका (उपचारात्मक शिक्षण हेतु) रिमीडियल शिक्षण हेतु तथा बच्चों के लिए उपचारात्मक कार्यपुस्तिका 'मेरी प्यारी गणित' का विमोचन किया जा चुका है। यह शिक्षक संदर्शिकायें शिक्षकों को गणित विषय की नई–नई विधियों से पढ़ाने एवं कार्यपुस्तिकायें बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगी। इसके गणित विषय के प्रति बच्चों की रूचि को बढ़ायी जा सकेगी। A Handbook on English Grammer For Teachers का विमोचन किया। कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों हेतु तैयार की गयी अंग्रेजी ग्रामर की यह पुस्तिका शिक्षकों को अंग्रेजी शिक्षण में मदद करेगी।शिक्षक अपने–अपने संस्थानों में बेहतर ढंग से लागू कराये जिससे छात्र–छात्राओं को बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। मोटीवेशन सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक छात्रों की शिक्षा का नींव होता है, शिक्षक ही बच्चों के भविष्य को बनाने का कार्य करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य को मेहनत एवं ईमानदारी से करना चाहिए। शिक्षक छात्र को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करे जिससे छात्र शिक्षक का नाम जहाँ जाये वही चर्चा करे। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता–पिता के बाद शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। डायट के द्वारा जो सामाग्री दी जाती है उसका अध्ययन शिक्षकों को करना चाहिये उसके बाद शिक्षक बच्चों को सही ढंग से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करे। डायटस का रोल ऐसे शिक्षकों को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने–अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करके भविष्य के लिए अच्छा नागरिक बना पाते है।

उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ''किशोर स्वास्थ्य क्लब'' का होगा गठन

किशोर एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ किशोर ही समाज व परिवार में दायित्वों का वहन कर स्वस्थ परिवार व समाज की नींव डालते हैं। किशोरों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत् और समावेशी विकास में योगदान कर सकें। किशोर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता

एवं गुणवत्ता हेतु प्रदेश संरकार गंभीर व कृत संकल्प है। इस दिशा में उत्तरदायित्वपूर्ण पहल के रुप में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाता है, जिसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के समस्त किशोर/किशोरियां शामिल हैं। किशोर वय के स्कूल जाने वाले वर्ग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के समन्वय से प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य क्लब गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य क्लबों के माध्यम से समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी एवं स्वस्थ व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियाँ आयोजित कर शिक्षक, छात्रों एवं हेल्थ वालिंटयर्स संदेशवाहकों में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का संवर्ग विकसित किया जाना है ताकि लैंगिक समानता और जीवन कौशल पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सफलता मिल सके।

प्रत्येक विद्यालय में गठित होने वाले क्लब में कम्युनिटी हेल्थ आफिसर को मुख्य संरक्षक घोषित कर प्रधानाचार्य को क्लब संरक्षक, दो अध्यापक (एक महिला और एक पुरुष) हेल्थ ब्रिगेडियर, प्रत्येक कक्षा से दो छात्र (एक बालक और एक बालिका) हेल्थ कैप्टन और एन.एस.एस., नेहरू युवा केंद्र, स्काउट एंड गाइड्स एवं एन.सी.सी. के छात्र/छात्रा को भी हेल्थ कैप्टन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ ब्रिगेडियर के द्वारा विद्यालय में साप्ताहिक रूप से क्लब में स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जाना है। साथ ही, सदस्यों का अभिमुखीकरण, प्रश्नोत्तरी, खेल, वाद–विवाद, पोस्टर/चित्रकारी प्रतियोगिता, रंगोली, मेंहदी, स्लोगन, सुलेख, योग नैतिक शिक्षा, मोबाइल–इंटरनेट सम्बन्धी उपयोगिता के सुरक्षित तरीकों के सबंध में गतिविधियाँ संपादित कराई जायेंगी। प्रत्येक स्कूल में छात्रों की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों के समाधान हेतु ''प्रश्न पेटिका'' भी लगाई जाएगी ताकि झिझक न महसूस हो। किशोर स्वास्थ्य क्लब का संचालन एवं नेतृत्व का पूर्ण दायित्व शिक्षा विभाग द्वारा निर्वहन किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग सहयोगी की भूमिका में रहते हुए समस्त प्रकार की आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं सामग्री उपलब्ध कराएगा। बेसिक शिक्षा विभाग से कार्यक्रम नोडल अधिकारी के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग से जनपदीय आर.के.एस.के. नोडल अधिकारी होंगे।

विद्यालय में संचालित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम जैसे– साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान, किशोरी सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य मंच, किशोर स्वास्थ्य दिवस, हैण्ड वाशिंग डे, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, मीना मंच एवं बाल संसद की गतिविधियाँ इस हेल्थ क्लब के माध्यम से संचालित की जायेंगी। विद्यालय स्तर से ही छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति संवेदित करने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त पूर्व माध्यमिक एवं इण्टर कॉलेजों में स्कूल हेल्थ क्लब का गठन किये जाने की योजना है। विद्यालयों में छात्रों के बीच विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य कि विभिन्न विषयों पर रोचक एवं मनोरंजक तरीके से छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किये जाने का उद्देश्य है। प्रथम चरण में समस्त विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान किये जा रहे हैं। ■

मो. : 8787093085

विद्यालय में संचालित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम जैसे– साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सम्पूरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान, किशोरी सुरक्षा योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य मंच, किशोर स्वास्थ्य दिवस, हैण्ड वाशिंग डे, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम, मीना मंच एवं बाल संसद की गतिविधियाँ इस हेल्थ क्लब के माध्यम से संचालित की जायेंगी। विद्यालय स्तर से ही छात्र–छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति संवेदित करने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त पूर्व माध्यमिक एवं इण्टर कॉलेजों में स्कूल हेल्थ क्लब का गठन किये जाने की योजना है।

खेलेगा यूपी, तेजी से आगे बढ़ेगा यूपी

—राजीव ओझा

कोस–कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, हर जिले को स्टेडियम मिल रहा, योगी सरकार ने बदली खिलाड़ियों की जिंदगानी। जी हां यह सच है, यूपी सरकार ने पिछले छह वर्षों में खेल के आधारभूत ढांचे को जिस तरह मजबूत किया है, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। खेल और खिलाड़ी दोनों की सूरत बदल गई। अब योगी सरकार की नई खेल नीति, प्रदेश में युवा खिलाड़ियों को नई ऊंचाई प्रदान करेगी, उन्हें प्रोत्साहित करेगी। व्यक्तित्व विकास में जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही महत्व खेलों का भी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही शिक्षार्जन का लाभ उठा सकता है। खेलों को जीवन से जोड़ने की जरूरत को समझते हुए योगी सरकार ने नई खेल नीति लागू की है। न लच्छेदार बातें न कोई झूठे वादे, योगी सरकार में जो कहा जाता वह किया जाता। सरकार के लिए हर वो काम प्राथमिकता सूची में ऊपर है जिसका सरोकार आम जनता से है। योगी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं। इसी क्रम में यूपी में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति विकसित करने के लिए राज्य की पहली खेलनीति– 2023 को योगी सरकार ने हरी झण्डी दे दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही नए संस्थानों का गठन, प्राइवेट एकेडमी और स्कूल–कॉलेज को भी खेलों से जोड़ने के लिए अहम प्रावधान

विकास को गति देने में स्वस्थ युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए योगी सरकार खेल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बेटियों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल करियर बेटियों में आत्मविश्वास जगाने और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में यूपी की बेटियां शानदार प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर कर रहीं हैं।

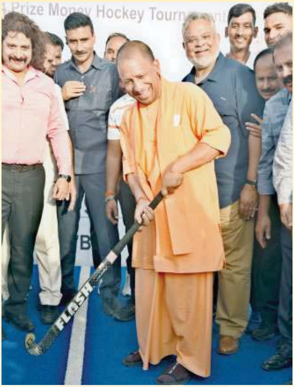

किए गए हैं। खास बात ये है कि विभिन्न राज्यों की खेल नीतियों का अध्ययन करने के बाद उसकी अच्छे प्रावधानों को प्रदेश सरकार ने खेल नीति 2023 में समाहित किया है। ध्यान देने वाली बात है कि खेल सुविधाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को प्रेरित–प्रोत्साहित करने के लिए जो खेल नीति बनी है उसे सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि व्यावहारिकता को ध्यान में रख बनाया गया है और लागू किया जा रहा है।

योगी सरकार युवाओं में खेल के प्रति रूचि जगाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग, खेल के प्रति उनकी रूचि जगाकर आसानी से किया जा सकता है। युवाओं की ऊर्जा के सदुपयोग का मतलब है उनके लिए ख्याति भी, करियर भी और कमाई भी। कहावत है आप जैसा बोयेंगे वैसा काटेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वस्थ नई पीढ़ी की पौध तैयार करने में जुटे हैं। यही युवा उत्तर प्रदेश का भविष्य हैं और खेल इन्हें संवारने का महत्वपूर्ण माध्यम है। योगी सरकार का नजरिया बिल्कुल साफ है। उन्हें पता है कि खेलेगा इंडिया की तर्ज पर खेलेगा यूपी तो बढ़ेगा यूपी और बढेगा यूपी तो बढेगा इंडिया। युवाओं का तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ और स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है। विकास को गति देने में स्वस्थ युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए योगी सरकार खेल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बेटियों को खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेल करियर बेटियों में आत्मविश्वास जगाने और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। क्रिकेट, हॉकी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में यूपी की बेटियां शानदार प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार पर कर रहीं हैं।

जैसा कि आप जानते हैं योगी सरकार के पहले कार्यकाल के सबसे सफल योजनाओं में एक थी ओडीओपी, यानी एक जिला एक उत्पाद। इस योजना से छोटे व्यापारियों को भी अच्छा लाभ मिला। अब योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इसी तर्ज पर एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की

है। इस योजना का नाम है एक जिला एक खेल योजना। जिसमें हर जिले की पहचान उस जिले के खेल से होगी। जिसके तहत ग्रामीण और क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा दिया जायेगा और युवाओं का उस खेल के प्रति रुझान बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल (ODOS) योजना शुरू की है। यूपी में सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल खेल और खिलाड़ियों के लिए खास है। अपनी तरह की पहली योजना 'एक जिला एक खेल' (one district one sports) का उद्देश्य प्रदेश में सभी पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाना भी है।

सरकार ने पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 'एक जिला, एक खेल' (ओडीओएस) योजना में शामिल किए गए 10 जिलों के खेल में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव केन्द्र की सहमति के बाद किया गया है। इन जिलों में आधुनिक खेलों के स्थान पर कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है।

यूपी में खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को अब एक नयी योजना के जरिए प्रशिक्षण और मदद दी जाएगी। यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद इसी तर्ज पर 'एक जिला एक खेल' यानी one district one sport योजना मंजूरी की है। साथ ही यूपी के सभी जिलों के लिए एक–एक खेल विशेष भी तय कर दिया है. उसकी पूरी सूची खेल विभाग ने तैयार की है।

क्या है एक जिला एक खेल

योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ओडीओपी योजना काफी सफल रही। इसकी तर्ज पर अब एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। इसमें हर जिले के लिए एक खेल निर्धारित किया गया है। कुछ खेलों को एक से ज्यादा जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। जिस जिले के लिए जो खेल निर्धारित है उस जिले में उस खेल के प्रशिक्षण और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के लिए खेलों को बढ़ावा देना प्राथमिकता सूची में शामिल है। यूपी में खिलाड़ियों को किस तरह सबसे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, कैसी सुविधाएं दी जाएं जिससे उनकी प्रतिभा में निखार आए, इसके लिए भी लगातार प्रयास किये जा रहे।

जिलों में बनाया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर

सरकार की योजना है कि ऐसे सभी जिलों में उसी खेल के लिए ट्रेनिंग सेंटर होगा जो वहां ज्यादा खेला जाता हो। साथ ही खेल प्रतिभाओं को चिह्नित कर उनको ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। इसके लिए जिलों को एक–एक खेल से विशेष रूप से जोड़ा गया है। वहां उस खेल के लिए स्टेडियम और सेंटर भी निर्धारित कर दी गए हैं। इस योजना का उद्देश्य गांव और जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर उनको प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। इन खेलों में हॉकी, बैडमिंटन, टेबिल टेनिस, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, जूडो जैसे खेल हैं। जिलों में इनके लिए खेलो इंडिया सेंटर भी बनाए जाएंगे।

योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में परम्परागत और ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही गांव में फिटनेस सेंटर और जिमनेजियम भी बनाए थे। वहीं युवक मंगल दल को भी सक्रिय किया था। इस योजना का उद्देश्य इन सभी खेलों से जुड़ी प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें मौका देना है।

- योगी सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण बनाने का फैसला किया है।
- नई खेल नीति में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 5 हाई परफॉरमेंस सेंटर बनाए जाने की योजना है।
- राज्य खेल प्राधिकरण में विभिन्न खेलो में खिलाड़ियों की दक्षता विकसित की जाएगी।
- हाई परफॉरमेंस सेंटर में खिलाड़ियों की फिटनेस को सुधारा जाएगा।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में केवल एक खेल को शामिल करके उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकेगा।
- योगी सरकार की नई खेल नीति में खेल विकास कोष की स्थापना और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य बीमा का भी प्रावधान है। इसके तहत 10 करोड़ की धनराशि से खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इस फंड के जरिए कमजोर खिलाड़ियों और खेल अकादमी को मदद दी जाएगी।
- प्रत्येक रजिस्टर्ड खिलाड़ी को राज्य सरकार की तरफ से ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा।
- एकलव्य क्रीड़ा कोष के माध्यम से खेल प्रतियोगिता के दौरान घायल हुए खिलाड़ियों के इलाज के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- नई खेल नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है की जमीनी स्तर पर इसे लागू किया जाए जिससे कि ट्रेनिंग का स्तर सुधरे।
- खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं।
- पहली श्रेणी में जमीनी स्तर के खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे।
- दूसरी श्रेणी में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित कर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर तैयार किया जाएगा।
- तीसरी श्रेणी में उच्च स्तर की खिलाड़ी आएंगे यानी

जो स्थापित खिलाड़ियों और विभिन्न खेलों में राज्य प्रतिनिधित्व करते हो ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

- हर जिले में एक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिलाओं और पैरा खेलने पर विशेष ध्यान।
- स्थानीय और स्वदेशी खेलो को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- खेल पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में भी प्रयास किया जाएगा
- खेल उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- खेल छात्रावासों में प्रवेश के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों की कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फिटनेस एक्सपर्ट, डाईट एक्सपोर्ट की नियुक्ति होगी।
- स्कूलों में विभिन्न खेलों के विकास के लिए खेल नर्सरी या एकेडमी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

नई खेल नीति में एक जिला एक खेल योजना में शामिल 10 जिलों के खेल में बदलाव किया गया है। ओडीओएस योजना में जिलों के लिए खेल का निर्धारण कर दिया गया है।

सरकार ने पारंपरिक खेलों को प्रोस्तसाहित करने के लिए 'एक जिला, एक खेल' (ओडीओएस) योजना में शामिल किए गए 10 जिलों के खेल में बदलाव कर दिया गया है। यह बदलाव केन्द्र की सहमति के बाद किया गया है। इन जिलों में आधुनिक खेलों के स्थान पर कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है।

जिन 10 जिलों के खेल बदले गए हैं, उनमें मथुरा में जूडो की जगह कुश्ती, बलिया, आंबेडकर नगर, कानपुर देहात एवं फतेहपुर में बैडमिंटन की जगह एथलेटिक्स, बहराइच में बैडमिंटन की जगह फुटबाल, श्रावस्ती में बैडमिंटन की जगह कबड्डी, झांसी, गोंडा एवं लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन की जगह हॉकी को एक जिला एक खेल घोषित किया गया है। अब इसके आधार पर ही इन 10 जिलों में खिलाड़ियों केचयन और उन्हें प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके आलावा शुरुआत में ओडीओएस योजना में 67 जिलों के लिए खेल का निर्धारण कर दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के खेल प्रतिभा को निखारने के लिए खेल यूनिवर्सल नियम 'कैच देम यंग' के आधार पर अलग–अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय खेल से जुड़ी प्रतिभाओं की सही उम्र में पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

खेलों में बेटियों को विशेष रूप से बढ़ावा

योगी सरकार खेल के क्षेत्र में बेटियों को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है। लड़कियों को टीमवर्क, आत्मनिर्भरता, लचीलापन और आत्मविश्वास सिखाकर लैंगिक समानता का सन्देश देना भी एक उद्देश्य है। खेल में महिलाएं लैंगिक रूढ़िवादिता और सामाजिक मानदंडों से ऊपर उठ कर प्रेरक रोल मॉडल बनाती हैं और यह सन्देश देती हैं कि महिलाएं, पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं।

योगी सरकार 2.0 महिला खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत खिलाड़ियों को पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

युवा और महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने की बात हो या फिर प्रदेश में खेल सुविधाओं में इजाफा करने की, सरकार ने शुरूआत से ही प्रदेश में बेहतर खेल सुविधाएं देने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। योगी सरकार में खेल जगत में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। महिला खिलाडियों को खेल जगत में प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार संकल्पबद्ध है। योगी सरकार ने बेटियों, युवाओं को खेल जगत में बढ़ावा देने के लिए कई स्वर्णिम योजनाओं का संचालन अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश में किया। योगी सरकार 2.0 में भी महिला खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए अपने संकल्प के साथ बढ़ रही है।

योगी सरकार 2.0 इस बार महिला खिलाड़ियों के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। जिसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अपने पिछले कार्यकाल में भी योगी सरकार ने महिला खिलाडियों को आर्थिक सहायता दी। प्रदेश के 19

जनपदों में 16 खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिलाड़ियों के लिए 44 छात्रावास की व्यवस्था संग 21 वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले 18 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ 60 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसके साथ ही 18 वें एशियन गेम्स में पदक विजेता 46 खिलाड़ियों को तीन करोड़ 90 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए गए। योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़े सकारात्मक बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

बर्मिंघम में चमके यूपी के सितारे

पिछले छह वर्षों में योगी सरकार ने प्रदेश में खेल स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए उसके सकारामक परिणाम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देखने को मिला है।

पिछले साल बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में चमके यूपी के आठ सितारे, इन खिलाड़ियों ने किया देश का नाम रोशन।

ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जो धाक जमाई उसमें यूपी के खिलाड़ियों ने चार चांद लगा दिए। पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी तो अन्नू रानी ने जैवलिन थ्रो में पदक जीत सुनहरे भविष्य की उम्मीदों को जगा दिया। उनके पदक का रंग जो भी रहा हो, मगर एथलेटिक्स में देश का रुतबा बढ़ाने में 'बड़ा' पदक साबित हुआ। जूडोका विजय यादव और पहलवान दिव्या काकरान ने मुश्किल परिस्थितियों से उबरते हुए पदक के साथ खुद को साबित किया तो पुरुष हॉकी में रजत और महिला हॉकी में देश को कांस्य पदक दिलाने में यूपी के खिलाड़ियों ललित उपाध्याय और वंदना कटारिया ने समां बांध दिया। वहीं क्रिकेट में सोना जीतने से बस कुछ पीछे रह गई टीम में यूपी की खिलाड़ियों दीप्ति शर्मा व मेघना सिंह ने अलग ही छाप छोड़ी।

2018 के गोल्डकोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों से तुलना करें तो 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी यूपी के हिस्से में सात पदक आए। मगर यह उपलब्धि इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि निशानेबाजी में लखनऊ के जीतू राई ने स्वर्ण व मेरठ के रवि कुमार ने कांस्य जीता। इस बार इन खेलों में निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया था।

प्रियंका गोस्वामी (मेरठ– 10 किमी वॉक– रजत पदक) : 10 किमी वॉक में भी स्टार वॉकर प्रियंका गोस्वामी का कोई जोड़ नहीं। पैदल चाल में अलग पहचान बनाने वाली प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल 10 किमी वॉक में सभी पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ओलंपिक और एशियन गेम्स में शामिल 20 किमी वॉक ही प्रियंका की मुख्य स्पर्धा है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में 10 किमी वॉक होने के कारण स्टार एथलीट ने पहली बार इसमें भाग लिया और कमाल का प्रदर्शन करते हुए

ओडीओएस योजना में शामिल जिलेवार खेल

कुश्ती– वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया व महराजगंज

एथलेटिक्स– मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली. बलिया और मुजफ्फरनगर।

हॉकी– प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद

टेबिल टेनिस– आगरा, कानपुर

बैडमिंटन– अलीगढ़ और गौतमबुद्ध नगर

भारोत्तोलन– मिर्जापुर और बिजनौर

बॉक्सिंग– बुलंदशहर और कुशीनगर

तीरंदाजी– सोनभद्र और ललितपुर

फुटबाल– हाथरस

तैराकी– पीलीभीत

शूटिंग– बांदा

कबड्डी– कन्नौज

लॉन टेनिस– प्रयागराज

43.38.83 मिनट का सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए रजत पदक पर कब्जा जमाया। बताते चले कि टोक्यो ओलंपिक में भी 20 किमी वॉक रेस के दौरान प्रियंका शुरुआती 12 किमी तक शीर्ष छह स्थान पर रही थी। वहीं से लगा कि कम दूरी वाली वॉक में बेहतर परिणाम सामने आ सकता है और बर्मिंघम में ठीक वैसा ही हुआ।

ललित उपाध्याय (वाराणसी– हॉकी– रजत पदक)

चांदी सी चमकी हॉकी टीम में यूपी के फारवर्ड ललित उपाध्याय का जलवा। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का चमकदार प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में भी जारी रहा। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम में वाराणसी के अनुभवी खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने मिडफील्ड और फारवर्ड के रूप में दोहरी भूमिका से पूरी तरह न्याय किया। छह मैचों में दो गोल करने वाले ललित का प्रदर्शन पूरी प्रतियोगिता के दौरान शानदार रहा।

क्रिकेट टीम रजत– दीप्ति शर्मा (आगरा) और मेघना सिंह (बिजनौर)

पहली बार शामिल महिला क्रिकेट में दिलाया रजत। इसमें यूपी की दीप्ति शर्मा व मेघना सिंह का खेल शनदार रहा। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार महिला क्रिकेट के टी–20 फारमेट को शामिल किया गया। इसमें भारतीय महिलाओं ने उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया। टीम में बतौर हरफनमौला खिलाड़ी शामिल अनुभवी दीप्ति शर्मा ने कुछ एक मौकों पर गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत में योगदान दिया। मेघना ने सभी छह मुकाबलों में टीम के आक्रमण की बागडोर संभाली।

विजय यादव (वाराणसी– जूडो– कांस्य पदक)

पदक दिलाने वालों की फेहरिस्त में यूपी के जूडोका विजय यादव भी शामिल थे। नेशनल चौंपियन बनने के बाद विजय यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य जीतकर यूपी का मान बढाया। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले जूडोका विजय यादव ने पहले जूनियर और फिर सीनियर वर्ग में पदक जीतकर चमक बिखेरी।

अन्नू रानी (मेरठ– भाला फेंक– कांस्य पदक)

अन्नू रानी ने 60 मीटर जैवलिन थ्रो कर दिलाया 'बड़ा' पदक। मेरठ की स्टार जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी ने 60 मीटर की दूरी नापते हुए जैवलिन थ्रो में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनने का गौरव हासिल किया।

दिव्या काकरान (मुजफ्फनगर– कुश्ती– कांस्य पदक)

राष्ट्रमंडल खेलों में महिला पहलवानों के चमकदार प्रदर्शन में यूपी की दिव्या काकरान का नाम भी शामिल रहा। मूल रूप से मुजफ्फरनगर की रहने वाली पहलवान का सामना पहले दौर में टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता नाइजीरिया की ब्लेसिंग से हो गया। जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ाए लेकिन ब्लेसिंग द्वारा स्वर्ण जीतने पर दिव्या को रेपचेस में मौका मिला। यहां दिव्या ने शानदार खेल दिखाया और अगले दोनों मुकाबले आसानी से जीतने हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।

वंदना कटारिया (मेरठ– हॉकी कांस्य)

बर्मिंघम में भारतीय महिला टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर भाग लेने गई वंदना कटारिया ने शानदार खेल दिखाया। फारवर्ड के रूप में वंदना ने टीम की अग्रिम पंक्ति की बेहतरीन ढंग से अगुवाई की, जिसकी बदौलत टीम 16 साल बाद कांस्य पदक जीतने में सफल रही। मेरठ की रहने वाली वंदना ने टीम से सभी छह मैच खेलकर चार गोल दागे।

बर्मिघम में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर

- **सीमा पुनिया (मेरठ)**– डिस्कस थ्रो में पांचवां स्थान
- **पूनम यादव (वाराणसी)**– वेटलिफ्टिंग (76 किग्रा) में कोई स्थान नहीं
- **पूर्णिमा पांडेय (वाराणसी)**– वेटलिफ्टिंग (87 किग्रा) में छठा स्थान
- **रोहित यादव (मिर्जापुर)**– भाला फेंक में छठा स्थान
- **सरिता सिंह (अमरोहा)**– हैमर थ्रो में 13वां स्थान

राष्टमंडल खेलों में प्रतिभाग और पदक विजेता के लिए यूपी सरकार की घोषणा (व्यक्तिगत और टीम वर्ग में समान राशि का प्रावधान)

प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को पांच लाख रुपये

- कांस्य जीतने पर 50 लाख रुपये
- रजत जीतने पर 75 लाख रुपये
- स्वर्ण जीतने पर डेढ़ करोड़ रुपये

प्रदेश में तेजी से बन रहे स्टेडियम

खेलो इंडिया के तहत प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से 37 नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में इन नए स्टेडियमों के निर्माण से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं इन युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं अपने ही प्रदेश में मिलेंगी। खेलो इंडिया योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया। 'खूब खेलो खूब पढ़ो' पखवाड़े में प्रदेश के 186 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खेल किट के लिए 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 की गई। प्रदेश के 18 खिलाड़ियों को 55 लाख 98 हजार रुपए की राशि दी गई। मेरठ में 'स्पोर्ट यूनिवर्सिटी' की स्थापना प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच देने की ओर सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

22वें कामनवेल्थ गेम्स के पदकधारी/प्रतिभाग करने वाले यूपी के इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया–

प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स रजत 75 लाख, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी रजत 75 लाख, मेघना सिंह क्रिकेट रजत 75 लाख, दीप्ति शर्मा क्रिकेट रजत 75 लाख, अन्नू रानी एथलेटिक्स कांस्य 50 लाख, दिव्या काकरान कुश्ती कांस्य 50 लाख, विजय कुमार यादव जूडो कांस्य 50 लाख, वंदना कटारिया हॉकी कांस्य 50 लाख, सीमा पुनिया एथलेटिक्स प्रतिभाग 5 लाख, सरिता रोमित सिंह एथलेटिक्स प्रतिभाग 5 लाख, रोहित यादव एथलेटिक्स प्रतिभाग 5 लाख, पूनम यादव भारोत्तोलन प्रतिभाग 5 लाख, पूर्णिमा पांडेय भारोत्तोलन प्रतिभाग 5 लाख, विश्वनाथ यादव ट्रायथलान प्रतिभाग 5 लाख।

डबल इंजन सरकार जिस तरह खेल और खिलाडियों को आगे बढाने की नीति पर काम कर रही है, उसे देखते हुए संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में विश्व खेल पटल पर भारत बुलंदियों पर होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। ■

मो. 8707587722

उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति का विकास

–रजनीश वैश्य

भारत एक युवा राष्ट्र है। युवा शक्ति भारत की पहचान है। फिर भी आजादी के बाद एक लम्बे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे। वर्ष 2014 से पहले खेल संसाधनों के अभाव में खेलों में भारत का प्रदर्शन साधारण रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा शक्ति की ऊर्जा को देश की प्रगति से जोड़ने का प्रयास किया। युवाओं को केंद्र में रखकर कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, मेक इन इंडिया अभियान, रोजगार सृजन कार्यक्रम व मुद्रा योजना प्रारंभ की गयीं। युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया। वर्ष 2014 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत गांव–गांव तक खेल गतिविधियों को प्रारंभ किया गया।

प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए राज्य की पहली खेल नीति को हरी झंडी दी गयी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। खेल नीति के लागू हो जाने से देश एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हासिल करेंगे तथा खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही 'राज्य खेल प्राधिकरण' का गठन भी किया जाएगा, जो भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की तर्ज पर काम करेगा।

खेलों में उत्तर प्रदेश की एक अलग ही पहचान रही है। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया, जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा। इसके बाद भी प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले खेल प्रोत्साहन सिर्फ कोरी बातें थीं। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थीं।

वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोडमैप तैयार किया। प्रदेश के युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और देश–प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों के सम्मान की परम्परा का श्रीगणेश भी प्रदेश में हुआ है।

प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास के लिए राज्य की पहली खेल नीति को हरी झंडी दी गयी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके तहत विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। खेल नीति के लागू हो

जाने से देश एवं राज्य के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण हासिल करेंगे तथा खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही 'राज्य खेल प्राधिकरण' का गठन भी किया जाएगा, जो भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की तर्ज पर काम करेगा।

नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशंस व खेल अकादमियों को आर्थिक मदद का प्रावधान भी रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इसका फायदा मिलेगा। सरकारी वित्तीय सहायता से एसोसिएशन और अकादमियां अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से राज्य में खेलों की सहायता के साथ–साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास का निर्णय लिया गया है।

राज्य में पीपीपी के तहत अलग–अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा पांच हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हाई परफारमेंस सेंटर से खिलाड़ियों को फिजिकल फिटनेस तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेगी, जिससे वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उच्च प्रदर्शन के लिए तैयार हो सकेंगे।

राज्य में खेलों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए से 'राज्य खेल विकास कोष' बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को खासा फायदा मिलेगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी तथा विदेशों में प्रदर्शन का मौका मिलेगा।

होनहार खिलाड़ी गांव से निकलें तथा प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से युवाओं में खेल के प्रति रुचि जागृत की जाएगी। उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में एक ओपन जिम और ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इसमें उन जिलों को प्राथमिकता से चुना जाएगा, जहां पर एक भी खेल स्टेडियम नहीं है।

खेल सुविधाओं से प्रदेश का कोई भी जिला अछूता नहीं रहे, इसके लिए एक जिला–एक खेल योजनान्तर्गत 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम, 132 खेल मैदान एवं 100 जिम की स्थापना की गयी है। पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों

> **कॉमनवेल्थ गेम्स–2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपये तथा 36वें नेशनल गेम्स के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गयी। बजट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।**

को प्रोत्साहित करने के लिए युवक मंगल दल गठित किए गए हैं। राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी विस्तृत तैयारियों के साथ किया जा रहा है। खिलाड़ियों के सपनों को पंख प्रदान करने तथा आर्थिक मुश्किलें से उनकी उड़ान न रूक सके, इस उद्देश्य से एकलव्य खेल क्रीड़ा कोष की स्थापना की गयी है। कोष से ट्रेनिंग कराने तथा प्रतियोगिता के दौरान चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। खिलाड़ियों का अपने खेल विधा से संबंधित आवश्यक उपकरण के लिए धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश सरकार ने बजट में खेल विकास कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस कोष से भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। खेल कोटा के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी की नौकरी प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।

खिलाड़ियों पर धनवर्षा

योगी सरकार ने ओलंपिक गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स के विजेताओं को पुरस्कृत करने की परम्परा का श्रीगणेश किया है। टोक्यो ओलम्पिक में पदक प्राप्त करने वाले देश के खिलाड़ियों और राज्यों के पदक विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपये व कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ओलंपिक टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपये व कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है।

एशियन गेम्स में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये तथा 75 लाख रुपये प्रदान किए गए। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स एवं विश्व चौम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता को क्रमशः 1.5 करोड़ रुपये तथा 75 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गयी। राज्य सरकार ओलंपिक गेम्स में प्रदेश से प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपये, एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 5–5 लाख रुपये प्रदान कर रही है।

कॉमनवेल्थ गेम्स–2022 में राज्य के पदक विजेता एवं

प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपये तथा 36वें नेशनल गेम्स के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गयी। बजट में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

खेल विश्वविद्यालय का निर्माण

मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जहां युवाओं को विभिन्न खेलों का विश्व स्तरीय शिक्षण–प्रशिक्षण मिलेगा। उन्हें भविष्य के विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। 700 करोड़ रुपये की लागत से 91.38 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित होने इस विश्वविद्यालय में युवाओं को खेल के साथ रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खेल, खेल विज्ञान तथा खेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण एवं शोध कार्य होगा और राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एण्ड एप्लाइड स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कोचिंग, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एण्ड मास मीडिया टेक्नोलॉजी, एडवेन्चर स्पोर्ट्स, बैचलर इन स्पोर्ट्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, परास्नातक, एमफिल तथा पीएचडी खेल विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकेगी। एथलेटिक्स, आउटडोर गेम्स, ट्रैक एंड फील्ड, शूटिंग रेंज, जैवलिन थ्रो, भारोत्तोलन, कुश्ती, बाक्सिंग तथा कायाकिंग रोविंग एंड राफ्टिंग की ट्रेनिंग यहां मिल सकेगी। पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम भी यह विश्वविद्यालय बनेगा।

विश्वविद्यालय में हाईटेक एवं मॉर्डन स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ खेल मैदान, स्विमिंग पूल व वेलोड्रोम साइक्लिंग ट्रैक स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड पर बनने वाले इस खेल विश्वविद्यालय को भारतीय पारम्परिक वास्तुकला के आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे यह पर्यावरण अनुकूल होने के साथ–साथ ऊर्जा कुशल भी होगा। मेरठ में विश्वविद्यालय के साथ ही सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है।

मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से खेल उत्पादों का निर्माण व्यापक रूप से किया जा रहा है। देश–दुनिया की खेल सामग्री के निर्माण का केंद्र मेरठ जनपद बन रहा है।

खेल–खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

- प्रत्येक जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना।
- ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम स्थापित।
- 1000 मंगल दलों का गठन।
- 132 खेल मैदान एवं 100 जिम की स्थापना।
- एकलव्य खेल क्रीड़ा कोष की स्थापना।
- खेल कोटा के तहत सरकारी नौकरी।
- ओलम्पिक पदक विजेताओं का सम्मान।
- नए खेल मैदानों का निर्माण।
- राजधानी के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में जी–20 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण। ■

मो. : 8840973541

अब खेल और खिलाड़ियों के लिए पहचाना जाएगा उत्तर प्रदेश

–सरिता त्रिपाठी

- निजी अकादमियों और स्कूल-कॉलेज को भी खेलों से जोड़ने के लिए किए गए उपाय।
- नई खेल नीति के अनुसार प्रदेश में होगी एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना।
- प्रदेश में बनाए जाएंगे एक-एक गेम पर आधारित 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
- 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनेंगे जहां उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान।

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में खेल कल्चर को बढ़ावा दे रही है। खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं से लेकर खिलाड़ियों, खेल संघों व निजी अकादमियों तक को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में योगी सरकार की मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दी गई है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही नए इंस्टीट्यूशंस का गठन, प्राइवेट एकेडमी और स्कूल–कॉलेज को भी खेलों से जोड़ने के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं। खास बात ये है कि विभिन्न राज्यों की खेल नीतियों का अध्ययन करने के बाद उसकी अच्छे प्रावधानों को प्रदेश सरकार ने खेल नीति 2023 में समाहित किया है। नई खेल नीति में एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का भी उल्लेख है।

खेल एसोसिएशन व अकादमियों को वित्तीय सहायता

नई नीति में विभिन्न खेल एसोसिएशन व खेल अकादमियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इसका फायदा मिलेगा। सरकार से मिलने वाली वित्तीय

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए बनेगी कमेटी

खेल नीति के अलावा भी मंत्रिपरिषद से खेलों से जुड़े कुछ और प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इनमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए विभिन्न कमेटियों को एक्टिवेट करने से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्टेडियम, ओपेन जिम, निर्माण, संचालन प्रबंधन के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। ताकि नयी पीढ़ी को सुविधाएं दी जाएं और होनहार खिलाड़ी गांव से निकलें और प्रदेश का नाम रोशन करें।

सहायता से ये एसोसिएशन और अकादमियां अवस्थापना तथा ट्रेनिंग सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगी और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को उसका लाभ दे सकेंगी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से राज्य में खेलों की सहायता के साथ–साथ खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास में भी सहयोग करेगी। प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जो एक–एक गेम पर आधारित होंगे। राज्य की सहायता के साथ इन्हें पीपीपी मॉडल पर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा नई खेल नीति में विभिन्न खेल सुविधाओं, कोच की मैपिंग का भी उल्लेख किया गया है।

राज्य खेल प्राधिकरण की होगी स्थापना

नई खेल नीति 2023 में एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह राज्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) की तर्ज पर काम करेगा, जहां विभिन्न खेलों की स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में खेल विकास कोष (स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड) बनाया जाएगा। इस फंड के माध्यम से कमजोर खिलाड़ियों, एसोसिएशन या अकादमी की मदद की जाएगी। यही नहीं, राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित किया जाएगा।

खिलाड़ियों का इलाज भी कराएगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की भी आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए सरकार ने नई खेल नीति 2023 में भी प्रावधान किया है। नीति के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष से खेल या प्रतियोगिता के दौरान

खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्धा कराएगी। उल्लेखनीय है कि खेलों के दौरान अक्सर खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। पैसे की कमी या इलाज में लापरवाही के चलते कई खिलाड़ी करियर के पीक पर ही रिटायर हो जाते हैं या खेल छोड़ देते हैं। ऐसे में अब सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

3 श्रेणियों में खिलाड़ियों का होगा प्रशिक्षण

खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें ट्रेन्ड किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी ग्रास रूट (जमीनी स्तर) के खिलाड़ी सम्मिलित होंगे। ये वो खिलाड़ी जिन्हें शुरुआती स्तर पर कोचिंग की आवश्यकता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं दूसरी श्रेणी डेवलपमेंट की होगी, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित कर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के तौर पर विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में एलीट क्लास के खिलाड़ी आएंगे, यानी वो स्थापित खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

नई खेल नीति में ये भी है खास

- प्रत्येक जिले में एक खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं तथा पैरा खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- स्थानीय और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रदेश में खेल उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- खेल पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में भी प्रयास किया जाएगा।
- प्रदेश में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
- छात्रावासों में बेहतर सुविधाएं जैसे फिटनेस एक्सपर्ट, डाइट एक्सपर्ट की सेवा ली जाएगी।
- छात्रावासों में एडमिशन के लिए इंटरनेशनल खिलाड़ियों की कमेटी गठित की जाएगी।
- स्कूलों में विभिन्न खेलों के विकास के लिए खेल नर्सरी या एकेडमी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ■

मो. : 9415650332

सशक्त होती नारी समृद्ध होता समाज

–मुकुल मिश्र

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है। किसी भी राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी का सशक्तिकरण हो, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करे। मैदान चाहे खेल का हो या फिर शिक्षा का मातृ शक्ति का सम्मान हो। कहते हैं एक महिला दो परिवारों को शिक्षित करती है। शिक्षित नारी ना सिर्फ घर–परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र में भी सकारात्मक योगदान करती है। राज्य की योगी सरकार महिलाओं–बेटियों को हर स्तर पर समृद्ध बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इस वर्ष के वित्तीय बजट 2023–24 में भी महिलाओं को सशक्त बनानेवाली योजनाओं में सरकार ने खासा बजट आवंटित किया है।

सभी वर्गों की बेटियों के विवाह के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी के चलायी जा रही अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए चलायी जा रही महिला सामर्थ्य योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 63 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में राज्य की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए जो काम किये, उन्हें आगे बढ़ाते हुए इस बार के बजट में महिला सुरक्षा, बेटियों के सम्मान और उनके उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के छह लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख के बजट में खासे प्राविधान किये हैं। बलिकाओं के प्रति आम जनता की सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलायी जा रही है। इस योजना में हर लाभार्थी को 15 हजार तक की धनराशि दी जाती है। इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। सभी वर्गों की बेटियों के विवाह

के लिए संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी के चलायी जा रही अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए चलायी जा रही महिला सामर्थ्य योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 63 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया जाता है। निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण अनुदान योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 4032 करोड़ रूपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इस योजना में अभी 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।

योगी सरकार शीर्ष प्राथमिकता में प्रदेश की कानून एवं शांन्ति व्यवस्था है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने राज्य की कानून–व्यवस्था को ना सिर्फ शीर्ष वरीयता पर रखा,बल्कि उन्होंने यह कर भी दिखाया। दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ बेटी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। ऐसा माना जाता है कि एक महिला की बात, एक महिला ही आसानी से समझ सकती है। तभी तो सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चत कराने के लिए महिला थाने बने और उनमें महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब सरकार ने तीन पीएसी बटालियनों के गठन का निर्णय भी लिया है। यह बटालियन राजधानी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में होंगी। महिला एवं बाल अपराधों के 36 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 1296 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1263 अभियुक्तों को दस वर्ष या उससे अधिक सजा तथा 3676 अभियुक्तों को दस वर्ष से कम सजा सुनायी जा चुकी है। जिससे साफ होता है कि ऐसे अभियुक्तों को सरकार किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहती। जब ऐसे अभियुक्तों को अधिक से अधिक सामने लाया जायेगा और उनके मुकदमों की पुलिस जल्द पैरवी कर सजा दिलवायेगी तो ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगी। जहां तक महिलाओं–बेटियों की सुरक्षा की बात है उसके लिए मार्च 2017 में राज्य की कमान संभालने के साथ ही योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया था। जिसने मार्च

2017 से अब तक 6807692 स्थानों पर 2,0902584 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 8440277 व्यक्तियों को चेतावनी दी और 24511 व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की। महिलाओं के लिए वीमेन पावर लाइन 1090 स्थापित की गयी जो महिलाओं–बेटियों के लिए काम करती है। जहां महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और वहां उनकी समस्या का समाधान सक्षम पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिससे बेटियों को सुरक्षा का ऐसा माहौल मिले कि वह बेखौफ हो आगे बढ़ती रहें।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य में बेटियों को शिक्षा के अवसर देने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की, जिसमें अब तक 14.25 लाख बेटियां लाभान्वित हुयीं। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 32.62 लाख को पेंशन मिली है, जिससे उनके जीवन में आशा की किरण का संचार हुआ। दो लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित हुयी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीवन मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में छह माह से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग एक करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में इसके लिए 291 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से छाटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और रक्त की कमी को कम करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन में इन्हें आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 455 करोड़ 52 लाख रूपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम योगी सरकार संचालित कर रही है। जिससे बालक–बालिका अनुपात सही हो सके। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की स्थिति में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं एक हजार रूपये चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को छह हजार रूपये एकमुश्त दिये जाने का प्रावधान सरकार

ने किया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं व बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 56 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की गयी है।

महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालयों की स्थापना की गयी है। महिलाओं के लिए नगरीय क्षेत्र में पिंक टॉयलेट बनवाये गये। निराश्रित महिलाओं को पेंशन से आच्छादित कर इन्हें संबल दिया गया। इस योजना में लाभान्वित होनेवाली महिलाओं की आयु सीमा की बाध्यता को समाप्त किया गया। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड गठित किये गये। हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए वन स्पॉट सेन्टर की स्थापना प्रदेश के सभी जिलों में की गयी। इन वन स्पॉट सेन्टर्स और महिला हेल्पलाइन 1090 सेवा में आनेवाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण होता है जिससे महिलाओं का इसपर ना सिर्फ विश्वास बढ़ा है बल्कि वे स्वयं को और सुरक्षित महसूस करती है।

शहरी क्षेत्रों के साथ ही दूरस्थ ग्रामीण इलाकों की बेटियों–महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच ने प्रदेश भर में मिशन शक्ति के अंतर्गत अनकों कार्यक्रमों की शुरुआत की। जिसमें बीट स्तर पर महिला कान्स्टेबल की तैनाती हो, जिससे कि महिला तथा बच्चियों की सुरक्षा पर गहन निगरानी हो सके।सभी विभागों के कर्मचारी समन्वय स्थापित कर महिला बीट अधिकारी के साथ सभी गांव की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करें व उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएं। इसके साथ ही अधिकारी सप्ताह में एक दिन नगरीय वार्ड और गांवों में एक वृहद अभियान शुरू कर ग्राम सचिवालय में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करें। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेजों में एंटी रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय करना, शाम को पुलिस की एक टीम बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में जाकर फुट पेट्रोलिंग भी शामिल है। जिससे ना सिर्फ प्रदेश की कानून–व्यवस्था को और चुस्त–दुरुस्त रखा जा सके बल्कि महिला अपराधों पर रोक लग सके। सच कहा जाये तो योगी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से ना सिर्फ महिलाएं सशक्त हुयी हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा के साथ ही शक्ति, सम्मान, गौरव प्राप्त हुआ है।

बेटियों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल, कॉलेजों में एंटी रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय करना, शाम को पुलिस की एक टीम बाजारों और भीड़ वाले इलाकों में जाकर फुट पेट्रोलिंग भी शामिल है। जिससे ना सिर्फ प्रदेश की कानून–व्यवस्था को और चुस्त–दुरुस्त रखा जा सके बल्कि महिला अपराधों पर रोक लग सके। सच कहा जाये तो योगी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं से ना सिर्फ महिलाएं सशक्त हुयी हैं बल्कि उन्हें सुरक्षा के साथ ही शक्ति, सम्मान, गौरव प्राप्त हुआ है।

महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और समाजिक सुरक्षा देने के लिए कृतसंकल्पित योगी ने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग को देखते हुए महिला सुरक्षा के लिए भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश 112 से इंटीग्रेशन, साइबर फारेंसिक सुविधा, डाटा एनालिटिक केन्द्र भी स्थापित किए हैं। हॉट स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, कंट्रोलरूम, सिटी बसों में पैनिक बटन आदि लगाये गये। इसी तरह हर घर नल से जल योजना ने भी महिलाओं की परेशानी को काफी कम किया है। घर से कोसों दूर पानी लेने जाना पड़ता था। उस दूरी को तय करने पर ना सिर्फ कई घटनाएं हो जाती थीं बल्कि दिन का आधा समय इसी में व्यतीत हो जाता था। पहले परिवार के लिए पानी जुटाना हो या फिर भोजन बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करना, एक बड़ी समस्या के रूप में महिला को ही इससे रुबरू होना पड़ता था। अब नल से जल और गैस सिलेण्डर ने उन्हें काफी राहत दी है। प्रदेश की योगी सरकार जिस प्रतिबद्धता से राज्य की महिलाओं और बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार कर रही है, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश महिलाओं व बेटियों के लिए भयमुक्त माहौल बनानेवाला नंबर वन प्रदेश बन जायेगा। ▪

मो. : 9335605656

महिलाओं के सतत् विकास के लिए प्रयत्नशील सरकार

–द्वारिका नाथ पाण्डेय

संस्कृत में एक उक्ति है कि "नारी अस्य समाजस्य कुशलवास्तुकारा अस्ति" अर्थात महिलाएं इस समाज की आदर्श शिल्पकार होती हैं। ये उक्ति इस बात को दर्शाती है कि किसी भी समाज का कुशल निर्माण नारी के हाथों में होता है अतः समाज के उत्थान से पूर्व नारी उत्थान करना होगा। भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना में नारी का योगदान प्राचीन काल से ही है। नारी–पुरुष समभाव एवं "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" की वैचारिकी वाला ये देश है। यहां गत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नारी उत्थान एवं विकास को लेकर कई योजनाएं बनाई एवम् कई कार्य किए और इतना ही नहीं सभी में सरकार को सफलता भी मिली। इस श्रृंखला में कई योजनाएं एवं कार्य अग्रलिखित हैं। जैसे–यूपी मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, महिला पुलिस की सुविधा हेतु पिंक बूथ का निर्माण करना इत्यादि प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं।

यूपी मिशन शक्ति–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। इसका शुभारंभ प्रदेश की महिलाओं एवम् बेटियों को स्वावलंबी, सशक्त, एवम् सुरक्षित बनाने लिए किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के जागरुकता एवम् ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। जिससे कि

महिलाओं एवं बेटियों को सशक्त बनाया जाए एवम् उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में उसे लॉन्च किया गया था।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना—समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद–भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी–

प्रथम श्रेणी– नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01–04–2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को रू. 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

द्वितीय श्रेणी– वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01–04–2018 से पूर्व न हुआ हो, को रू. 1000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

तृतीय श्रेणी– वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू. 2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी– वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू.

2000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

पंचम श्रेणी– वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, को रू. 3000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

षष्ठ श्रेणी– वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो, को रू. 5000 एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना– गरीब बेटियों और तलाकशुदा महिलाओं के जीवन को रोशन करने के उद्देश्य से शुरू की कई इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले कई परिवारों को खुशियों की सौगात दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार विवाह करने वाली बेटियों एवम् तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्विवाह करने हेतु पैंतीस हजार रुपए सीधे उनके खाते में प्रदान करती है। इसके अलावा दस हजार रूपए बेटी के विवाह के अतिरिक्त खर्च और 6 हजार रूपए को टेंट, बिजली जैसे अन्य खर्चों के लिए प्रदान किए जाते है।

महिला सामर्थ्य योजना– महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई यूपी महिला सामर्थ्य योजना के माध्यम से महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा उनके आसपास

उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के हिसाब से कुटीर उद्योगों की शुरुआत करने को प्रेरित किया जाएगा। महिलाओं द्वारा उत्पादित पदार्थो को बेचने के लिए भी सरकार उन्हे बाजार उपलब्ध कराएगी। जहाँ महिलाओं को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 200 विकासखंडों में महिला सामान्य सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे सामान्य उत्पादन और उसकी तकनीकी, विकास, पैकेजिंग, लेवेलिंग और बारकोडिंग इत्यादिकी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य जागरूकता, सेमिनार, एक्स्पोजर, परामर्श कार्यक्रम, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन सुविधा केंद्रों का 90 प्रतिशत का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस सबके लिए प्रदेश सरकार ने दो सौ करोड़ रुपए बजट की घोषणा की है।

यूपी मिशन शक्ति–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। इसका शुभारंभ प्रदेश की महिलाओं एवम् बेटियों को स्वावलंबी, सशक्त, एवम् सुरक्षित बनाने लिए किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के जागरुकता एवम् ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया जाता है।

महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार–

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के विकास और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाओं से स्त्री शक्ति को जोड़ने का प्रयास किया है। महिला सुरक्षा सदैव से समाज में एक मुद्दा रहा है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा का कवच देने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिछले दिनों 3000 नए पिंक बूथ बनाने की घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए टू व्हील पिंक पेट्रोल, विशेष सुविधा युक्त पिंक टॉयलेट के निर्माण के साथ साथ डार्क स्पॉट्स को चिन्हित कर स्थानों पर उचित प्रकाश की व्यवस्था की गई है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के माध्यम से भी महिलाओं को तत्काल सेवा एवम् उनकी समस्याओं का निदान कर उन्हे सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

इन योजनाओं के अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने प्रदेश में छह माह से छह वर्ष तक आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वागीण विकास के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में समेकित बाल विकास सेवा योजना संचालित की। जिससे लाखों की संख्या में गर्भवती महिलाएं व कुपोषित बच्चे लाभन्वित हुए।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, स्वयं साहायता योजना, उज्ज्वला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, शबरी संकल्प अभियान, महिला शक्ति केन्द्र, किशोरी बालिका योजना, सखी सेंटर, महिला हेल्पलाइन 1090, मिशन शक्ति, घरौनी योजना, कन्या सुमंगला योजना, स्वामित्व योजना, एंटी रोमियो स्क्वॉड जैसे प्रयासों से सीधे तौर पर ग्रामीण व शहरी महिलाओं को लाभ मिल रहा है।

प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार पूरी ऊर्जा के साथ महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रही है जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने भी शुरू हो गए है। महिला सुरक्षा से लेकर महिलाओं के स्वावलंबन बनने तक में उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है।

(संदर्भ–महिला एवम् बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार एवम् उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य अधिकृत वेबसाइट्स)

मो. : 916387425744

पूरी दुनिया को सेहत का तोहफा देगा भारत

–डॉ. शिव राम पाण्डेय

कदन्न, मिलेट्स, मोटे अनाज, कोर्स सीरियल्स, सिरि धान्य, पोषक अनाज और श्री अन्न यह उस कृषि उपज का नाम है जिसकी बहुत दिनों तक खेती करने के बाद भारतीय किसानों ने लगभग छोड़ दिया था। केन्द्र की मौजूदा सरकार ने पोशक अनाजों, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ''श्री अन्न'' नाम दिया है की खेती को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय ही नही अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है। श्री अन्न भारत के लिए आर्थिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि बेहद लाभकारी है। हम दुनिया के सबसे बड़े श्री अन्न उत्पादक हैं और इसकी उपज और निर्यात बढ़ा कर हम देश की आर्थिक सेहत में वृद्धि कर सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने रणनीतिक पहल शुरू भी कर दिया है। भारत की पहल पर आज दुनिया वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स इयर के रूप में मना रही है। परम्परागत रूप से उगाए जाने वाले औषधीय गुणों से परिपूर्ण मोटे अनाज यानी श्री अन्न, दुनिया में भारत की नई पहचान बना रहे हैं। भारतीय बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार और कुट्टू की अब विश्व में मांग बढ़ती जा रही है।

20 प्रतिशत की भागीदारी के साथ भारत मोटे अनाज यानी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुनिया में मोटे अनाज की क्रांति लाने की जिम्मेदारी भारत ने अपने कंधों पर उठा रखी है। एपीडा की मार्केटिंग रणनीति के साथ दुनियाभर में मोटे अनाज के आयात को लक्षित कर भारत के निर्यात में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था एपीडा की लक्ष्य वर्ष 2025 तक 100 मिलियन डॉलर का श्री अन्न निर्यात करना है। भारत की क्षमता का आकलन करते हुए एक व्यापक वैश्विक मार्केटिंग अभियान तैयार किया जा रहा है। इसके अनुसार 30 आयातक देशों और 21 मोटे अनाज के उत्पादक राज्यों का ई–कैटलॉग तैयार किया गया है। मोटे अनाज और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

बढ़ती आबादी के साथ हमारे कृषि परिदृश्य में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की कृषि उपज में तो चमत्कारिक प्रगति हुई है। किसी जमाने में भुखमरी के संकट से जूझ रहा देश आज अपने कृषि उपजों का निर्यात करने लगा है। यह चमत्कार कृषि के यंत्रीकरण, रसायनीकरण और संसाधनों की उपलब्धता के कारण संभव हुआ है।

देश में मोटे अनाज यानी मिलेट्स का प्रोत्साहन देने के लिए विगत दिनों दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर श्री मोदी ने मिलेट्स डाक टिकट और मिलेट्स स्मृति चिन्ह के रूप में 75 रुपए के सिक्के का भी अनावरण किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि देश के करीब ढाई करोड़ छोटे किसान मिलेट्स के पैदावार से सीधे सीधे जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मिलेट्स के प्रचार प्रसार से और इसके खानपान में वृद्धि से देश के छोटे किसानों को सीधे फायदा होगा। देश के करीब 9 राज्यों में मोटे अनाजों की खेती होती है और इसकी खेती ज्यादातर आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है।

श्री मोदी ने कहा कि मिलेट्स का ग्रोथ रेट 30 प्रतिशत से ज्यादा है साथ ही 19 जिलों में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। देश के करीब 500 स्टार्टअप मोटे अनाज के पैदावार से लेकर इसकी सप्लाई चेन और इसके प्रमोशन के लिए काम शुरू कर चुके हैं। कुछ साल पहले तक जहां मिलेट्स की खपत 2 से 3 किलो प्रति परिवार प्रतिमाह थी, अब बढ़कर 14 किलो प्रति परिवार हो रही है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज का पैदावार और देश में इसकी सप्लाई चैन बनाना सबसे अहम कार्य है।

उन्हों ने कहा, ''श्री अन्न'' मानव और मिट्टी दोनों की सुरक्षा करता है. साथ ही ये फूड सिक्योरिटी और फूड हैबिट दोनों के लिए जरूरी पहल है, श्री का मतलब समस्या से मुक्ति है। मोटा अनाज पूरे विश्व समुदाय के लिए अच्छा कदम होगा, श्री अन्न से लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियों में कमी आएगी। मोटे अनाज को देश में पीडीएस सिस्टम से जोड़ना इसके लिए एक अहम कड़ी हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिड–डे–मील से भी इसको जोड़कर इसकी उपयोगिता और इसकी अहमियत को बढ़ाया जा सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था एपीडा की लक्ष्य वर्ष 2025 तक 100 मिलियन डॉलर का श्री अन्न निर्यात करना है। भारत की क्षमता का आकलन करते हुए एक व्यापक वैश्विक मार्केटिंग अभियान तैयार किया जा रहा है। इसके अनुसार 30 आयातक देशों और 21 मोटे अनाज के उत्पादक राज्यों का ई–कैटलॉग तैयार किया गया है। मोटे अनाज और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक वर्चुअल ट्रेड फेयर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

देश में पहले हल बैलों से खेती होती थी। जिसके पास जितना गोई (जोड़ी) बैल, वह उतना ही अधिक बड़मनई (सम्पन्न)। उस दौर में खेतिहर मजदूरों की भरमार थी। बिना बुलाये ही मजदूर काम करने चले आते थे। उस दौर में नकद पैसा बहुत कम देखने को मिलता था। मजदूरी अनाज के ही रूप में दी जाती थी। चेना, साँवा, कोदो, मड़ुआ, काकुन, ज्वार बाजरा अंकरी अक्सा, चना, मटर, जौ, जौकेराई आदि फसलों की भरमार थी। अनाज की उपज में जौ केराई की बहुलता थीं जौ केराई का मतलब जौ प्लस केराव (मटर) या अक्सा जिसे गोजई भी कहते थे की बहुलता थी। गेहूँ का साम्राज्य तो छठे दशक के बाद स्थापित हुआ है। गेहूँ और धान का चावल बड़मनई लोगों का भोजन था। गरीब आदमी तो अपना पेट मोटे अनाज ही खाकर पाट पाता था। मेरी माँ एक कहावत कहती थीं –

जे खाय चूनी–चोकर, ते बना रहै धोकर।
जे खाय निराबानी ते कां लइ जायं भवानी।।

चूनी चोकर का मतलब मोटे अनाजों और निराबानी का मतलब फाइन खाद्यान्न जैसे अरहर की दाल, गेहूँ के आटे और धान के चावल से है। उस दौर में सिचाई की सुविधा या तो थी नही और अगर थी भी तो सिंचाई के उपकरण ढेकली, दोगला, रहट और गगरा थे, नहरें और नलकूप की सुविधा कहीं–कहीं और बहुत ही सीमित मात्रा में थी। खेती भगवान की कृपा पर निर्भर थी। धान और गेहूँ की फसल के सिवा अन्य फसलें वर्षा की मोहताज थीं। पारम्परिक खेती का दौर था ''तेरह कातिक

तीन अषाढ़'' के फार्मूले पर खेती होती थी। यह फार्मूला खेत की तैयारी के लिए था। अषाढ़ माह में पानी बरस जाने पर एक दिन में ही साँवा, कोदो, काकुन, मडुआ और अगैती धान की बोआई हो जाती थी और एक दिन में दलहनी फसलो की बोआई हो जाती थी। अगैती धान की बोआई रसौती विधि यानी पर्याप्त नमी के साथ सूखे खेत में छिटकुआ विधि से होती थी जबकि जोरदार बारिश होने पर जब खेतों में पानी एकत्र हो जाता था तब उसी पानी में पलेवा लगाकर धान की बोआई की जाती थी। उस समय धान की रोपाई का प्रचलन बहुत कम था। खरीफ फसलों में सबसे पहले काकुन की फसल (बुआई से लगभग ड़ेढ़ माह में) उसके बाद सावाँ की फसल (बुआई से लगभग दो माह में) तैयार हो जाती थी जबकि धान की फसल तैयार होने में 70 से 90 दिन लग जाते थे। यानी आधे सावन से काकुन, भादो माह से सावाँ और पितृपक्ष से धान का चावल खाने को मिलने लगता था। इस दौरान ऊँचाई वाले क्षेत्रों में धान होता नहीं था और जलभराव और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में धान होता तो था मगर फसल के गलने का खतरा बरकरार रहता था। मोटा अनाज खाना उस समय लोगों की मजबूरी थी। आम आदमी मोटा अनाज खाकर खूब ताकतवर और स्वस्थ रहता था। उस समय लोग एक तो बीमार पड़ते नहीं थे और अगर बीमार होते भी थे तो अपने खान–पान में बदलाव और घरेलू उपचार कर स्वस्थ हो जाते थे। खेतों में काम करने वाले मजदूर तीज–त्योहार, मरनी–करनी शादी विवाह और नवान्न के अवसर पर या कोई मेहमान आ जाने पर ही मजदूरी के बदले में गेहूँ और चावल की माँग करते थे। यानी लोग मोटा अनाज खाकर खूब स्वस्थ और मजबूत, शक्तिशाली बने रहते थे। मेहनत–मशक्कत ही उनकी सेहत का राज था। उपरोक्त कहावत इन्हीं तथ्यों को प्रमाणित करती है। मोटे अनाजों में सेहत का खजाना छिपा होता था इसीलिए उसे खाकर उस समय के लोग स्वस्थ रहा करते थे। हरित क्रांति से देश में कृषि की उत्पादता और उत्पादन तो बढ़ा मगर मोटे अनाज चलन से बाहर हो गये। कम्पोस्ट खाद का खेती में इस्तेमाल बन्द ही हो गया। सारा जोर जमीन से अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने पर लगा दिया गया। बोरी वाली खाद खेती का अमृत बन गई। फसल सुरक्षा के नाम पर धरती

माता को जहर पिलाना शुरू कर दिया गया। फसलों में खर पतवार निकालनें के लिए भी निराई गुड़ाई बन्द कर धरती को रासायनिक जहर दिया जाने लगा। कृषि में मशीनीकरण का जोर बढ़ने के कारण पशुपालन की अनिवार्यता समाप्त हो गई और पराली जलाने की नई बीमारी ने जन्म ले लिया जिससे धरती की उर्वरा शक्ति के साथ–साथ हमारे मित्र कीट भी विदा हो गये। हमारे अन्न में घुला जहर ही हमारे लिए काल बन गया है। इस सच्चाई पर भी सबसे पहले भारत की ही नजर पड़ी है। भारत सरकार फिर से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2018 को भारत नें मिलेट्स इअर यानी कदन्न वर्ष के रूप में मनाया गया और देश में मोटे अनाजों की खेती के लिए देश के किसानों को प्रेरित किया गया। अब भारत की ही पहल पर वर्ष 2023 को समूची दुनिया मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है। भारत सरकार जहाँ मोटे अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में ले आई वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मोट अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई नीति तैयार किया है। मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने की सरकार की पहल स्वागत योग्य है लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। देश और दुनिया को रसायन मुक्त और पारम्परिक खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। केवल एक वर्ष मिलेट्स इयर मना लेने से देश दुनिया और समाज का भला नहीं होने वाला है। इसके लिए लगातार पहल की तो जरूरत है ही उसकी खेती को और लाभदायी बनाने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोटा अनाज उत्पादक और निर्यातक देश है, हमारा देश अकेले दुनिया का 40 प्रतिशत मोटा अनाज पैदा करता है इसलिए मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देना भारत के लिए

लाभदायक भी है और जरूरी भी है। मोटे पोषक अनाजों का उत्पादन बढ़ाकर जहां जहाँ स्वास्थ्य बजट को कम किया जा सकता है वहीं उसके निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार को और भी समृद्ध किया जा सकता है। यही नहीं मोटे या पोषक अनाजों के लिए प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा किये जा सकते हैं। हमारी सरकार इस दिशा में काफी सक्रिय भी है।

भारतीय मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र ने 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्स्पो तथा क्रेता–विक्रेता बैठकों में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी में सहायता देने की योजना पर काम कर रही है।

मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने की भारत की सुदृढ़ नीति के अनुसार भारतीय मोटे अनाजों की ब्रांडिंग और प्रचार में विदेश स्थित भारतीय मिशनों का सहयोग लिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शेफर्स (रसोइयों) के साथ–साथ डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर मार्किट तथा हाइपर मार्किट जैसे संभावित खरीदारों की पहचान की जाएगी, ताकि उनके साथ बैठक की जा सके और प्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क किया जा सके।

एपीईडीए ने दक्षिण अफ्रीका, दुबई, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, सिडनी, बेल्जियम, जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम बनाए हैं। एपीईडीए इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फूड शो, क्रेता–विक्रेता बैठकों और रोड शो में भारत के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी में सहायता करेगा।

भारतीय मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के भाग के रूप में एपीईडीए ने गुलफूड 2023, फूडेक्स, सोल फूड एंड होटल शो, सउदी एग्रो फूड, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के फाइन फूड शो, बेल्जियम के फूड और बेवरिज शो, जर्मनी के बायोफैक और अनुगा फूड फेयर, सेन फ्रैंसिस्को के विंटर फैंसी फूड शो जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को दिखाने की योजना बनाई है।

भारत विश्व में मोटे अनाजों के अग्रणी उत्पादकों में एक है और वैश्विक उत्पादों में भारत का अनुमानित हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत है। एफएओ के अनुसार वर्ष 2020 में मोटे अनाजों का विश्व उत्पादन 30.464 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हुआ और भारत का हिस्सा 12.49 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कुल मोटा अनाज उत्पादन का 41 प्रतिशत है। भारत ने 2021–22 में मोटा अनाज उत्पादन में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि इससे पहले के वर्ष में यह उत्पादन 15.92 एमएमटी था।

भारतीय मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने के भाग के रूप में एपीईडीए ने गुलफूड 2023, फूडेक्स, सोल फूड एंड होटल शो, सउदी एग्रो फूड, सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के फाइन फूड शो, बेल्जियम के फूड और बेवरिज शो, जर्मनी के बायोफैक और अनुगा फूड फेयर, सेन फ्रैंसिस्को के विंटर फैंसी फूड शो जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर मोटे अनाजों और उसके मूल्यवर्धित उत्पादों को दिखाने की योजना बनाई है।

इसके अतिरिक्त, लक्षित देशों के भारत स्थित विदेशी मिशनों के राजदूतों तथा संभावित आयातकों को 'रेडी टू ईट' मोटे अनाज उत्पादों सहित विभिन्न मोटे अनाज उत्पादों को दिखाने और बैठकों में आमंत्रित किया जारहा है।

भारत के शीर्ष पांच मोटा अनाज उत्पादक राज्य हैं – राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। मोटा अनाज निर्यात का हिस्सा कुल उत्पादन का एक प्रतिशत है। भारत के मोटे अनाज के निर्यात में मुख्य रूप से सम्पूर्ण अनाज है और मोटे अनाजों के मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बहुत कम है।लेकिन अनुमान है कि वर्ष 2025 तक मोटे अनाज का बाजार वर्तमान 9 बिलियन डॉलर बाजार मूल्य से बढ़कर 12 बिलियन डॉलर हो जाएगा। ■

मो. : 9415757822, 6387257161

पर्यटन से लगेंगे यूपी के विकास को पंख

–अमित नारायण भार्गव

किसी भी राज्य में यदि पर्यटन क्षेत्र का विस्तार होता है, तो धरम–करम के साथ घुमक्कड़ी का दायरा भी बढ़ता है। यही नहीं, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अपार अवसर भी सृजित होते हैं, साथ ही उस क्षेत्र के विकास के नये द्वार भी खुल जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रारंभ से ही पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और विकास को प्राथमिकता देते रहे हैं। इस दिशा में योगी सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन के विकास की ऐसी रूपरेखा खींची कि छह वर्षों में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का कायाकल्प हुआ और वहां सुगम आवागमन की सुविधा मिली तो पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती चली गयी। असुविधाओं के कारण जिन पर्यटन स्थलों पर लोग जाने से कतराते थे, आज सारी सुविधाएं मिलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन बढ़ गया है।

प्रदेश सरकार ने पर्यटन विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नयी पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों को 40 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। पूंजीगत सब्सिडी के अलावा बैंक ऋण पर देय ब्याज और स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण में भी छूट मिलेगी। नयी पर्यटन नीति के जरिये प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नीति के तहत प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान भी है।

नयी नीति में प्रदेश में रामायण और महाभारत सर्किट बनने का रास्ता साफ हो गया है। इससे धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थलों को नयी पहचान भी मिलेगी। इसके तहत बुद्ध सर्किट से लेकर महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट का निर्माण भी होगा। वाइल्डलाइफ और इको टूरिज्म के क्षेत्रों को चिह्नित कर उनका पर्यटन के लिहाज से विकास किया जायेगा।

कम विकसित क्षेत्रों में टूरिज्म बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने से लेकर रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी सरकार का फोकस है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक स्थलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए अलग-अलग सर्किट का विकास करके एक समान पर्यटन केंद्र शामिल किये जायेंगे। उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जायेगा। इसे नयी पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। सरकार इन सर्किट के जरिये पर्यटन के नये क्षेत्रों का भी विकास करेगी।

नीति में युवाओं एवं बच्चों में प्रारंभ से ही पर्यटन व संस्कृति की समझ, आवश्यकता तथा महत्व को विकसित करने की योजना भी बनायी गयी है। इसके तहत युवा पर्यटन क्लबों को देश में उत्तरदायी और सतत पर्यटन विकसित करने के साधन के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा राज्य में विभिन्न पर्यटन व्यवसायों द्वारा संचालित असाधारण पहलों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करने के लिए बेस्ट टूर ऑपरेटर, बेस्ट वेलनेस सेंटर, बेस्ट होटल, बेस्ट हेरिटेज होटल, बेस्ट इको टूरिज्म ऑपरेटर, बेस्ट इको रिसॉर्ट, बेस्ट होमस्टे, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर आदि राज्य पर्यटन पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

जिन नये पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जायेगा, उनमें रामायण सर्किट प्रमुख है। रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन धार्मिक स्थलों को भगवान राम एवं माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह, बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे।

इसी तरह वाइल्डलाइफ और इको टूरिज्म को एक साथ रखते हुए इसमें सेंचुरी और फॉरेस्ट रिजर्व को विकसित किया जायेगा। इनके तहत प्राकृतिक स्थल विकसित किये जायेंगे। वाइल्डलाइफ से जुड़े क्षेत्रों को भी पर्यटन के लिहाज से विकसित करते हुए यहां पर्यटकों के अनुकूल सुविधाओं में इजाफा किया जायेगा।

महाभारत सर्किट में हस्तिनापुर, कांपिल्य, एछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। इसी तरह शक्तिपीठ सर्किट का भी विकास होगा। इसमें विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से देवीपाटन, नैमिषारण्य, मां ललिता देवी, मां ज्वाला देवी, शाकुम्भरी देवी सहारनपुर से शिवानी देवी चित्रकूट और शीतला माता मऊ तक विस्तार होगा। आध्यात्मिक स्थलों को भी पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जायेगा। इसके तहत आध्यात्मिक

सर्किट बनाया जा रहा है। इसमें गोरखपुर, बलरामपुर से लेकर मथुरा, संत रविदास स्थल, मां परमेश्वरी देवी आजमगढ़, बलिया का बिघू आश्रम, आगरा का बटेश्वर, हनुमान धाम शाहजहांपुर को सम्मिलित किया गया है। इसी तर्ज पर सूफी कबीर सर्किट भी विकसित होगा। इसे अमेठी, मगहर, संत कबीरनगर से लेकर कबीरदास की कर्मभूमि वाराणसी के लहरतारा तक ले जाने का प्रस्ताव है। उधर, जैन सर्किट देवगढ़, हस्तिनापुर से लेकर पार्श्वनाथ, दिगंबर जैन मंदिर रामनगर तक ले जाने का प्रस्ताव है।

नयी नीति में क्राफ्ट सर्किट बनाने का भी इनोवेटिव आइडिया है। उत्तर प्रदेश में अनेक जिलों में हैंडीक्राफ्ट का काफी काम होता है। कहीं मार्बल, तो कहीं ग्लास, पीतल, हथकरघा, क्रॉकरी, कालीन, टेराकोटा का काम होता है। इनमें से कई जिले और उत्पाद ओडीओपी में भी शामिल हैं। इन सारे क्राफ्ट से जुड़े स्थलों को साथ लेकर क्राफ्ट सर्किट निर्मित किया जायेगा।

योगी सरकार ने नीति में स्वतंत्रता संग्राम सर्किट की भी परिकल्पना शामिल की है। इसमें मेरठ, शाहजहांपुर, काकोरी, चौरीचौरा जैसे स्थल शामिल हैं, जिनका देश के स्वतंत्रता संग्राम अभियान में अहम स्थान है। इसके अलावा बुंदेलखंड सर्किट को भी विकसित किया जाना है। इसमें चरखारी, चित्रकूट, कलिंजर, झांसी, देवगढ़, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन जैसे जिले शामिल होंगे।

प्रदेश के कम विकसित क्षेत्रों को विकसित करके भी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने का पोटेंशियल होता है। इसे देखते हुए ही नीति में इसको केंद्र बिंदु में रखा गया है।

इतना ही नहीं, 22 तरह की गतिविधियां पर्यटन से जुड़ेंगी। पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियां, अब तक पर्यटन के दायरे में शामिल नहीं थीं, उन्हें सम्मिलित किया गया है। इनमें बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, हेरिटेज होम स्टे, इको टूरिज्म की इकाइयां, कारवां टूरिज्म यूनिट, प्रदर्शनी, पिलग्रिम डॉर्मेट्री, धर्मशालाएं, वेलनेस रिसॉर्ट, आल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय–झील, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म जैसी कुल 22 एक्टिविटीज को नयी नीति में जगह दी गयी है।

योगी सरकार उत्तर प्रदेश को 'पर्यटन प्रदेश' बना देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा नयी पर्यटन नीति से और साफ होता है। पर्यटन स्थल के तहत विभिन्न निवेशकों को कम ज्ञात पर्यटन स्थलों में निवेश करने का मौका दिया जायेगा।

फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन (एफटीओ) में पर्यटन इकाई के प्रस्तावों हेतु महिला उद्यमी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के उद्यमियों को सब्सिडी में अतिरिक्त 5 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये तक की बैंक ऋण राशि पर पात्र पर्यटन इकाइयों को अधिकतम 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष ऋण राशि के 5 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी। ■

मो. : 9415005540

बेहतर स्वास्थ्य का सपना साकार

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता यूपी

–सुयश मिश्रा

डबल इंजन वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में दूनी गति से कार्य कर रही है। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब यूपी आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ गया है। हालही में जारी किए गए 20 हजार करोड़ रुपए के बजट से यूपी में कई परिवर्तन होने की संभावना देखी जा रही है।

समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा आम आदमी भी सरकारी चिकित्सा का समुचित लाभ ले सके इसको लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। अब अस्पताल की दीवारों पर जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उसका नाम और मोबाइल नंबर भी होगा साथ ही अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसका भी ब्यौरा दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों व तीमारदारों को हर हाल में बेहतर सुविधाएं दी जाएं। चिकित्सालय के इमरजेंसी रूम के सामने एक कर्मचारी की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाए। यह यहां आ रहे रोगियों को तत्काल डाक्टर के पास उपचार के लिए भेजने में मदद करेगा और इन्हें व्हील चेयर व स्ट्रेचर दिलाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वैलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, शहरों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ क्लब लैब की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के सुदृढ़ीकरण हेल्थ इनफॉरमेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 1547 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालही में 20 हजार करोड़ के स्वास्थ्य बजट से न सिर्फ यूपी की तस्वीर बदलती दिख रही है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी उम्मीद देखी जा रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान

योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई स्कीमें गरीबों के कल्याण के लिए चला रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार के ऐतिहासिक काम–स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का समय पर न आना और अनुपस्थिति बड़ी चुनौती थी इसको लेकर भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सख्ती दिखाई। ड्यूटी से गायब डाक्टर व पैरामेडिकल कर्मियों के खिलाफ अब न सिर्फ कार्रवाई हो रही है बल्कि प्रत्येक सोमवार को स्वास्थ्य महानिदेशालय की

समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठा आम आदमी भी सरकारी चिकित्सा का समुचित लाभ ले सके इसको लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। अब अस्पताल की दीवारों पर जिस डॉक्टर की ड्यूटी है उसका नाम और मोबाइल नंबर भी होगा साथ ही अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसका भी ब्यौरा दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों व तीमारदारों को हर हाल में बेहतर सुविधाएं दी जाएं।

मानीटरिंग सेल को रिपोर्ट कार्ड भेजने की अनिवार्यता भी कर दी गई है। मानीटरिंग सेल इसका सत्यापन करेगी और रिपोर्ट गलत होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब स्वास्थ्य महानिदेशालय मानीटरिंग सेल की मदद से निगरानी की व्यवस्था शुरू की गई है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों (CMO) को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन कम से कम पांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का औचक निरीक्षण करें। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य की निचली इंकाइयों को मजबूत करना है। अस्पताल

में डाक्टर व कर्मचारी समय पर उपस्थित हों यह सुनिश्चित किया जाए। कौन–कौन से डाक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर दीवार पर पेंट कर लिखा जाए इसको लेकर भी कार्य शुरू हो गया है। अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हैं और कितने बेड खाली हैं, इसका भी ब्योरा लिखा जाएगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट मानीटरिंग सेल को सीएमओ ईमेल आइडी monitoringcell.dgmh@gmail.com पर भेजना होगा। हालही में जारी बजट में योगी सरकार ने प्रदेश वासियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा है। उनकी सेहत सुधारने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। बजट में कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों पर यूपी के विजय अभियान का ब्लूप्रिंट पेश किया गया है। सरकार का ग्रामीण स्वास्थ्य पर भी जोर है गरीबों के इलाज की व्यवस्था के साथ वैलनेस सेंटर लोगों के रोग के वाहक बनेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बढ़ती क्षमता, नर्सिंग कॉलेजों और नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से स्वास्थ्य क्षेत्र में यूपी आत्मनिर्भर होता दिखाई दे रहा है। गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए 650 करोड़ रुपए वहीं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़ जबकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। ताकि जिले के हर नागरिक को स्वास्थ्य की वो हर बुनियादी सुविधा मिले जिसकी आस में वो बड़े शहरो की ओर दौड़ लगाते हैं।

आपको बता दें कि प्रदेश में 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। जबकि 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। वहीं 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। इसके अलावा असाध्य रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अन्य प्रदेशों के लिए एक मॉडल होंगी। ■

मो. : 8924856004

आस्था के सम्मान की परम्परा

–ए.एम. सिंह

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लोक आस्था व जन–जन के पर्व–त्योहारों को नई रंगत प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप यूनेस्को द्वारा प्रयागराज कुंभ को 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' के रूप में मान्यता दी गयी। 2019 के दिव्य–भव्य कुंभ ने नए–नए कीर्तिमान स्थापित किए और कई विश्व रिकॉर्ड बनाए। होली पर रंगोत्सव हो या दीपावली पर दीपोत्सव या फिर वाराणसी की देव दीपावली, प्रदेश में हर पर्व की छटा निराली रहने लगी है। सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के विकास के लिए भी प्रदेश सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद व विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन कर पौराणिक स्थलों का विकास कर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कुंभ के साथ माघ मेले के आयोजन के कारण तीर्थराज प्रयागराज का विकास प्रदेश सरकार के मुख्य केंद्र है। वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ तैयारी की रूपरेखा अभी से तैयार होने लगी है। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार संकल्पित है। इन तैयारियों की एक झलक प्रयाग में सम्पन्न हुए माघ मेले में देखने को मिली।

"प्रयागस्य पवेशाद्वै पापं नश्यतिः तत्क्षणात्।" यानी प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। यहां आना हमेशा सुखकारी, हितकारी व आनन्दकारी रहता है। माघ मास की हो तो प्रयागराज का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि माघ महीने में पवित्र नदियों के संगम पर देवी–देवता भी पूरे महीने वास करते हैं।

मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतिहि आव सब कोई।

देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहिं सकल त्रिवेणी।।

अर्थात सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में देव, दनुज, किन्नर, गंधर्व सभी आते हैं और त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। प्रयागराज में पवित्र संगम की रेती पर प्रत्येक वर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक चलता है। इस बार प्रयागराज माघ मेला 6 जनवरी, 2023 को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ प्रारंभ और महाशिवरात्रि 18 फरवरी, 2023 को स्नान के साथ समाप्त हुआ। माघ मेले में देश–दुनिया के लाखों श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज पहुंचे। माघ मेले में कल्पवासियों के रहने के लिए तंबुओं का बनाया गया शहर सबके आकर्षण का मुख्य केंद्र बिन्दु रहा। छोटे–छोटे तंबू की कुटिया में श्रद्धालुओं ने एक महीने तक कठोर नियम से कल्पवास किया।

प्रदेश सरकार की माघ मेला को लेकर व्यापक तैयारियों के परिणामस्वरूप पवित्र संगम में डुबकी लगाकर नवजीवन का संचार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मेले की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मेला सेक्टर को 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया। माघ माह में संगम में स्नान का विशिष्ट महत्व होता है, विशेष रूप से पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा व महाशिवरात्रि पर इन पर्वों पर सुरक्षा व सुविधा के साथ स्नान के लिए खास व्यवस्था की गई थीं।

प्रदेश सरकार की माघ मेला को लेकर व्यापक तैयारियों के परिणामस्वरूप पवित्र संगम में डुबकी लगाकर नवजीवन का संचार करने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मेले की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मेला सेक्टर को 6 सेक्टरों में विभाजित किया गया। माघ माह में संगम में स्नान का विशिष्ट महत्व होता है, विशेष रूप से पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा व महाशिवरात्रि पर। इन पर्वों पर सुरक्षा व सुविधा के साथ स्नान के लिए खास व्यवस्था की गई थीं। नदी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पांच पीपे के पुल का निर्माण किया गया, ताकि आवागमन सुचारू रहे। छोटे–बड़े घाटों के साथ 16 स्नान घाट मुख्य रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयार किए गए थे।

14 हजार से अधिक एलईडी लाइट से पूरे मेला क्षेत्र को जगमग किया गया। 16 मुख्य द्वार पर आकर्षक रंग–बिरंगी लाइटों से मेले का मनोरम दृश्य देखते ही बना। मेला परिसर में निरंतर बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए 20 अस्थायी विद्युत उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए 18 बड़े जनरेटर उपकेंद्रों की व्यवस्था भी की गयी थी। मेले में आए पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को पीने की पानी की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया था। स्थान–स्थान पर पीने के पानी के लिए व्यवस्था की गयी थी। 20 नलकूपों से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। राज्य सरकार के लोक हितकारी प्रयासों से प्रयागराज माघ मेला– 2023 सुखद यादगार स्मृतियों के साथ सम्पन्न हुआ। अगले वर्ष पुनरू आने की कामना लेकर पर्यटक–श्रद्धालु, विशेष रूप कल्पवासी अपने–अपने गंतव्य को रवाना हुए। ■

14 हजार से अधिक एलईडी लाइट से पूरे मेला क्षेत्र को जगमग किया गया। 16 मुख्य द्वार पर आकर्षक रंग–बिरंगी लाइटों से मेले का मनोरम दृश्य देखते ही बना। मेला परिसर में निरंतर बिजली आपूर्ति होती रहे, इसके लिए 20 अस्थायी विद्युत उपकेंद्रों से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। इसके साथ ही आपात स्थिति के लिए 18 बड़े जनरेटर उपकेंद्रों की व्यवस्था भी की गयी थी।

मो. : 9451907315

वैश्विक सांस्कृतिक विरासत में अतुलनीय है
काशी की दिव्यता और भव्यता

—प्रेमशंकर अवस्थी

काशी इन दिनों अपने दिव्यता और भव्यता के साथ नये अवतार में है। विश्व—छितिज पर नये—नये उपमान गढ़कर भारतीय सनातन संस्कृति की चेतना का पुर्नजागरण की आधारशिला बन गयी है। वैसे तो काशी का महात्म्य वैश्विक पटल पर पहले से ही देदीप्यमान है। जहां इस नगरी की आध्यात्मिक चेतना न केवल वैश्विक पटल पर अपितु सम्पूर्ण ब्रह्ममाण्ड को आलोकित व प्रकाशमान करने वाली है। भला क्यों न हो? क्योंकि काशी अखिल ब्रह्ममाण्ड नायक भगवान विश्वेश्वर शिव की प्रिय नगरी है। जहां वह स्वयं माँ पार्वती के साथ निवास करते हैं। गंगा का अविरल जल इस नगर को प्राकृतिक सौन्दर्य और जीवन्तता का मर्मस्पर्शी अनुभव कराता है यह बात हर व्यक्ति के मन में उमड़ती रहती है कि काशी तीन लोक से न्यारी शिव की नगरी है काशी अविनाशी है। शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी मुक्ति—क्षेत्र है। जिसकी कही गति नहीं है उसकी काशी में गति है। काशी अशरण—शरण है। यहां प्राणी मृत्यु की दशा में सीधे स्वर्ग जाता है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के भाव में काशी

''मरणम् मंगलम् यत्र, विभूतिश्य विभूषणम्।

कौपीयं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते।।

अर्थात् जहां मृत्यु का प्राप्त होना शुभ माना जाता है। विभूति (भभूत) जहां लोगों का आभूषण है। लगोंटी जहां के लोगों के रेशमी वस्त्र के समान है। वह काशी नगरी भला किसके द्वारा भुलाई जा सकती है?

काशी शब्दों का विषय नहीं है काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी समस्त ज्ञान की प्रकाशिता है। सनातन धर्म संस्कृति के आदि शंकराचार्य ने काशी के महात्म्य का वर्णन अपने शब्दों में किया है।

''काश्यां हि काशयते काशी, काशी सर्वप्रकाशिता।

सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ताहि काशिका ।।

काशी में विश्वेश्वर की प्रेरणा से ही ढेर सारे समाज सुधारकों ने काशी की चिरन्तन शिक्षा परम्परा को गुरूता दी है। काशी वेद अध्ययन परम्परा को भी श्री कुमारिल भट्ट व महर्षि दयानन्द सरस्वती जैसे विचारकों ने इससे न केवल जनमानस को जोड़ा अपितु अपने ज्ञान और कौशल से समाज की जड़ता दूर करने का काम किया। काशी की आध्यात्मिक चेतना से जुड़कर ''महात्मा बुद्ध'' गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, संत कबीर दास, संत रामानन्द, पंडित मदन मोहन, मालवीय, जयशंकर प्रसाद, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मुंशी प्रेमचन्द्र, पण्डित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जी जैसे युग साधकों ने सत्य, न्याय अहिंसा के साथ–साथ तार्किक ज्ञान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा समाज को दी।

कहते हैं कि भगवान विश्वेश्वर को जब किसी से अनोखा कार्य कराना होता है तो वह अपनी शरण में लेकर उसे प्रेरणा देते हैं। आदि शंकराचार्य को केरल के कालणि से काशी बुलाया और अलौकिक ज्ञान देकर उन्हें सनातन धर्म संस्कृति को विश्वपटल पर जागरण हेतु प्रेरित किया। जगत गुरू शंकराचार्य को काशी में श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। वेदान्तों में सनातनी यहां तक मानते हैं कि भगवान विश्वेश्वर के ही स्वरूप आदि गुरू शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने काशी पहुंचकर सर्व प्रथम अन्नपूर्णा का दर्शन कर एक अनोखी भिक्षा मांगी।

''अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे।

ज्ञान–वैराग्य–सिद्धयर्थं भिक्षा देहि च पार्वति।।

अर्थात् अन्नपूर्णा के रूप में विराजान प्राण वल्लभा हे पार्वती आप मुझे वही भिक्षा दीजिये। जिससे मुझे ज्ञान वैराग्य

की सिद्धि प्राप्त हो। अन्नपूर्णा के इस प्रमाण मंत्र द्वारा उन्होंने ज्ञान वैराग्य की सिद्धि की भीख मांगी। भगवान विश्वेश्वर की प्रेरणा महारानी अहिल्या होल्कर को भी मिली जो अपने राज्य इन्दौर से ढाई सौ वर्ष पहले काशी आकर औरंगजेब की क्रूरता और विध्वंस का शिकार काशी विश्वनाथ मन्दिर का पुर्ननिर्माण की नींव रखी थी।

यह भी एक संयोग ही कहा जायेगा कि काशी विश्वेश्वर की प्रेरणा से ही मोदी और योगी का समाज सुधारक के रूप में काशी में प्राकट्य होना किसी अजूबे से कम नहीं। दिव्य और भव्य काशी के विकास की पटकथा वैसे तो 2014 में ही काशी के स्वर्णिम इतिहास में लिख दी गयी थी। जिसकी घोषणा काशी के सांसद बनकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। जो कार्य इतिहास में एक हजार वर्ष से नहीं हो पाया था। उसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया। काशी इन दिनों इतिहास के एक ऐसे ही अभूतपूर्व सृजन की साक्षी है। काशी श्री विश्वनाथ धाम दृढ़ संकल्प शक्ति व हिन्दू स्वभिमान की पुर्नस्थापना की अद्वितीय मिसाल है। काशी विश्वनाथ धाम के विकास में पंख तब लग गये। जब एक और कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के रूप में 2017 में उदय हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। काशी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संसदीय कर्मभूमि और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का। काशी उत्तर प्रदेश में है।

''जननी जन्म भूमिश्च, स्वर्गाऽदपि गरीयसी'' के रूप में दिखाता है। जब काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य और भव्य विकास की आधारशिला आठ मार्च 2019 को इसी भाव से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा नई काशी के रूप में रखी गयी थी। हर जीव में भगवान श्री विश्वेश्वर का दर्शन होता है। इसीलिये वे जीवत्व में शिवत्व सदैव विद्यमान का भाव रखते हैं चूंकि काशी का सम्पूर्ण क्षेत्र साक्षात भगवान श्री विश्वेश्वर का शरीर है।

''सर्वे क्षेत्रेशु भूपृष्ठे, काशी क्षेत्रम् चमें बपुः''

''ऐसी शास्त्रोक्ति है। तुलसी में काशी के लिये यही भाव है।

जहां रह सम्भु भवानि सो काशी सेई न कस''

ऋषियों का कथन है कि भगवान विश्वेश्वर के शरण में आने पर ''सम बुद्धि'' की प्राप्ति होती है।

''विश्वेश्वर शरणम् यायांम् समे बुद्धि प्रदास्यति'' यही शिवत्म का मंत्र मोदी जी व योगी जी के काशी सतत् विकास का मूल मंत्र है, जिसे काशी विश्वनाथ के रूप में **''ऋण मुक्ति''** की साधना का साधन बनाया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में ''मुगल शासकों की क्रूरता और विध्वंश के शिकार बाबा विश्वनाथ का वैभव काशी विश्वनाथ के धाम के रूप में लौटा। शताब्दियां

नतमस्तक हैं। धार्मिक आस्था प्रफुल्लित है। इतिहास का चक्र सौभाग्य स्वर्णिम महादशा में हैं शिव की दशा में उलझी मणिकर्णिका की गंगा को अपने आराध्य का गलियारा मिल गया है। आज उस अन्याय का प्रतिकार हुआ है। जो चार सौ साल पहले जो मंदिर औरंगजेब की क्रूरता का शिकार हो गया था। ढाई सौ साल पहले इन्दौर की महारानी अहिल्या बाई होल्कर ने जिस मंदिर के पुनरूद्धार के महान संकल्प की नींव रखी थी। आखिर किसने सोचा था कि आगे आने वाले समय पर प्रधानमंत्री उसी नींव पर करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का स्वर्ण महल खड़ा कर देंगे''।

आज जिस दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम की सृष्टि हुई है। यह प्रधानमंत्री मोदी के मन में पनपा विचार का परिणाम है। द्वादश ज्योर्तिलिंगों में शुमार काशी विश्वनाथ धाम का पुरातन वैभव इस आधुनिक नवनिर्माण के आलोक में और भी प्रकाशमान व गौरवशाली हो उठा है। महात्मा गांधी सबसे पहले 1902 में विश्वनाथ मन्दिर आये थे। उन्हें जो लगा वह एक टीस थी। जो 1916 में दूसरी बार आने पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में बोले। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बहुत पीड़ा से अपनी यात्रा और मन्दिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का लम्बा वर्णन किया है। गांधी दर्शन से प्रभावित प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल के अवसर उनके सपनों का काशी विश्वनाथ धाम व उसके आसपास के शिवालयों और मंदिरों का जीर्णोद्धार, बाबा विश्वनाथ को गंगा से जोड़ने और दुनिया के इस प्राचीन शहर के आनन्द कानन स्वरूप को पुर्नस्थापित करने का संकल्प लिया। जो पूरा हो गया है। इसके अन्तर्गत पांच मुख्य तीर्थ आते हैं दशाश्वमेघ, लोलार्ककुण्ड, बिन्दुमाधव, केशव, मणिकर्णिका इन्हीं से युक्त यह अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जहां मानव को जीवित और मृत्यु की दशा में मुक्ति गति प्राप्त होती है। अब काशी के घाट पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है। जबकि इन घाटों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। घाट टूट गये थे। एक घाट की दूसरे से कनेक्टविटी नहीं थी। घाटों के इतिहास को बताने वाला कोई नहीं था। आज सभी घाटों का सौन्दर्यीकरण हो चुका है। आगे चलकर आदि केशव घाट से विनायक तक प्लेट

फार्म निर्माण की योजना भी पूरी हो चुकी है। जिसे पंचकोष यात्रियों को असुविधा न हो, सभी घाटों का इतिहास प्रत्येक घाट के बोर्ड पर लिखा है। यही संकल्प बड़ी दिव्यता और भव्यता को साकर रूप दे रहा है।

काशी विश्वनाथ धाम के जरिये इस महान तीर्थ को उसकी एतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आभा के साथ मोक्षदायिनी गंगा को जोड़ने और जुड़ने वाले प्रधानमंत्री ही हैं। उन्होंने ही काशी विश्वनाथ धाम परिसर जो पहले पांच हजार वर्गफीट में नहीं था। उस परिसर का अब दायरा 5 लाख 27 हजार 730 वर्गफीट तक हो गया है।

गंगा का अविरल जल इस नगर को प्राकृतिक सौन्दर्य और जीवन्तता का मर्मस्पर्शी अनुभव कराता है यह बात हर व्यक्ति के मन में उमड़ती रहती है कि काशी तीन लोक से न्यारी शिव की नगरी है काशी अविनाशी है। शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी मुक्ति–क्षेत्र है। जिसकी कही गति नहीं है उसकी काशी में गति है। काशी अशरण–शरण है। यहां प्राणी मृत्यु की दशा में सीधे स्वर्ग जाता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य विकास में करके मानव दर्शन की नई परिभाषा सृजित की। इसी दृष्टि से पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक स्थापना के सम्बन्धों का सौंदर्य–बोध विकसित कर परियोजना के दायरे में आने वाले प्राचीन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया गया।

काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में मकराना, चुनार के लाल बलुआ पत्थर समेत सात विशेष पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में 2100 वर्ग फीट मन्दिर परिसर के दायरे को मुख्य मंन्दिर परिसर उन्तीस हजार वर्गफीट के विस्तार के अलावा दायरे में आये भोगशाला, यात्री सुविधा केन्द्र, आध्यात्मिक पुस्तकालय, मुमुक्षु भवन, वैदिक केन्द्र, मल्टीपरपज हाल, का निर्माण सिटी म्यूजियम और वाराणसी गैलरी, आदि का निर्माण भव्यता का दिग्दर्शन देश–विदेश के धार्मिक और पर्यटकों के लिये आस्था व आकर्षण का केन्द्र बने हैं। काशी के इस बदलाव में यह सावधानी रखी गयी कि न्यूनता में पौराणिकता के साथ कोई छेड़ छाड़ न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के विकास में एक नया अध्याय बाबा विश्वनाथ मन्दिर कॉरीडोर के साथ जोड़ा है। वैसे काशी विश्वनाथ मन्दिर के विकास का अन्तिम काम 1853 में हुआ था। जब महाराजा रणजीत सिंह ने मन्दिर के शिखर पर सोना मढ़वाया था। अब उसी बाबा विश्वनाथ मन्दिर को भव्यता प्रदान करने का कार्य हुआ है। यह कारीडोर काशी विश्वनाथ मन्दिर मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच पच्चीस हजार स्क्वायर मीटर में बना है जिसके तहत फूड स्ट्रीट, रिवर फ्रन्ट, बनारस के तंग गलियों का चौड़ीकरण भी है। मन्दिर से गंगा घाट तक 10 से 15 मी. चौड़ा स्थल पद का निर्माण कराया गया है।

काशी विकास के नित्य नये आयामों के चरमोत्कर्ष पर

है। यह धार्मिक नगरी अब धीरे–धीरे पूर्वान्चल का बिजनेस हब बन गयी है। पारम्परिक नगर के स्वरूप को बनाये रखते हुये आधार भूत संरचना में तेजी से बदलाव हुआ है। सड़क से लेकर ट्रीटमेन्ट प्लांट, कन्वेशन सेंटर से लेकर सिटी कमांड के जरिये ट्रैफिक संचालन व्यवस्था में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अंडरग्राउन्ड केबल से लेकर कार्गों सेन्टर तक नये स्वरूप में अवतरित है। काशी की साफसुथरी गलियाँ, चकाचक गंगा घाट वहां लगे हेरिटेज लाइट श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। दीवारों की पेंटिंग बाबा विश्वनाथ गलियारे निर्माण कार्य के बाद नये काशी के रूप में प्रगट हो रही है। नगर का कायाकल्प कुछ इस प्रकार से किया गया है कि, काशी की जरूरत और शोहरत दोनों में चार चांद लग गये हैं। अस्सी घाट तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केन्द्र बन गया है। जहां सुबह–सवेरे आस्था के स्वर लगने लगते हैं। **''काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर–हर महादेव शम्भों''।** सुबह का राग चारों तरफ गूंजता है और लोग इस राग में धीरे–धीरे डूब जाते हैं।

काशी विकास के नित्य नये आयामों के चरमोत्कर्ष पर है। यह धार्मिक नगरी अब धीरे–धीरे पूर्वांचल का बिजनेस हब बन गयी है। पारम्परिक नगर के स्वरूप को बनाये रखते हुये आधार भूत संरचना में तेजी से बदलाव हुआ है। सड़क से लेकर ट्रीटमेन्ट प्लांट, कन्वेशन सेंटर से लेकर सिटी कमांड के जरिये ट्रैफिक संचालन व्यवस्था में बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अंडरग्राउन्ड केबल से लेकर कार्गों सेन्टर तक नये स्वरूप में अवतरित है।

बाबतपुर वाराणसी हाइवे 17.6 किलो मीटर लम्बा है इस हाइवे को आज गेटवे ऑफ बनारस कहा जाता है। बनारस के किसी भी क्षेत्र से बाबतपुर हवाई अड्डे

तक पहुंचने का यह मार्ग ब्रांड बनारस की पहचान बन गया है। इस हाइवे के बनने से विदेशी मेहमानों की आवक पहले से कई गुना बढ़ गयी है। वहीं गंगा में जल परिवहन के जरिए बनारस से हल्दिया तक मालवाहक जहाज भेजने के लिये रामनगर में बने मल्टी मॉडल टर्मिनल का शुरू होना किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। स्वतंत्र भारत में यह इनलैंड वाटर परिवहन का पहला प्रोजेक्ट है। जिसका गौरव वाराणसी को मिला है। प्रधानमंत्री ने नवम्बर 2018 में जब इसका उद्घाटन किया तो उन्होंने कहा था, काशी नेचर कल्चर और एडवेंचर का संगम बनने जा रही है। काशी विश्वनाथ कोरिडोर के जरियें भारतीय अध्यात्म–संस्कृति से देश–दुनिया को भली भांति परिचित कराने के लिये नवीन रूप में कोरिडोर (विश्वनाथ धाम) अब हमारे सामने है। विश्वनाथ धाम में चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और वेदांग की झलक मिलती है। काशी की दीवारें संस्कृति की धरोहर से पर्यटकों को रू–ब–रू करा रही हैं भारत रत्न से लेकर काशी के कलाकार और महापुरूषों के चित्र दीवारों पर जीवन्त दिखते हैं। मैदागिन स्थित टाउन हाल न सिर्फ अपने पुराने स्वरूप में लौटा है। बल्कि वहां अब कई तरह के सांस्कृतिक आयोजन भी किये जा रहे हैं। हाल ही में मोदी फेस्ट आयोजित किया गया था। जिसके जरिए वाराणसी के लोग अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री से सीधे जुड़े। अमृत के तहत शहर में करोड़ों रूपये से जहाँ जल शिविर का कार्य कराया गया है। वहीं नगर निगम द्वारा सात पार्कों का सुन्दरीकरण भी कराया गया है स्मार्ट सिटी प्रोटेक्ट के तहत पांच पार्कों को थीम के आधार पर विकसित हुये हैं। सेल्फी थीम पर शास्त्री नगर पार्क, गुलाबबाड़ी के तर्ज पर गुलाबबाग पार्क और सौर ऊर्जा पर आधारित मच्छोदरी पार्क और शेड एण्ड लाइट शो की थीम पर रवीन्द्रपुरी पार्क का विकास किया गया है। वाराणसी में 30 एकड़ भूमि में फूड पार्क में बनारस डेरी संकुल का निर्माण चार सौ पच्हत्तर करोड़ की लागत से बना है इस डेरी में पांच लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत होता है। जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ किसानों को 1.7 लाख दुग्ध उत्पादकों के लिये लाभ के नये अवसर सृजित हुये है। पण्डित मदनमोहन मालवीय कैंसर सेन्टर में एक सौ तीस करोड़ की लागत से डाक्टर, नर्स, छात्रावास व आश्रयगृह से सम्बन्धित परियोजना पूर्ण होने की कगार में है।

वाराणसी को जाम से निजात देने के लिये गोदौलिया और मैदगिन की आधुनिक पार्क के बाद अब बेनिया बाग में 90.42 करोड़ की लागत से पार्क व अन्डर ग्राउन्ड पार्किंग स्थल का निर्माण हुआ है। सोलह हजार पांच सौ वर्ग मीटर में बेनिया बाग भूमिगत पार्किंग में चार सौ सत्तर चार पहिया तथा एक सौ बीस दो पहिया वाहन की क्षमता है। यह पार्क जिले में सेन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित हुआ है। जो मोदी और योगी का बनारस के लिये सौगात साबित हुई है। काशी

धाम का यह स्थल सदैव भीड़ भाड़ वाले इलाके में होने की वजह से सुबह तक जाम का अंजाम लोगों को भोगना पड़ रहा था। उससे बनारस के लोगों को निजात मिली है।

अब तो काशी का बहुआयामी विकास अपने चरमोत्कर्ष पर है जो कल्पना से परे था वही आज काशी में सच है 24 मार्च, 2023 को काशी में गंगा के समानान्तर गंगा बही, किन्तु ये गंगा माँ गंगाजी के अलावा विकास की गंगा थी। इसका उद्गम डॉ. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रांगण था और साक्षी बन रहे थे। देश दुनिया के वे लोग, जिन्हें काशी और भारतीय संस्कृति से विशेष लगाव है, जहाँ भगीरथ की भूमिका में थे विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मौका था 28 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास का। जो 1780 करोड़ की लागत से धरातल पर आकार ले रही थी देश के पहले ट्रांसपोर्ट रोप वे की सुविधा को काशी ने नजीर बनते देखा।

काशी के पुरातन और नूतन स्वरूपों के दिव्य एवं भव्य दर्शन की उपलब्धता के पीछे मोदी व योगी जी की उदारता की परिणति है जो विगत 9 वर्षों में काशी विकास यात्रा में अब तक 35 हजार करोड़ की लागत का अनुमान है विकास के रास्ते धन के आभाव में कभी बंद नहीं होंगे यह सब कुछ काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से हैं हम तो केवल माध्यम हैं। सात करोड़ से अधिक पर्यटकों की साल भर में काशी में आमद, वैश्विक सनातन संस्कृति की जिज्ञासा मंजूषा की प्रत्याशा का यह मणिकांचन संयोग ही कहा जायेगा।

काशी के लोगों के लिये एक और सौभाग्य की बात यह रही कि 100 वर्षों के बाद माता अन्नपूर्णा की अपने घर वापसी हुई है, माता के अभाव में काशी विश्वनाथ अनाथ जैसे लगने लगे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्थक प्रयास से मां अन्नपूर्णा और काशी निहाल हुई, जब विदेश से भारत वापस आयी माता अन्नपूर्णा 15 नवम्बर, 2021 को पुनः अपने ही प्राचीन घर पर प्राण प्रतिष्ठित हो गयी। बाबा विश्वनाथ की कृपा से माता भी वापस आयीं और दिव्य और भव्य काशी का 13 दिसम्बर, 2021 को लोकार्पण करके बाबा विश्वनाथ और काशी के लोगों के ऋण को उतारने का प्रयास भी सार्थक हुआ। आज भी मोदी और योगी जी काशी और अयोध्या के अलौकिक विकास का जो सपना देखते हैं इसीलिये काशी में विकास की गंगा निरंतर अपने वेग पर बह रही है। काशी विश्वनाथ पृथ्वी पर साक्षात् स्वर्ग हैं, और स्वर्ग के अनुरूप वह विकसित भी हो रही है। काशी विश्वनाथ धाम के बहाने काशी में इतिहास की एक ऐसी स्वर्ण मंजूषा निर्मित हुई है जो शताब्दियों तक अपनी ऊर्जा से धर्म संस्कृति के इस धाम को सदैव रोशन करती रहेगी। ■

मो. : 9450403222

सब जग होरी, ब्रज में होरा

सवा महीने तक चलती है ब्रज मंडल की विश्व प्रसिद्ध ब्रज के रंगों में सराबोर होने एक बार अवश्य आइए, निश्चित ही इस अनुभव को जीवन भर भूलना मुश्किल होगा।

–डॉ. अतुल कुमार सिंह

ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली करीब सवा महीने तक चलती है। जितनी तरह से ब्रज में होली मनाई जाती है, उतने प्रकार से विश्व में कहीं नहीं मनाई जाती। यहां रंगों की होली, गुलाल की होली, लट्ठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, हुरंगा, होलिका दहन, कीचड़ की होली, धुलेंडी पर दही और हल्दी की होली, मंदिरों में फाग और समाज गायन, फालैन में होली से पंडा का गुजरना सहित दर्जन भर तरीकों से होली मनाई जाती है। ब्रज में खासतौर से वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, दाऊजी की होली देखने लोग आते हैं।

ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। पूरे ब्रजमंडल में होली करीब सवा महीने तक चलती है। वसंत पंचमी से शुरू होने के साथ ही धुलेंडी तक ब्रज में अलग–अलग तरह से होली मनाई जाती है। बेहद आश्चर्यजनक है कि होली का रंग–बिरंगा त्योहार जिस तरह से 84 कोस में बसे पूरे ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, उतने प्रकार से विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता। फिलहाल पूरे ब्रज में होली का हुड़दंग देखने लायक होता है। यहां रंगों की होली, गुलाल की होली, लट्ठमार होली, लड्डू होली, फूलों की होली, हुरंगा, होलिका दहन, कीचड़ की होली, धुलेंडी पर वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर में दही और हल्दी की होली, मंदिरों में फाग और समाज गायन, फालैन में होली से पंडा का गुजरना सहित दर्जन भर तरीकों से होली मनाई जाती है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रावल, बाद ग्राम, मथुरा, दाऊजी सहित सभी जगहों के मंदिरों में होली की धूम रहती है।

ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। पूरे ब्रजमंडल में होली करीब सवा महीने तक चलती है। वसंत पंचमी से शुरू होने के साथ ही धुलेंडी तक ब्रज में अलग–अलग तरह से होली मनाई जाती है। बेहद आश्चर्यजनक है कि होली का रंग–बिरंगा त्योहार जिस तरह से 84 कोस में बसे पूरे ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है, उतने प्रकार से विश्व में कहीं नहीं मनाया जाता। फिलहाल पूरे ब्रज में होली का हुड़दंग देखने लायक होता है।

ब्रज के मंदिरों में प्रिया–प्रियतम यानि राधा–कृष्ण तो होली खेलते ही हैं, इस रंग और गुलाल में भक्त भी सराबोर होकर आते हैं। खासतौर पर बरसाना, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव और दाऊजी के मंदिरों में अलग–अलग दिनों में होली धूमधाम से मनाई जाती है। यहां टेसू और गुलाब के फूलों से बने रंगों की फुहार भक्तों को भिगोती रहती हैं। फुलेरा दौज से फूलों की होली का आयोजन ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में हो जाता है। बरसाना और वृंदावन में खासतौर पर मंदिरों में फूलों की होली खेली जाती है। बरसाना के राधारानी में मंदिर में फुलेरा दूज के दिन पूरे दिन फूलों की होली होती है। राधा–कृष्ण को फूलों से होली खिलाने के साथ ही मंदिरों के सेवायत आने वाले भक्तों पर फूल बरसाते हैं।

बरसाना की लड्डू होली जग प्रसिद्ध है। लट्ठमार होली से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन टनों लड्डू राधारानी मंदिर के परिसर में लुटाए जाते हैं। इस बार 27 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली मनाई गई। बरसाना की लट्ठमार होली इस बार 28 फरवरी को धूमधाम से मनाई गई। इस दिन बरसाना की गोपियां नंदगांव के हुरियारों पर प्रेम में पगे लठ्ठ बरसाए। नंदगांव से बरसाना आकर हुरियारे फाग गाते हैं और रंग फेंकते हैं। बरसाना की लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है, इसे देखने देश–विदेश से लोग आते हैं। इसी प्रकार की लठामार होली नंदगांव में भी होती है, हालांकि वह बरसाना के एक दिन बाद होती है। इस बार नंदगांव में 1 मार्च को लठामार होली खेली गई।

वैसे तो वसंत पंचमी से ही लेकिन वृंदावन में रंग भरनी एकादशी से होली का विशेष शुभारंभ हो जाता है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा देने के लिए भक्त आते हैं और पूरी परिक्रमा में रंग और गुलाल उड़ता है। शाम को हाथी की सवारी निकलती है और गुलाल से पूरा वृंदावन नहा उठता

है। वहीं सभी मंदिरों में भी रंग और गुलाल भर–भर कर उड़ने लगता है। रंगभरनी एकादशी इस बार 3 मार्च को मनाई गई। रंगभरनी एकादशी में सभी लोगों को एक बार वृंदावन में होली मनाने जरूर जाना चाहिए। द्वादशी को गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है। इस बार 4 मार्च को गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन हुआ। इस दिन गोकुल के कान्हा रूपी लोग इकट्ठे होकर खेलते हैं और गोकुल की महिलाएं छड़ी से मारती हैं। होली का यह रूप भी काफी प्रसिद्ध है. इसे देखने भी बाहर से लोग पहुंचते हैं।

पूरे ब्रज में होलिका दहन को विधि–विधान से मनाया जाता है। इस बार 6 मार्च को होलिका दहन हुआ। पूरे ब्रज क्षेत्र में हर गांव, कस्बे और शहर के चौराहों पर लकड़ियों, घास, फूस, गाय के गोबर से बने उपलों, गूलरी आदि की होली रखी जाती है। सुबह घरों से महिलाएं नए–नए कपड़े पहनकर होली पूजन करने जाती हैं। उसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जाता है। सभी लोग अपने–अपने घरों में रखी होली के लिए यहीं से आग लेकर जाते हैं और घरों में जौ और गेहूं की बालों को भूनते हैं। एक दूसरे के घर जाते हैं और गले लगते हैं। होलिका दहन वाले दिन ब्रज के फालैन में बड़ा मेला लगता है। यहां रात को होलिका दहन के बाद पहले से पूजा–अर्चना पर बैठा पंडा होली की धधकती आग के बीचों–बीच से नंगे पांव निकलता है। इस दृश्य को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यह परंपरा कई सालों से यहां निभाई जा रही है। देश–विदेश से लोग फालैन के इस प्रह्लाद को देखने के लिए जाते हैं। इस बार 6 मार्च को रात में होलिका दहन के तुरंत बाद पंडा आग से निकाला गया।

होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी होती है। इस दिन पूरे ब्रज में सभी ब्रजवासी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। सभी मंदिरों में होली होती रहती है। इस बार 7 मार्च को धुलेंडी मनाई गई। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी इसी दिन होली का विशेष आयोजन होता है। खास बात है कि इस दिन वृंदावन में परंपरा है कि दोपहर 2 बजे तक ही होली होती है। उसके बाद लोग नए–नए कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। कोई भी उन पर रंग या गुलाल नहीं डालता है। इस परंपरा का आज भी सख्ती से पालन होता है। धुलेंडी के अगले दिन बल्देव दाऊजी मंदिर में हुरंगा मनाया जाता है। हुरंगा के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। 8 मार्च को इस बार दाऊजी में हुरंगा हुआ। इस दिन दाऊजी मंदिर प्रांगण में बल्देव की महिलाएं लाठियां लेकर और लहंगे–चूनर पहनकर इकठ्ठा होती हैं। वहीं आसपास के हुरियारे होली खेलने आते हैं और फाग गाते हैं। इस तरह कई घंटे तक यह आश्चर्यजनक हुरंगा खेल वहां चलता रहता है। दाऊजी का हुरंगा भी जग प्रसिद्ध है।

धुलेंडी के अगले दिन बल्देव दाऊजी मंदिर में हुरंगा मनाया जाता है। 8 मार्च को इस बार दाऊजी में हुरंगा मनाया गया। इस दिन दाऊजी मंदिर प्रांगण में बल्देव की महिलाएं लाठियां लेकर और लहंगे–चूनर पहनकर इकठ्ठा होती हैं। वहीं, आस–पास के हुरियारे होली खेलने आते हैं और फाग गाते हैं। इस तरह कई घंटे तक यह आश्चर्यजनक हुरंगा खेल चलता रहता है। दाऊजी का हुरंगा भी जग प्रसिद्ध है। रंग, गुलाल और फूल ही नहीं ब्रज के गांवों में गोबर से भी होली खेली जाती है। ब्रज के कई गांवों में लोग गोबर को पानी में मिलाकर बाल्टियों में भरकर एक–दूसरे पर डालती हैं। कई जगहों पर कीचड़ से भी होली खेली जाती है, हालांकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है लोग सिर्फ आनंद के लिए ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि जिसने जीवन में एक बार ब्रज की होली नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए जीवन में एक बार जरूर ब्रज के रंगों में सराबोर होने आइए, निश्चित ही इस अनुभव को जीवन भर भूलना मुश्किल होगा। ■

(लेखक, स्वदेश हिंदी दैनिक के स्थानीय संपादक हैं।)
मो. : 9451907315

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से

₹35 लाख करोड़+ के एम.ओ.यू.

1 करोड़+ रोज़गार के अवसर

असीमित अवसरों का प्रदेश

सुरक्षित निवेश

बढ़ चला उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

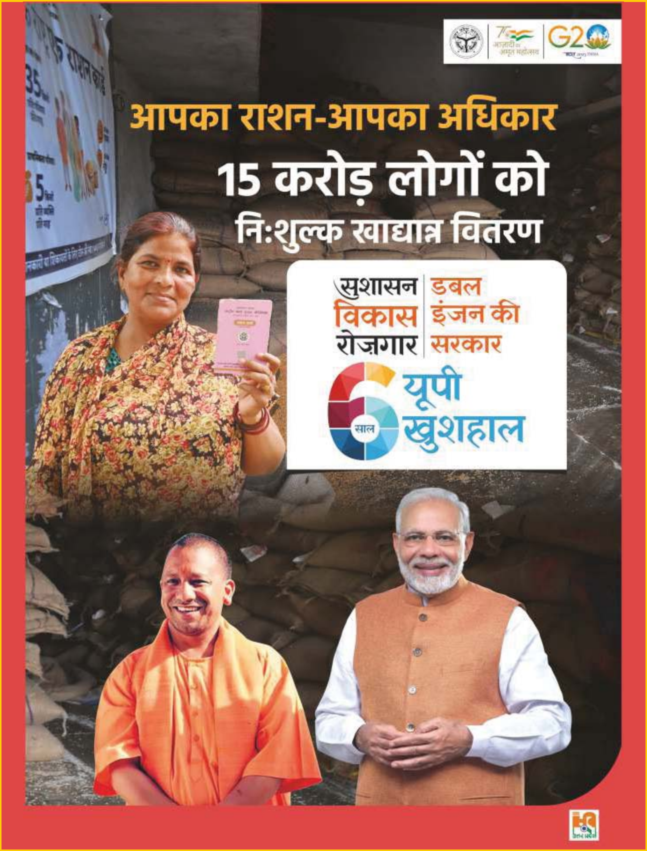

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. स्वत्वाधिकारी के लिए शिशिर, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश एन. भार्गव, प्रकाश पैकेजर्स, लखनऊ द्वारा मुद्रित, सम्पादक– **कुमकुम शर्मा**